₹ 20

www.kewalsach.com

निर्भीकता हमारी पहचान

दिसम्बर 2023

केवल सच

हिन्दी मासिक पत्रिका

RNI NO.- BIHHIN/2006/18181, DAVP NO.-129888, POSTAL REG. NO. :- PT-35

माया मिली न राम... !

WESTERLIN DRUGS PVT. LTD.
(Serving nation since 1990)

WESTOCITRON
WESTOCLAV
WESTOFERON
WESTOPLEX
QNEMIC

AOJ
AZIWEST
DAULER
MUCULENT
AOJ-D
BESTARYL-M
GAS-40
MUCULENT-D

SEVIPROT
WESTOMOL
WESTO ENZYME
ZEBRIL

WESTERLIN DRUGS PVT. LTD.
WD
Dispersing Happiness

WESTERLIN DRUGS PVT. LTD.
Industrial area, Fatuha-803201
E-mail- westerlindrugsprivatelimited@gmail.com
Phone No.:0162-3500233/2950008

जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएँ

मेधा पाटकर
01 दिसम्बर 1954

बोमन इरानी
02 दिसम्बर 1959

जावेद जाफरी
04 दिसम्बर 1963

प्रकाश सिंह बादल
08 दिसम्बर 1927

सोनिया गांधी
09 दिसम्बर 1946

शत्रुघ्न सिन्हा
09 दिसम्बर 1945

स्व० प्रणव मुखर्जी
11 दिसम्बर 1935

विश्वनाथन आनंद
11 दिसम्बर 1969

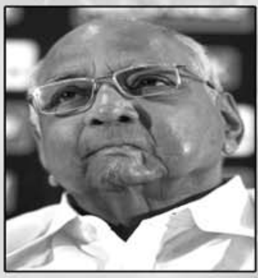

शरद पवार
12 दिसम्बर 1940

रजनीकान्त
12 दिसम्बर 1950

युवराज सिंह
12 दिसम्बर 1981

जॉन अब्राहम
17 दिसम्बर 1972

प्रतिभा देवी पाटिल
19 दिसम्बर 1934

गोविन्दा
21 दिसम्बर 1963

अनिल कपूर
24 दिसम्बर 1959

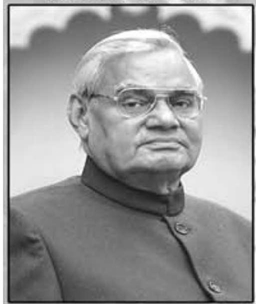

स्व० अटल बिहारी बाजपेयी
25 दिसम्बर 1924

स्व० राजू श्रीवास्तव
25 दिसम्बर 1963

सलमान खान
27 दिसम्बर 1965

स्व० अरूण जेटली
28 दिसम्बर 1952

रतन टाटा
28 दिसम्बर 1937

निर्भीकता हमारी पहचान

www.kewalsach.com

केवल सच

हिन्दी मासिक पत्रिका

Regd. Office :-
East Ashok, Nagar, House No.-28/14, Road No.-14, kankarbagh, Patna- 8000 20 (Bihar) Mob.-09431073769
E-mail :- kewalsach@gmail.com

Corporate Office:-
Vaishnavi Enclave, Second Floor, Flat No. 2B, Near-firing range, Bariatu Road, Ranchi- 834001
E-mail :- editor.kstimes@rediffmail.com

Delhi Office :-
Sanjay Kumar Sinha, A-68, 1st Floor, Nageshwar Talla Shastri Nagar, New Delhi - 110052
Mob.- 09868700991, 09955077308
E-mail:- kewalsach_times@rediffmail.com

Kolkata Office :-
Ajeet Kumar Dube, 131 Chitranjan Avenue, Near- md. Ali Park, Kolkata- 700073 (West Bengal)
Mob.- 09433567880 09339740757

ADVERTISEMENT RATES PER ISSUE

COLOUR

AREA	FULL PAGE	HALF PAGE	Qr. PAGE
Cover Page	5,00,000/-	N/A	N/A
Back Page	1,60,000/-	N/A	N/A
Back Inside	1, 00000/-	60,000/-	35000
Back Inner	90,000/-	50,000/-	30000
Middle	1,50,000/-	N/A	N/A
Front Inside	1, 00000/-	60,000/-	40000
Front Inner	90,000/-	50,000/-	30000

B & W

AREA	FULL PAGE	HALF PAGE
Inner Page	60,000/-	35,000/-

1. एक साल के नियमित विज्ञापन पर पत्रिका के वेवसाइट **www.kewalsach.com** के फ्रंट पर भी विज्ञापन निःशुल्क तथा आपका वेवसाइट से सीधा लिंक हो सकता है।
2. एक साल के नियमित विज्ञापन पर 10 प्रतिशत की रियायत।
3. आपके प्रोडक्ट या संगठन के प्रचार-प्रसार हेतु आलेख को उचित स्थान।
4. पत्रिका द्वारा सामाजिक कार्य में आपके संगठन/प्रोडक्ट का बैनर/फ्लैक्स को उचित स्थान देकर आपके संगठन का व्यापक प्रचार-प्रसार।
5. विज्ञापन का भुगतान चेक या आर.टी.जी.एस. से ही मान्य होगा।

महाप्रबंधक (विज्ञापन)

श्रीराम

मंदिर का उद्घाटन और 2024 का चुनाव

अपनी प्रतिक्रिया हमारे ई-मेल पर दें:- editor.kstimes@rediffmail.com

मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 के प्रचंड जीत के बाद भाजपा लोकसभा चुनाव 2024 में भगवान श्रीराम के भरोसे 400 का आंकड़ा पार की पारी खेलने में जुट चुकी है। एक तरफ तीन बड़ों राज्यों में सरकार और 22 जवरी 2024 को त्रेतायुग के प्रभु श्रीराम के भव्य मंदिर अयोध्या का उद्घाटन भारत देश के सनातन प्रेमी वोटर का मिजाज बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के बाद भी बदल देगा का माहौल सज चुका है। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, विश्व हिन्दू परिषद् एवं बजरंग दल और शिवसेना सहित हिन्दूवादी संगठनों का वर्षो संघर्ष का फल मिलने वाला है और प्रभु श्रीराम मस्जिद से मुक्त होकर तंबू में और अब भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। त्रेतायुग के प्रभु श्रीराम की जन्मभूमि पर विराजमान होने के बाद द्वापरयुग के विष्णु के अवतार भगवान श्रीकृष्ण की जन्मभूमि मथुरा का वातावरण भी बदला - बदला हुआ दिखने लगा है और हिन्दुओं को लगने लगा है की ''**मोदी है मुमकिन है**'' अन्यथा भारत को दोगली राजनीति को महत्व देने वाले राजनेताओं ने हिन्दुओं की लाश पर राजनीति की है का आरोप सदैव लगता रहा है। विधानसभा की जीत के साथ - साथ जम्मू-कश्मीर का धारा- 370 के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी मोदी की सरकार के पक्ष में आया है जिसकी वजह से 2024 के लोकसभा चुनाव में 400 का आंकड़ा पार करने की जुगाड़ के अंकगणित में गृहमंत्री अमित शाह चाल चल चुके हैं और दूसरी ओर इंडिया गठबंधन मजबूती से बंधन बांध पायेगा उसी में लगे हैं।

सौगंध राम की खाते हैं, हम मंदिर वहीं बनायेंगे'', यह नारा को भारतीय राजनीति में तीन दशक से पक्ष-विपक्ष ने इसको ऐसे वजूद में रखा जैसे अपनी नीजि संपत्ति को रखते हैं लेकिन आखिरकार इसका सर्वाधिक लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिला और 02 सीट वाली बीजेपी 303 पर पहुंच गयी और अब हालात ऐसे हैं कि उसको सत्ता से बेदखल करने के लिए कांग्रेस को अपने घोर विरोधियों से हाथ मिलाना पड़ रहा है। 22 जनवरी, 2024 को प्रभु श्रीराम तंबू से भव्य मंदिर में विराजमान होंगे की सूचना मात्र से ही देश-विदेश में रह रहे सनातन प्रेमियों में सकरात्मक शक्ति का एहसास हो रहा है। ''**अटल-आडवाणी केसरिया बाना, भारत को हिन्दूराष्ट्र बनाना**'' का नारा 56 इंच वाले भारत देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र दामोदर दास मोदी ने हकीकत में तब्दील कर दिया है। लंबे खूनी एवं राजनीतिक संघर्ष के बाद सुप्रीम कोर्ट ने **09 नवंबर 2019 को 05 जजों के बेंच** ने राम मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाया और महज चार साल में अयोध्या में भव्य मंदिर का निर्माण हो गया और **22 जनवरी 2024** को मंदिर में प्रभु श्रीराम विराजमान होंगे। भाजपा के साथ-साथ साधु-संत, कथावाचक, हिन्दूवादी संगठन और प्रभु श्रीराम के भक्तों में एक अलग एहसास हो रहा है और उद्घाटन की उक्त तिथि को अयोध्या में करोड़ों श्रद्धालु पहुंच कर इस एतिहासिक क्षण के साक्षी बनेंगे। 2014 में केन्द्र की सत्ता में आई भाजपा का प्रचंड बहुमत 2019 में 300 का आंकड़ा पार कर गया इसके बाद देश के भीतर विपक्ष इस प्रकार राजनीतिक दृष्टिकोण से विखंडित हो गया कि 2024 के लोकसभा चुनाव में यूपीए की जगह अब इंडिया नाम से महागठबंधन बन गया लेकिन 2023 के अंत में हुए 5 राज्यों के विधानसभा में भाजपा ने कांग्रेस से राजस्थान एवं छत्तीसगढ़ की सरकार को छीन लिया और तीनों बड़े राज्यों में सनातन धर्म का पताका को फहराया जिससे विपक्षी गठबंधनों में निराश का माहौल बन चुका है। विपक्ष भले ही महंगाई, बेरोजगारी और अडाणी-अंबानी की मोदी से दोस्ती और हिन्दूवादी विचारधारा के माध्यम से वोटर का मिजाज अपने पक्ष में करना चाहते हैं लेकिन जहां भाजपा के पास अमित शाह जैसे रणनीतिकार और योगी आदित्यनाथ जैसे स्टार प्रचारक हो तो कहीं भी किला फतह की गुंजाईश बन मोदी के लिए बन जाती है। 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी की सरकार की वापसी में श्रीराम मंदिर के निर्माण का उद्घाटन का बहुत बड़ा रौल साबित होने वाला है इससे विपक्ष भी इंकार नहीं करेगा क्योंकि जो कल तक हिन्दू वोटर से दूर भागता था वह राजनीतिक दल के सूरमा भी तिलक लगाकर और जनेउ पहनकर फोटो भी आवाम के बीच डालकर हिन्दू होने के दावा कर रहे हैं लेकिन उनका गठबंधन कभी कुछ और कूटनीति करते हैं तो कभी खुद ही **पीएम मेटेरियल** बन जाते हैं जिसका लाभ भाजपा को मिल सकता है। 3 दिसंबर 2023 को 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे जहां भाजपा को बुलंदी पर पहुंचा दिया वहीं विपक्ष की चिंता बढ़ा दी है और तो और धारा-370 हटाने के सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया है इसके बाद तो वोटर के बीच भी भाजपा के प्रति और विश्वास बढ़ा है। ''**अयोध्या तो सिर्फ झांकी है अभी मथुरा - काशी बाकी है**'' का शोर फिर से लोकसभा चुनाव 2024 में गूंजने लगेगा। इस चुनाव में देश के भीतर सनातन धर्म का डंका बजेगा और हिन्दू-मुस्लिम वोट का बंटवारा होना निश्चित है। उत्तरप्रदेश, उत्तराखंड, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, दिल्ली, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, असम और उड़ीसा राज्य में जय श्रीराम - जय श्रीराम का मंदिर निर्माण की चर्चा से 2024 के लोकसभा चुनाव में होना तय है और वहां का वोटर में इस जयघोष का असर होता स्पष्ट तौर पर दिखता है और तीनों राज्यों के मुख्यमंत्री बनाये जाने से कार्यर्त्ताओं में भी जोश है जिसकी वजह से भाजपा के भीतर एक अलग माहौल बना है तथा आदिवासी समाज को राष्ट्रपति बनाना और मुख्यमंत्री बनाकर अपना वोट बैंक पर भी अपना कब्जा जमाया है। जहां एक तरफ भाजपा मजबूत होती जा रही है वहीं कांग्रेस गठबंधन की राजनीति की वजह से कमजोर होती जा रही है क्योंकि कांग्रेस के साथ खड़े राजनीतिक दल भी कांग्रेस के कमजोर होने का लाभ उठाकर कम सीट पर लड़ने के लिए बाध्य करती है। सनातन धर्म का इंग्नोर करना विपक्ष के लिए महंगा साबित होगा और भारत की विदेश नीति का लोहा अन्य दलों के राजनेता एवं कार्यकर्त्ता भी स्वीकार करते हैं वैसे में भाजपा मजबूत है उससे ज्यादा विपक्ष कमजोर है जिसका लाभ मोदी सरकार को मिल रहा है। 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर निर्माण के उद्घाटन के बाद लोकसभा के चुनाव में भाजपा के सभी सभाओं एवं रैलिओं में **जय श्री राम** का जयघोष सुनाई देगा और मथुरा में भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा भी गरमा जायेगा। अभी देश का मूड सनातन धर्म के पक्ष में है और मोदी के अलावा दूसरा चेहरा को प्राथमिकता नहीं देना चाहता है चाहे बेराजगारी बढ़े या फिर महंगाई।

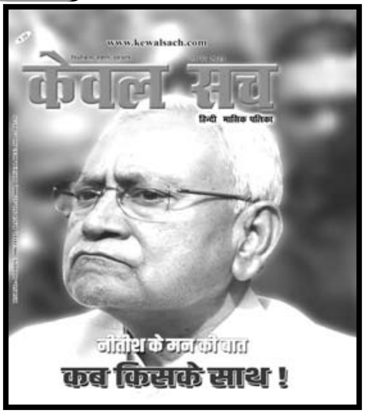

नवंबर 2023

आपको केवल सच पत्रिका कैसी लगी तथा इसमें कौन-कौन सी खामियाँ हैं, अपने सुझाव के साथ हमारा मार्गदर्शन करें। आपका पत्र ही हमारा बल है। हम आपके सलाह को संजीवनी बूटी समझेंगे।

केवल सच

राष्ट्रीय हिन्दी मासिक पत्रिका

हमारा पता है :-

द्वारा:- ब्रजेश मिश्र

पूर्वी अशोक नगर, रोड़ नं.- 14, मकान संख्या- 14/28
कंकड़बाग, पटना-800020 (बिहार)
फोन:- 9431073769/ 8340360961/ 9955077308

हमारा ई-मेल

kewalsach@gmail.com, editor.kstimes@rediffmail.com
kewalsach_times@rediffmail.com

एक पर एक

संपादक जी,

नवंबर 2023 अंक का कई खबर पाठकों का ध्यान बरबस अपनी ओर आकर्षित करता है. संजय सिन्हा की ''सेक्सगुरु नीतीश कुमार'' की खबर एवं संपादकीय ''नीतीश की सियासी बयान या फिसली जुबान'' भी बेजोड़ है। डी एन शुक्ला की खबर ''पश्चमी चंपारण की बेटियों ने बीपीएससी में लहराया परचम'' सही बात को पाठक के बीच रखा है। धर्मेंद्र सिंह की खबर ''हाइवे बना मुसीबत, एमपी एमएलए के पास भी हल नहीं सटीक खबर है।

✦ संजय पटवा, मानपुर बाजार, गया (बिहार)

मन की बात

ब्रजेश जी,

नवंबर 2023 अंक में अमित कुमार की खबर 'नीतीश के मन की बात, कब किसके साथ' में बिहार की राजनीति के साथ-साथ नीतीश कुमार की दिल में भाजपा की क्या जगह है, समय-समय पर उनकी जुबां से झलक जाती है। सरकार के मुखिया का पद पर लगातार बने रहने की लालच की वजह से नीतीश कुमार कभी भाजपा तो कभी महागठबंधन के पक्ष में ऐसा बयान देते हैं जिससे दोनों दल चिंतित रहता है की अगला पल क्या हो जाए। मुझे यह खबर काफी सटीक लगा।

✦रणधीर राय, छोटी बदलपुरा, खगौल, पटना

सत्य की जीत

मिश्रा जी,

केवल सच पत्रिका की बेबाक एवं निष्पक्ष खबरों की वजह से इसकी अलग ही पहचान है। नवंबर 2023 अंक में पत्रकार अरविंद मिश्रा ने अपनी खबर 'सत्य की जीत हुई, निर्दोष साबित हुए पूर्व कारा अधीक्षक अभिषेक पांडे में पूरी घटना की जानकारी विस्तार पूर्वक पाठकों के समक्ष प्रस्तुत किया है जो काबिले तारीफ है। कैदी गुड्डू कुमार की मौत के मामले में फसाने की साजिश करने वाले शायद भूल गए कि जीत सदैव सत्य की ही होती है और पूरे मामले पर पहले भी खबर लिखकर सरकार तथा विभाग को भी सजग किया था। यह अंक भी बेजोड़ और पठनीय है।

✦ रेश्मी चटर्जी, बाबू बाजार, कोलकात्ता, प.बं.

फिसली जुबान

मिश्रा जी,

बिहार विधानसभा में सेक्स एडुकेशन पर जिस प्रकार हांथ का ईशारा करते हुए अंदर-बाहर का बयान दिया उसपर बहुत ही मार्मिक संपादकीय **''नीतीश की सियासी प्लान या फिसली जुबान''** नवम्बर 2023 अंक में बहुत ही भावनात्मक दृष्टिकोण से नीतीश कुमार की इस हरकत को सभी प्रकार के एंगल से लिखा है जो पठनीय है। श्री कुमार कब किस प्रकार का राजनीति के दोयम दर्जे के बयान देंगे के विषय पर पर निर्भीक होकर खबर लिखने की क्षमता के लिए साधुवाद। नीतीश कुमार के बयान का गंध बिहार के साथ-साथ देशभर में फैल रहा है।

✦ आशीष सक्सेना, टाटी सिलवे, राँची, झा०

एक मुहिम

संपादक जी,

बिहार का रहने वाला हूं और बनारस में प्रतियोगी परीक्षा का तैयारी के लिए रहता हूं। नवंबर 2023 अंक में राजीव शुक्ला एवं शशि रंजन सिंह की राज्य सवास्थ्य समिति वाली खबर को पढ़कर बहुत सटीक जानकारी हुई कि किस प्रकार एम्बुलेंस को लेकर विभाग, समिति और मंत्रालय के बीच बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार व्याप्त है। पहले भी सोसायटी की खबर को पढ़ा हूं केवल सच में जिसमें उर्मीला का आतंक पर विस्तार से लिखा गया था। उर्मीला की खबर क्यों बंद कर दिया सर, इसमें बहुत भ्रष्टाचार है और आपकी पत्रिका ने विस्तार से छापा था।

✦ दीपक पाण्डेय, पाण्डेपुर-आजमगढ़ मार्ग, बनारस

खेवनहार

संपादक जी,

राजनीतिक समीक्षा आपकी पत्रिका केवल सच पूर्ण बेबाकी से करती है। नवम्बर 2023 अंक में जहानाबाद संसदीय क्षेत्र का 2024 में कौन खेवनहार होगा पर विकाश कुमार एवं सतोष कुमार मिश्रा ने सटीक जानकारी दी है। राजनीति एवं भ्रष्टाचार की कई खबरें केवल सच पत्रिका की साख को मजबूत करती है। जमुई जिलाधिकारी का साक्षात्कार भी बहुत बढ़िया है। झारखंड एवं उत्तरप्रदेश की राजनीतिक खबरों का आभाव स्पष्ट तौर दिखता है। प्रतियोगी परीक्षा के लिए भी सामग्री प्रत्येक महीने दिया जाना चाहिए।

✦ मनोरंजन सिंह, अरवल मोड़, जहानाबाद

अन्दर के पन्नों में

22 हजार बी.एड धारक शिक्षकों पर....23

बालू माफियाओं द्वारा जानलेवा हमला...57

सरकार-प्रशासन के उपेक्षा का शिकार...82

RNI No.- BIHHIN/2006/18181, DAVP No.- 129888

समृद्ध भारत खुशहाल भारत

निर्भीकता हमारी पहचान

केवल सच

राष्ट्रीय हिन्दी मासिक पत्रिका

वर्ष:- 18,	अंक:- 211,	माह:- दिसंबर 2023,	मूल्य:- 20/- रू

फाउंडर

स्व० गोपाल मिश्र

संपादक

ब्रजेश मिश्र

9431073769 8340360961

editor.kstimes@rediffmail.com

kewalsach@gmail.com

प्रधान संपादक

अरूण कुमार बंका	7782053204
सुरजीत तिवारी	9431222619
निलेन्दु कुमार झा	9431810505, 8210878854
सच्चिदानन्द मिश्र	9934899917
रामानंद राय	9905250798
डॉ० शशि कुमार	9507773579

संपादकीय सलाहकार

अमिताभ रंजन मिश्र	9430888060, 8873004350
अमोद कुमार	9431075402

महाप्रबंधक

त्रिलोकी नाथ प्रसाद	9308815605, 9122003000

triloki.kewalsach@gmail.com

महाप्रबंधक (विज्ञापन)

पूनम जयसवाल	9430000482, 9798874154
मनीष कुमार कमलिया	9934964551, 8809888819

उप-संपादक

अरविंद मिश्रा	9934227532, 8603069137
प्रसुन्न पुष्कर	9430826922, 7004808186
ब्रजेश सहाय	7488696914
ललन कुमार	7979909054, 9334813587
आलोक कुमार सिंह	8409746883

संयुक्त संपादक

अमित कुमार 'गुड्डू'	9905244479, 7979075212
राजीव कुमार शुक्ला	9430049782, 7488290565
कृष्ण कुमार सिंह	6209194719, 7909077239
काशीनाथ गिरी	9905048751, 9431644829
बिरेन्द्र सिंह	7050383816

सहायक संपादक

शशि रंजन सिंह	8210772610, 9431253179
मिथिलेश कुमार	9934021022, 9431410833
नवेन्दु कुमार मिश्र	9570029800, 9199732994
कामोद कुमार कंचन	8971844318

समाचार प्रबंधक

सुधीर कुमार मिश्र	9608010907

ब्यूरो-इन-चीफ

संकेत कुमार झा	9386901616, 7762089203
बिनय भूषण झा	9473035808, 8229070426

विधि सलाहकार

शिवानन्द गिरि	9308454485
रवि कुमार पाण्डेय	9507712014

चीफ क्राइम ब्यूरो

आनन्द प्रकाश	9508451204, 8409462970

साज-सज्जा प्रबंधक

अमित कुमार	9905244479

amit.kewalsach@gmail.com

कार्यालय संवाददाता

सोनू यादव	8002647553, 9060359115

प्रसार प्रतिनिधि

कुणाल कुमार	9905203164

बिहार प्रदेश जिला ब्यूरो

पटना (श०)	:- श्रीधर पाण्डेय	9470709185
(म०)	:- गौरव कुमार	9472400626
(ग्रा०)	:-	
बाढ़	:-	
भोजपुर	:- गुड्डू कुमार सिंह	8789291547
बक्सर	:- बिन्ध्याचल सिंह	8935909034
कैमूर	:-	
रोहतास	:- अशोक कुमार सिंह	7739706506
	:-	
गया (श०)	:- सुमित कुमार मिश्र	7667482916
(ग्रा०)	:-	
औरंगाबाद	:-	
जहानाबाद	:- नवीन कुमार रौशन	9934039939
अरवल	:- संतोष कुमार मिश्रा	9934248543
नालन्दा	:-	
	:-	
नवादा	:- अमित कुमार	9934706928
	:-	
मुंगेर	:-	
लखीसराय	:-	
शेखपुरा	:-	
बेगूसराय	:- निलेश कुमार	9113384406
	:-	
खगड़िया	:-	
समस्तीपुर	:-	
जमुई	:- अजय कुमार	09430030594
वैशाली	:-	
	:-	
छपरा	:-	
सिवान	:-	
	:-	
गोपालगंज	:-	
	:-	
मुजफ्फरपुर	:- .	
	:-	
सीतामढ़ी	:-	
शिवहर	:-	
बेतिया	:- रवि रंजन मिश्रा	9801447649
बगहा	:-	
मोतिहारी	:- संजीव रंजन तिवारी	9430915909
दरभंगा	:-	
	:-	
मधुबनी	:- सुरेश प्रसाद गुप्ता	9939817141
	:- प्रशांत कुमार गुप्ता	6299028442
सहरसा	:-	
मधेपुरा	:-	
सुपौल	:-	
किशनगंज	:-	
	:-	
अररिया	:- अब्दुल कय्यूम	9934276870
पूर्णिया	:-	
कटिहार	:-	
भागलपुर,	:-	
(ग्रा०)	:- रवि पाण्डेय	7033040570
नवगछिया	:-	

दिल्ली कार्यालय

केवल सच, हिन्दी मासिक पत्रिका,
द्वारा- संजय कुमार सिन्हा
A-68, 1st Floor,
नागेश्वर तल्ला, शास्त्रीनगर, न्यू
दिल्ली-110052
संजय कुमार सिन्हा, स्टेट हेड
मो०- 9868700991, 9431073769

उत्तरप्रदेश कार्यालय

केवल सच, हिन्दी मासिक पत्रिका,
................................., स्टेट हेड

सम्पर्क करें
9308815605

पश्चिम बंगाल कार्यालय

केवल सच, हिन्दी मासिक पत्रिका,
द्वारा- अजीत कुमार दुबे
131 चितरंजन एवेन्यू,
कोलकात्ता, पश्चिम बंगाल- 700073
अजीत कुमार दुबे, स्टेट हेड
मो०- 9433567880, 9308815605

मध्य प्रदेश कार्यालय

केवल सच, हिन्दी मासिक पत्रिका,
हाउस नं.-28, हरसिद्धि कैम्पस
खुशीपुर, चांबड़
भोपाल, मध्य प्रदेश- 462010
अभिषेक कुमार पाठक, स्टेट हेड
मो०- 8109932505,

झारखंड कार्यालय

केवल सच, हिन्दी मासिक पत्रिका,
वैष्णवी इंक्लेव,
द्वितीय त्तल, फ्लैट नं- 2बी
नियर- फायरिंग रेंज
बरियातु रोड, राँची- 834001

छत्तीसगढ़ कार्यालय

केवल सच, हिन्दी मासिक पत्रिका,
................................., स्टेट हेड
सम्पर्क करें
8340360961

संपादकीय व प्रधान कार्यालय:-

☞ पूर्वी अशोक नगर, रोड नं:-14, मकान संख्या:- 14/28, कंकड़बाग, पटना-800020 (बिहार) मो०- 9431073769, 9955077308

☞ .e-mail:- kewalsach@gmail.com, e ditor.kstimes@rediffmail.com
kewalsach_times@rediffmail.com

☞ स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक ब्रजेश मिश्र द्वारा सांध्य प्रवक्ता खबर वर्क्स, ए- 17, वाटिका विहार (आनन्द विहार), अम्बेडकर पथ, पटना 8000 14(बिहार) एवं पूर्वी अशोक नगर, रोड नं. 14, कंकड़बाग पटना-800020 से प्रकाशित, संपादक- ब्रजेश मिश्र। RNI NO.-BIHHIN/2006/18181

☛ पत्रिका में प्रकाशित समाचारों से संपादक की सहमति आवश्यक नहीं है।

☛ सभी प्रकार के वाद-विवादों का निपटारा पटना न्यायालय के अधीन होगा।

☛ आलेख पर कोई आपत्ति हो तो एक महीने के भीतर खंडन करें।

☛ किसी भी लेख के लिए रचनाकार/लेखक स्वयं जिम्मेवार होंगे।

☞ सभी पद अवैतनिक हैं।

☞ फोटो-समाचार साभार भी (माध्यम- इंटरनेट एवं अन्य स्त्रोत)

☞ कोई भी शिकायत हमारे पते पर लिखकर भेजें।

☞ **विज्ञापन का भुगतान चेक या ड्राफ्ट एवं RTGS से ही मान्य होगा।**

☞ भुगतान Kewal Sach को ही करें। प्रतिनिधियों को नगद न दें।

☞ A/C No. :- 0600050004768
BANK :- Punjab National Bank
IFSC Code :- PUNB0060020
PAN No. :- AAJFK0065A

प्रधान संपादक

....
....

झारखण्ड स्टेट ब्यूरो

....
....

झारखण्ड सहायक संपादक

ब्रजेश कुमार मिश्र	9431950636, 9631490205
ब्रजेश मिश्र	7654122344-7979769647
अभिजीत दीप	7004274675-9430192929

उप संपादक

....
....

संयुक्त संपादक

....
....

विशेष प्रतिनिधि

भारती मिश्रा 8210023343-8863893672

....
....

झारखण्ड प्रदेश जिला ब्यूरो

राँची	:- अभिषेक मिश्र	7903856569
	:- ओम प्रकाश	9708005900
साहेबगंज	:- अनंत मोहन यादव	9546624444
खूँटी	:-	
जमशेदपुर	:- तारकेश्वर प्रसाद गुप्ता	9304824724
हजारीबाग	:-	
जामताड़ा	:-	
दुमका	:-	
देवघर	:-	
धनबाद	:-	
बोकारो	:-	
रामगढ़	:-	
चाईबासा	:-	
कोडरमा	:-	
गिरीडीह	:-	
चतरा	:- धीरज कुमार	9939149331
लातेहार	:-	
गोड्डा	:-	
गुमला	:-	
पलामू	:-	
गढ़वा	:-	
पाकुड़	:-	
सरायकेला	:-	
सिमडेगा	:-	
लोहरदगा	:-	

श्री चन्द्र प्रकाश सिंह

प्रधान संरक्षक सह प्रबंध संपादक

'केवल सच' पत्रिका **एवं 'केवल सच टाइम्स'**

राष्ट्रीय संगठन मंत्री, राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस (इंटक)

पूर्व निदेशक सदस्य, ओरियेंटल बैंक ऑफ कॉमर्स

09431016951, 09334110654

डॉ. सुनील कुमार

शिशु रोग विशेषज्ञ सह मुख्य संरक्षक

'केवल सच' पत्रिका

एवं 'केवल सच टाइम्स'

एन.सी.- 115, एसबीआई ऑफिसर्स कॉलोनी, लोहिया नगर, कंकड़बाग, पटना- 800020

फोन- 0612/3504251

श्री सज्जन कुमार सुरेका

मुख्य संरक्षक

'केवल सच' पत्रिका **एवं 'केवल सच टाइम्स'**

डी- 402 राजेन्द्र विहार, फॉरेस्ट पार्क

भुवनेश्वर- 751009 मो-09437029875

सुधीर कुमार

मुख्य संरक्षक सह निदेशक **"मगध इंटरनेशनल स्कूल"** टेकारी

" केवल सच " पत्रिका **एवं " केवल सच टाइम्स "**

9060148110

sudhir4s14@gmail.com

श्री आर के झा

मुख्य संरक्षक

'केवल सच' पत्रिका **एवं 'केवल सच टाइम्स'**

EX. CGM, (Engg.) N.B.C.C

08877663300

बिहार राज्य प्रमंडल ब्यूरो

पटना		
मगध		
सारण		
तिरहुत		
पूर्णिया	**धर्मेन्द्र सिंह**	9430230000 7004119966
भागलपुर		
मुंगेर		
दरभंगा		
कोशी		

विशेष प्रतिनिधि

आशुतोष कुमार	9430202335, 9304441800
सुमित राज यादव	9472110940, 8987123161
बेंकटेश कुमार	8521308428, 9572796847
राजीव नयन	9973120511, 9430255401
मणिभूषण तिवारी	9693498852
दीपनारायण सिंह	9934292882
आनन्द प्रकाश पाण्डेय	9931202352, 7808496247
विनित कुमार	8210591866, 8969722700
रामजीवन साहू	9430279411, 7250065417

छायाकार

त्रिलोकी नाथ प्रसाद	9122003000, 9431096964
मुकेश कुमार	9835054762, 9304377779
जय प्रसाद	9386899670,
कृष्णा प्रसाद	9608084774, 9835829947

माया मिली न राम... !

● अमित कुमार

'दिल के अरमां आंसुओं में बह गये और पीएम पद की बात तो दूर, संयोजक भी बनते-बनते रह गये'। शायद यही अल्फाज इस वक्त नीतीश कुमार गुनगुना रहे होंगे! ज्ञात हो कि 12 जून को पटना में देशभर के विपक्षी दलों की बैठक के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहल पर कांग्रेस का रुख जैसा था, वैसा ही 19 दिसम्बर की चौथी बैठक के दौरान उसमें कोई बदलाव नहीं दिखा। कांग्रेस के नंबर वन नेता राहुल गांधी और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे उस बैठक में आने को तैयार नहीं हुए तो 23 जून की तारीख रखी गई। इस बार पहल राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद ने भी की। यह बैठक हुई भी। इस दौरान नीतीश को संयोजक बनाए जाने की चर्चा रही, लेकिन यह पूरा नहीं हुआ। इसके बाद दो बैठकें हुई, लेकिन नीतीश किनारे ही रहे। वह किसी पद की इच्छा नहीं जता रहे, लेकिन बिहार और उनकी पार्टी से लगातार मांग उठ रही थी कि उन्हें पीएम का प्रत्याशी घोषित किया जाए।

19 दिसम्बर की बैठक से पहले भी यह आवाज तेजी से उठी थी, लेकिन दिल्ली में जब सारे नेता बैठे तो सब उलटा हो गया। लालू ने कुछ बोला नहीं और उनके करीबी रहे कुछ नेताओं ने आवाज भी उठाई भी तो कांग्रेस के लिए।

गौरतलब हो कि दिल्ली में इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक हुई। बैठक में सीट शेयरिंग, संसद में सांसदों को सस्पेंड करने समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। किन्तु इंडिया गठबंधन की बैठक के बीच ही नीतीश कुमार और लालू यादव निकल गए। ये दोनों नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी शामिल नहीं हुए। दोनों नेताओं के नाराज होने की वजह खड़गे को इंडिया गठबंधन का पीएम चेहरा का प्रस्ताव बताया जा रहा है। दरअसल, ममता बनर्जी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को इंडिया गठबंधन का पीएम चेहरा का प्रस्ताव रखा था। इस पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी ममता बनर्जी के प्रस्ताव का समर्थन कर दिया।

इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक

इससे नाराज नीतीश और लालू यादव बैठक को बीच में छोड़कर बाहर निकल गए। बता दें कि इंडिया गठबंधन बनाने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी विपक्षी दलों को एक साथ जोड़ा था। इसके बाद राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा थी कि नीतीश कुमार गठबंधन का संयोजक बन सकते हैं। इससे पहले तीन बैठकों में पीएम के चेहरे पर सहमति नहीं बन पा रही थी। वही इस चौथी बैठक में इस बात की चर्चा थी कि नीतीश कुमार को गठबंधन का मुखिया बनाया जाएगा। यानी प्रधानमंत्री का चेहरा नीतीश कुमार ही होंगे, लेकिन बैठक शुरू होते ही ममता बनर्जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे को पीएम उम्मीदवार के तौर पर नाम का प्रस्ताव रख दिया। इससे गठबंधन की बैठक में फूट पड़ गई और बीच बैठक में ही नीतीश कुमार और लालू यादव बाहर निकल आए। दिगर बात है कि इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में नीतीश कुमार और लालू यादव के शामिल नहीं होने पर बीजेपी ने चुटकी ली। बिहार बीजेपी के दिग्गज नेता एवं राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने एक्स पर लिखा कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनने का सपना लेकर 2022 में दूसरी बार भाजपा से नाता तोड़ लिए थे और अब पटना में अपने पक्ष में पोस्टर लगवा कर बड़ी उम्मीद से गठबंधन की दिल्ली बैठक में गए थे, लेकिन किसी ने संयोजक पद के लिए भी उनके नाम का प्रस्ताव नहीं किया। प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी तो बहुत दूर की बात है। मोदी ने कहा कि नीतीश कुमार को न माया मिली, न राम। वे खाली हाथ जब पटना लौटेंगे, तब जदयू के लिए कार्यकर्ताओं का मनोबल बनाये रखना मुश्किल होगा। पार्टी में भगदड़ मच सकती है।

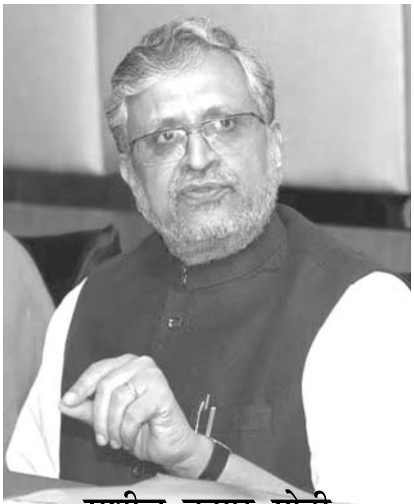
सुशील कुमार मोदी

बहरहाल, राजस्थान, मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ में भाजपा की प्रचंड जीत के बाद अब भाजपा के पास कुल 17 राज्यों में सत्ता होगी। लोकसभा 2024 चुनाव में भाजपा से मुकाबले के लिए कांग्रेस ने विपक्षी दलों के साथ इंडिया गठबंधन तो जरूर बनाया किंतु लोकसभा चुनाव के पांच महीने पहले अब इन राज्यों में कांग्रेस को मिली हार का असर इंडिया गठबंधन पर क्या होगा? भाजपा ने हिंदी पट्टी के तीनों राज्यों में सरकार बना ली और भाजपा का मुकाबला करने के लिये बनाए गये इंडिया गठबंधन क्या काम आया? सबसे बड़ा दल कांग्रेस सिर्फ एक राज्य में सरकार बना पायी। ऐसे में सवाल है कि क्या कांग्रेस, इंडिया गठबंधन की धुरी बनी रह सकती है? और इससे भी बड़ा सवाल ये कि क्या इंडिया गठबंधन का कोई भविष्य बचा भी है? सनद् रहे कि 3 दिसंबर को कांग्रेस की तरफ से घोषणा हुई थी कि इंडिया गठबंधन की अगली मीटिंग 6 दिसम्बर को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के घर पर होगी। गौर करने लायक बात ये है कि पिछले तीन महीनों से इंडिया गठबंधन की कोई मीटिंग नहीं हुई थी, लेकिन बाद में खबर आयी कि मीटिंग टल गई है; क्यों? क्योंकि

प्रेस वार्ता में इंडिया गठबंधन के नेता

राजस्थान में भाजपा

अखिलेश यादव, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी और एम.के. स्टालिन ने मीटिंग में आने से इनकार कर दिया था। सबके अपने-अपने तर्क हैं, पर ट्विंकल-ट्विंकल लिटिल स्टार बोलने वाले बच्चे भी ये बता सकते हैं कि अंदरखाने कुछ खटपट तो चल ही रही है। वही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीते दिनों सीपीआई सीपीएम की रैली में कहा था कि "इंडिया अलाइंस में अब तो कुछ हो ही नहीं रहा है, कांग्रेस पार्टी पांच राज्यों के चुनाव में ज्यादा व्यस्त है"। उधर सपा की नाराजगी की कई वजहें देखी जा सकती है। पहली तो यही है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने सपा के साथ गठबंधन नहीं किया। इसके अलावा कमलनाथ के अखिलेश पर दिए बयान ने भी रिश्ते तल्ख कर दिए। दरअसल मामला ये था कि अखिलेश ने गठबंधन न करने पर कह दिया कि कांग्रेस ने धोखा किया है तो दूसरी तरफ इस पर जब कमलनाथ से मीडिया ने पूछा तो उन्होंने कहा कि "अरे भाई! छोड़ो अखिलेश वखिलेश"। वही ममता बनर्जी ने दावा किया कि उन्हें तो इस मीटिंग की कोई खोज-खबर ही नहीं थी। वे तो उत्तरी बंगाल के दौरे पर हैं। इसलिए मीटिंग में नहीं आएंगी। भविष्य में क्या होगा, इस पर तो अनुमान लगाना मुश्किल हैं, पर अब तक जो कुछ हुआ उसका बेसिक क्लीअर करना जरूरी है। अगर क्षेत्रीय दलों की तरफ से इस तरह के सिग्नल आ रहे हैं, तो इससे यही मैसेज जा रहा है कि इंडिया का बिखराव शुरू हो गया है। क्योंकि अगर भिड़ना ही था तो अंदरखाने भिड़ते, इस तरह मीडिया के सामने लड़ना, उनकी लड़ाई को ही कमजोर करेगा। क्या कॉन्फिडेंस आएगा कार्यकर्ताओं में? इसके अलावा उनकी सबसे बड़ी वीकनेस है कि उनके पास कोई लीडर ही नहीं है। वही कांग्रेस की हार के बाद अब विपक्षी पार्टियों के पास कोई विकल्प ही कहां बचता है कि वे इंडिया गठबंधन से अलग होने की सोचें भी।

बताते चले कि इंडिया गठबंधन का पूरा नाम है Indian National Developmental Inclusive Alliance जिसे हिन्दी में भारतीय राष्ट्रीय विकासशील समावेशी गठबंधन कहेंगे। 2024 के आम चुनावों से पहले, पीएम मोदी की बीजेपी और एनडीए से मुकाबला करने के लिए देश भर की 28 पार्टियों ने एक साथ गठबंधन किया। जुलाई 2023 में बंगलुरु से पहली बार इंडिया गठबंधन का नाम अनाउंस हुआ था। इससे पहले जून 2023 में पटना में 15 विपक्षी पार्टियों की बैठक में इस गठबंधन का खाका बनने लगा था। ऐसा ही माहौल नब्बे का पूरा दशक राजनीतिक अस्थिरता का था और ऐसे में कांग्रेस से मुकाबला करने के लिए एनडीए की स्थापना हुई थी। उस वक्त हुआ ये है कि तब कांग्रेस से लड़ने के लिए बीजेपी एक गठबंधन में शामिल हुई थी और अब बीजेपी से लड़ने के लिए कांग्रेस एक गठबंधन में शामिल हुई है। 19 दिसम्बर की बैठक से पहले कयास लगाये जा रहे थे कि अगली जब भी समन्वय समिति की मीटिंग होगी, उसमें तीन मुद्दे प्रमुख होंगे। पहला कि गठबंधन की पार्टियां कांग्रेस से सीट शेयरिंग पर क्लैरिटी चाहती हैं। इसके अलावा कॉमन कैम्पेन प्लान पर भी बात होगी और आगामी चुनावों पर घोषणापत्र क्या होना चाहिए, इस पर भी एक कॉमन एजेंडा बनेगा। तो इस तरह से ये एक आइस ब्रेकिंग मीटिंग होने वाली होगी। बाद में जब 6 दिसंबर की बैठक रद्द हुई तब लालू प्रसाद यादव द्वारा 17 दिसम्बर की तारीख का ऐलान जरूर किया गया किन्तु वह तारीख भी मुक्कविल ना हो सकी। अब यह तारीख बढ़कर 19 दिसम्बर कर दी गई। हालिया चुनावों के नतीजों के बाद होने वाली बैठक का महत्व अब और भी बढ़ गया है। सवाल उठ रहे हैं कि इन नतीजों का इस गठबंधन और इसके भविष्य पर क्या असर पड़ेगा। ऐसा इसलिए भी, क्योंकि नतीजों के बाद इंडिया के घटक दलों ने

छत्तीसगढ़ में भाजपा

मध्य प्रदेश में भाजपा

हार की समीक्षा करते कांग्रेस अध्यक्ष

बिहार भाजपा में जीत की खुशी

कांग्रेस के रवैए पर सवाल उठाए हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्लाह ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा था कि 'कांग्रेस ने चुनावों के दौरान जो बातें की थीं, वे खोखली साबित हुईं।' उन्होंने गठबंधन की उपेक्षा का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि '6 तारीख की मिटिंग के बहाने तीन महीने बाद उनको इंडिया एलायंस दोबारा याद तो आया। अब देखते हैं, उस पर क्या बात होती है।' इसी तरह जेडीयू ने भी कांग्रेस पर तंज कसा। पार्टी के प्रवक्ता केसी त्यागी ने कहा था कि 'इन चुनावों में विपक्ष के तौर पर इंडिया गठबंधन कहीं था ही नहीं। उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक तौर पर सोशलिस्ट पार्टियाँ इन राज्यों में थीं, लेकिन कांग्रेस ने कभी इंडिया गठबंधन के अपने दूसरे सहयोगियों से न तो सलाह ली और न ही उनसे राय मांगी।' उन्होंने ये भी कहा कि 'चुनाव प्रचार के दौरान भोपाल में इंडिया गठबंधन की एक रैली होनी थी, लेकिन पार्टी नेतृत्व ने ये रैली नहीं करने का फैसला किया।'

इंडिया गठबंधन की बैठक की तैयारी

गौरतलब हो कि इंडिया गठबंधन पहले ही दिन से कई चुनौतियों से जूझ रहा है, जैसे इसके घटक दल कई राज्यों में एक दूसरे के सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी हैं और वे एक-दूसरे के खिलाफ चुनाव भी लड़ते रहे हैं। इसके साथ ही विभिन्न मुद्दों और विषयों पर उनकी राय और स्टैंड भी अलग है। इंडिया गठबंधन और कांग्रेस ने इन चुनावों में एक मौका गँवाया है। उनकी नजर में इन चुनावों में विपक्षी दलों को साथ लेने और एक राजनीतिक बदलाव की पहल की जा सकती थी, जिससे इंडिया गंठबंधन की भावना को मजबूती मिलती। छोटी पार्टियों को अपने साथ लेने से कांग्रेस को जो फायदा मिल सकता था, उसमें उसने चूक की है। वही गठबंधन बनने से जो राजनीतिक शक्ल बदलती है, वह नहीं बदली। जैसे तेलंगाना में उन्होंने सीपीआई के साथ गठबंधन किया था, लेकिन सीपीएम के साथ नहीं किया था, तो इस तरह से बाकी जगह भी छोटे दलों को साथ लाने का फायदा वे नहीं ले पाए। उदाहरण के तौर पर देखे कि जैसे अजीत जोगी की पार्टी जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ का वोट बीजेपी को ट्रांसफर हो गया। इसी तरह राजस्थान में भारत आदिवासी पार्टी के साथ भी गठबंधन किया जा सकता था। अखिलेश यादव की पार्टी एसपी मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ना चाहती थी तो एक-दो सीटें उन्हें दी जा सकती थी। कुछ सीटें वामदलों को देते तो नई राजनीति ला सकते थे, लेकिन कांग्रेस उसी लाइट-हिंदुत्व में पड़ गई। न कांग्रेस ने हिंदुत्व को चुनौती दी, न ही उस पर खेल पाए। तो फिर कोई कांग्रेस को क्यों चुनेगा? यहाँ सिर्फ कांग्रेस बनाम बीजेपी की लड़ाई हुई। यह इंडिया एलायंस का टेस्ट ही नहीं था। बता दें कि कांग्रेस के नेताओं ने इन चुनावों में लगभग हर मंच से यह वादा दोहराया कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आई तो जाति आधारित जनगणना कराएँगे। यह विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया का भी प्रमुख मुद्दा है। इस साल 18 जुलाई को बेंगलुरु में बैठक के बाद एक साझा बयान जारी कर इंडिया गठबंधन ने जातिगत जनगणना कराने की मांग की थी। माना जाता है कि बीजेपी इस तरह की जनगणना कराने को लेकर असहज है, क्योंकि उसे डर है कि इससे उसके अगड़ी जातियों के परंपरागत हिंदू वोटर नाराज हो सकते हैं। 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए भी अभी से विपक्षी दल जाति आधारित जनगणना को अहम मुद्दा बनाते हुए चल रहे हैं। ऐसे में क्या ये चुनाव इस मुद्दे का भी लिटमस टेस्ट थे, क्योंकि इन राज्यों में ओबीसी वोटरों की काफी संख्या है? मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में समाजवादी या पिछड़ा वर्ग आंदोलन का उतना प्रभाव नहीं रहा, जितना उत्तर प्रदेश या बिहार में रहा है। बिहार और यूपी में क्षेत्रीय दल मजबूत हैं। उनके पास जातिगत जनगणना के मुद्दे के लिए एक कैडर है। जिस तरह बिहार में कर्पूरी ठाकुर और लालू प्रसाद यादव या उत्तर प्रदेश में लोहिया या मुलायम सिंह यादव ने लड़ाई लड़ी है, वैसी इन राज्यों में नहीं लड़ी गई। इसलिए, वहाँ बीजेपी को कांग्रेस के खिलाफ खाली मैदान मिला है। कांग्रेस ने तो बैकवर्ड क्लास मूवमेंट की बात इंडिया गठबंधन बनने के बाद ही की। वही उत्तर प्रदेश या बिहार की तुलना में अभी राजस्थान और मध्य प्रदेश में जातिगत जनगणना के मुद्दे को लेकर उतनी जागरूकता नहीं है। साथ ही

अखिलेश यादव

उमर अब्दुला

ममता बनर्जी

अरविंद केजरीवाल

राजस्थान और मध्य प्रदेश में जिस तरह का एक सामंती ढाँचा है, वहाँ कोई ऐसी प्रभावशाली जाति नहीं है जो इस मुद्दों पर बात कर सके। यहाँ जातिगत जनगणना का असर उतना नहीं है, क्योंकि यहाँ के लिए यह विषय नया है, जबकि बिहार वगैरह में इस विषय पर पहले ही लामबंदी हो चुकी है।

बहरहाल, मल्लिकार्जुन खड़गे ने इंडिया गठबंधन की जो बैठक बुलाई थी, माना जा रहा है कि उसमें लोकसभा चुनावों से पहले सीटों के बँटवारे पर भी चर्चा हो सकती थी। चुनावों के जो नतीजे आए हैं, उनसे इंडिया गठबंधन का काम आसान हो जाएगा। इस हार से इंडिया एलायंस के आतंरिक समीकरण थोड़े आसान हो जाएँगे, क्योंकि अगर कांग्रेस मजबूती से आती तो परेशानी बढ़ सकती थी। इस धक्के के बाद कांग्रेस और अन्य पार्टियों को अहसास होगा कि हमें इस गठबंधन और एक-दूसरे के प्रति समझ बनाने की जरूरत है। वही जिन राज्यों में बीजेपी जीती है, वहाँ इंडिया एलायंस का खास असर नहीं है। हालाँकि, राजस्थान में कांग्रेस अगर सीपीएम और बीएपी के साथ गठबंधन करती तो एकतरफा जीत नजर नहीं आती। मामला काफी करीबी आ सकता था। इस गठबंधन की जरूरत महाराष्ट्र, झारखंड, बिहार, असम और उत्तर प्रदेश में ज्यादा है।

सनद् रहे कि चार राज्यों के विधानसभा चुनावों के नतीजों के बाद गठबंधन के सभी दल कांग्रेस पर हमलावर हो गए हैं। जीत हर सवाल का जवाब होती है। जीत के साथ ही सवाल भी खत्म हो जाते हैं। विधानसभा चुनावों में हार के बाद कांग्रेस के विपक्षी खेमे के नेताओं के निशाने पर आ जाने की सबसे बड़ी वजह तो यही है, लेकिन क्या बात बस इतनी ही है? चुनावों में हार जीत लगी रहती है। जिस बीजेपी ने तीन राज्यों में चुनाव जीते हैं, 2018 में सत्ता में होते हुए भी चुनाव हार गयी थी। देखा जाये तो पिछली बार बीजेपी पांचो राज्यों में चुनाव हार गयी थी, कांग्रेस के पास तो ये कहने का मौका भी है कि एक राज्य तेलंगाना का चुनाव तो वो जीती ही है। विपक्षी गठबंधन इंडिया को लेकर सहयोगी दलों के नेताओं के निशाने पर कांग्रेस नेतृत्व के आ जाने की असली वजह सिर्फ ये नहीं है बल्कि, ये तो बहाना भर है। असली बात तो ये है कि कांग्रेस अपनी ही चाल में फंस गयी है और अब कांग्रेस के साथ विपक्षी खेमे के नेता बिल्कुल वैसी ही राजनीति कर रहे हैं, जैसा कांग्रेस उनके साथ कर रही थी। विधानसभा चुनावों के दौरान कांग्रेस नेतृत्व नीतीश कुमार के निशाने पर रहा। अब नीतीश कुमार, ममता बनर्जी और अखिलेश यादव तीनों एक साथ कांग्रेस नेतृत्व को आंख दिखाने लगे हैं, जैसे कांग्रेस ही विपक्ष के बिखराव के लिए जिम्मेदार है। किन्तु यह भी सच है कि पिछले 3 महीने में 'इंडिया' की बैठकों को रोककर कांग्रेस का नेतृत्व 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों पर कांग्रेस का फोकस था। नतीजों के सामने आने के बाद चार में से तीन राज्यों में कांग्रेस की हार हो गई। इसके बाद कांग्रेस को अब गठबंधन में शामिल दूसरे दलों के गुस्से का सामना करना पड़ रहा है। जो इसे एक बड़े मौके की चूक बता रहे हैं। इन तीन महीने में कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों के बीच कटुता उभरकर सामने आ गई। कांग्रेस ने इन सभी 5 राज्यों में हुए चुनाव में विपक्षी गठबंधन 'इंडिया' में शामिल अपने सहयोगियों को सीटें देने से साफ इनकार कर दिया था। कांग्रेस का कहना था कि यह गठबंधन केवल 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए है। 'इंडिया' गठबंधन में सबसे ज्यादा कटुता मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ

लालू प्रसाद यादव

रामनाथ ठाकुर

नीतू सिंह

के.सी. त्यागी

सीटें बांटने से इनकार करने पर देखी गई।

बहरहाल, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा इंडिया गठबंधन के 28 दलों की बैठक 6 दिसंबर को बुलाई थी, लेकिन ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, अखिलेश यादव और हेमंत सोरेन जैसे नेताओं के न पहुंच पाने के कारण मीटिंग को रद्द करनी पड़ी। इसके बाद लालू प्रसाद यादव की तरफ से अपडेट किया गया है कि 17 दिसंबर को गठबंधन की मीटिंग होने जा रही है। लालू यादव ने ये भी कहा है कि मीटिंग में ममता बनर्जी सहित सारे नेता हिस्सा लेंगे किन्तु इसे भी बढ़ाकर 19 दिसम्बर किया गया और यह चौथी बैठक दिल्ली में मल्लिकार्जुन के नेतृत्व में पूरी भी हुई। दूसरी तरफ नाराज अखिलेख की बात करे तो मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने सपा को एक भी सीट नहीं दी थी, वह भी नहीं जहां से 2018 में अखिलेश की पार्टी के उम्मीदवार को जीत मिली थी। अखिलेश और कांग्रेस की तल्खी जगजाहिर रही तो वहीं ममता बनर्जी ने भी चुनावी राज्यों में क्षेत्रीय दलों को लेकर ग्रैंड ओल्ड पार्टी के रवैये पर सवाल उठाए थे। जनता दल यूनाइटेड के नेता नीतीश कुमार ने भी राज्यों के चुनाव की वजह से इंडिया गठबंधन का कोई कार्यक्रम नहीं होने को लेकर नाराजगी जताई थी। अब सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बड़ी लकीर खींच दी है। अखिलेश यादव ने साफ संदेश दे दिया है कि अब इंडिया गठबंधन में पहले सीट बंटवारा होगा और इसके बाद आगे की बात होगी। उन्होंने ये भी कहा है कि इंडिया गठबंधन के पहले जो बात तय हुई थी कि जो जहां मजबूत होगा वो वहां नेतृत्व करेगा और दूसरी पार्टियां वहां उसकी सहयोग करेंगी। इंडिया गठबंधन को इसी फॉर्मूले पर आगे बढ़ना होगा। अब चूकि इंडिया गठबंधन के घटक दलों के बीच लोकसभा सीटों के बंटवारे की कवायद शुरू होनी है, पर मौजूदा परिस्थितियों में यह गुत्थी आसानी से सुलझते हुए नहीं दिख रही है। सपा ने फैसला किया है कि घटक दलों के पास मजबूत प्रत्याशी होने पर ही वह कोई भी सीट छोड़ेगी। सीटों के बंटवारे के लिए तृणमूल, सपा और डीएमके सरीखी क्षेत्रीय पार्टियां भी एकसमान फॉर्मूला अपनाने पर सहमत हैं। इंडिया के सूत्रों का कहना है कि अब क्षेत्रीय शक्तियां भी सीटों के लिहाज से कांग्रेस की बहुत ज्यादा बात मानने के लिए तैयार नहीं हैं। सपा पहले ही कांग्रेस से कह चुकी है कि यूपी में वो जो सीटें चाहती है, उन पर किस नेता को लड़ाएगी, पहले यह बताए। सपा के रणनीतिकारों का कहना है कि लोकसभा चुनाव में कोई भी प्रत्याशी तभी लड़ाई में आता है, जब उसके पास कम से कम डेढ़ से दो लाख बुनियादी वोटों का इंतजाम हो। तब गठबंधन के कारण जुड़ने वाला वोट उसे जीत की ओर ले जाता है। इसलिए पहले कांग्रेस को यह बताना होगा कि डेढ़ से दो लाख बुनियादी वोट हासिल कर सकने वाले कौन से नेता उसके पास हैं। सीट बंटवारे की बात उसके बाद ही शुरू होगी। सपा सूत्रों का कहना है कि इंडिया की समन्वय बैठक में मांगे जाने के बावजूद कांग्रेस ने उन नेताओं की सूची नहीं सौंपी है, जिन्हें वह यूपी में लोकसभा चुनाव लड़ाना चाहती है। हालांकि अखिलेश इंडिया गठबंधन से एग्जिट की बात नहीं कर रहे लेकिन साथ ही संकेत ये भी साफ दे रहे हैं कि बात अब हमारी शर्तो पर ही होगी। अब सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या कांग्रेस अखिलेश यादव की इस शर्त पर राजी होगी?

गौरतलब हो कि चुनावी नतीजे आने के बाद कांग्रेस को यूपी, बिहार और बंगाल के साथ-साथ जम्मू-कश्मीर से भी नेताओं ने तेवर दिखाने शुरू कर दिये। यूपी से अखिलेश यादव, बिहार से नीतीश कुमार, पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी और जम्मू-कश्मीर से उमर अब्दुल्ला। वैसे नीतीश कुमार ने गठबंधन की 6 दिसम्बर

राहुल गांधी

नीतीश कुमार

की मीटिंग में शामिल न होने की वजह अपनी तबीयत ठीक न होना बताया, लेकिन उमर अब्दुल्ला तो कह रहे हैं कि गठबंधन का मतलब सिर्फ कांग्रेस नहीं होता। सही बात है, गठबंधन में सभी बराबर के हकदार हैं। वही पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव के बाद एक बार फिर विपक्षी गठबंधन की चर्चा जोरों पर है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इंडिया अलायंस की बैठक की तारीख निर्धारित की तो विपक्ष के कई दलों ने दूरी बना ली। सपा ने खुलकर अपनी शर्तें रख दी। वही 19 दिसंबर को इंडिया गठबंधन की अहम बैठक से ठीक पहले अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के 13 में से 13 लोकसभा सीटें मांगी है। अब इन तमाम पार्टी नेताओं के विरोध को बैलेंस करने के लिए एक बार फिर बिहार के मुख्यमंत्री और जदयू नेता नीतीश कुमार का नाम आगे किया जाने लगा है। हालांकि अटकलें लगाई जा रही थीं कि लालू के सहयोगी और बिहार के सीएम नीतीश कुमार बैठक में शामिल होने के लिए तैयार नहीं थे। हालांकि अपने चेहरे को फ्रंट बनाने को लेकर नीतीश कुमार ने मिटिंग में न जाने को लेकर बीमार होने का बहाना बनाया। वही बता दें कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे। पत्रकारों से बातचीत के दौरान ये सभी बाते कहीं गई। नीतीश कुमार की तबीयत को लेकर विपक्षी दल

तमाम तरह की अटकलें लगा रहे थे और हेल्थ बुलेटिन तक जारी करने की डिमांड की थी। किन्तु 5 दिसम्बर को कैबिनेट की बैठक में भी नीतीश शामिल हुए थे। उक्त मौके पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि न जाने क्या फालतू न्यूज छप रहा था कि हम नहीं जाएंगे। हम तो चाहते हैं कि सब मिलकर काम करें। नीतीश कुमार ने कहा कि मेरी तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं चल रही थी। मुझे सर्दी-खांसी और बुखार हो गया था और पांच दिनों से आराम कर रहे थे और अब 17 दिसम्बर को होने वाली बैठक में जरुर शामिल होंगे। चुनाव में हार-जीत होती रहती है। कांग्रेस को कम वोट नहीं आया है। हमारे नहीं जाने की बात बेकार है। हम

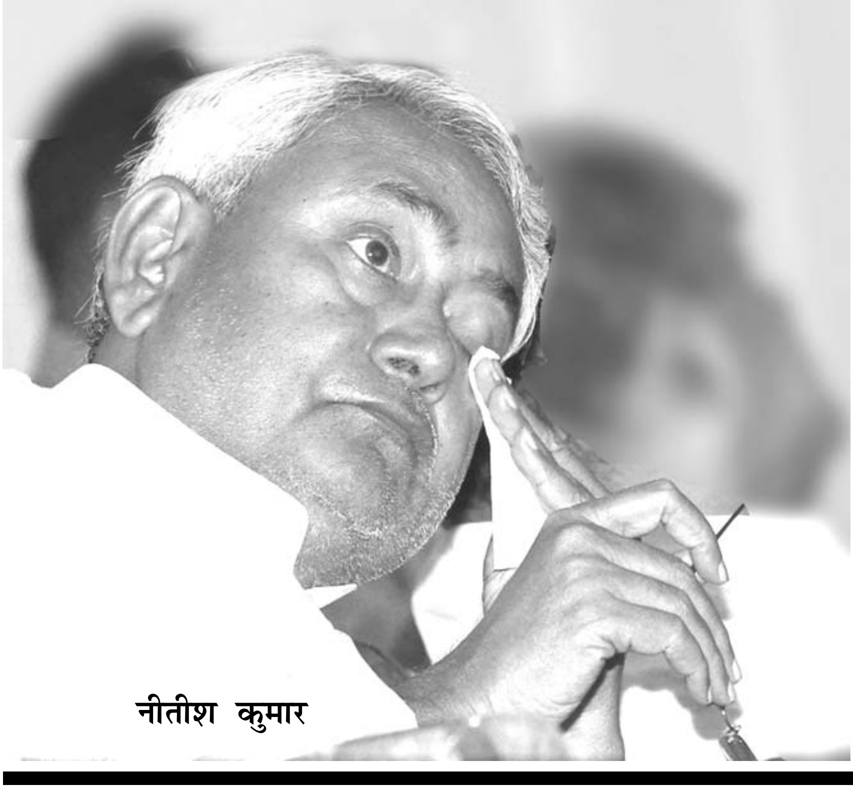
नीतीश कुमार

अलायंस की बैठक में नहीं जाएंगे, ये संभव ही नहीं है। उन्होंने कहा कि हमें कुछ नहीं चाहिए। नीतीश ने बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि अब देर नहीं होनी चाहिए। एकजुट होकर सब लड़ें, यही चाहते हैं। हमें कुछ नहीं चाहिए, इंडिया गठबंधन के साथ रहूंगा। सभी विपक्षी दल मिलकर काम करें और तैयारी तेज कर दें। बिहार के हित में हमेशा काम करता रहूंगा। नीतीश ने कहा कि अगर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले तो और अच्छा रहेगा। साथ ही उन्होने जातीय गणना और आर्थिक सर्वेक्षण की वकालत की। उन्होंने कहा कि मुझे अपने लिए व्यक्तिगत कुछ नहीं चाहिए। जैसे आजादी की लड़ाई लड़ी गई, वैसे ही इनसे लड़ाई लड़नी है। नीतीश ने आगे कहा कि ये लोग (बीजेपी) पूरा इतिहास बदल रहे हैं। इनके खिलाफ एकजुट होकर लड़ना होगा। हालांकि नीतीश कुमार को बीमार होने की बात पर सफाई इसलिए देनी पड़ी, क्योंकि सवाल ये उठ रहे थे कि अगर बीमार थे तो मीटिंग से ठीक एक दिन पहले 5 दिसंबर को वो कैबिनेट की मीटिंग में कैसे शामिल हुए थे?

बहरहाल, कांग्रेस की हार के बाद गठबंधन में एक बार भी नीतीश कुमार के समर्थन में आवाजें जरूर उठ रही थी। यहां तक की बिहार से कांग्रेस विधायक नीतू सिंह ने भी कहा था कि कांग्रेस को बड़ा दिल दिखाना चाहिए। उन्होंने कहा था कि इंडिया गठबंधन को नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ना चाहिए। इसका नेतृत्व जल्द उन्हें दिया जाए। पहले भी कांग्रेस गैर कांग्रेसी को पीएम बना चुकी है। उन्होंने मांग की कि नीतीश के बिहार मॉडल पर देश में चुनाव लड़ा जाए। नीतू ने अपनी पार्टी पर सवाल उठाते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से चूक हुई है। दरअसल, उनका इशारा एमपी में सपा समेत अन्य दलों से गठबंधन न करने को लेकर था। वही जनता दल

यूनाइटेड नेता और राज्यसभा सांसद रामनाथ ठाकुर ने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को विपक्षी गठबंधन 'इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इन्क्लूसिव अलायंस' (इंडिया) का संयोजक बनाया जाना चाहिए। जेडीयू के राज्यसभा सदस्य ने कहा कि नीतीश कुमार ने अपनी छवि ऐसी बनाई है जो उन्हें विपक्षी समूह के संयोजक बनने के लिए सबसे उपयुक्त बनाती है। उन्होंने कहा कि ''नीतीश कुमार ने बिहार में अपनी जो छवि बनाई है, अगर वह इंडिया के नेता बनते हैं तो यह अच्छा होगा।

विदित हो कि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव कांग्रेस की हार से मन ही मन फूले नहीं समा रहे होंगे क्योंकि कांग्रेस की केंद्र में बीजेपी को सत्ता से हटाने के मुहिम की हवा निकाल दी है। ऐसा माना जा रहा था कि चार राज्यों में से तीन राज्यों पर भाजपा की प्रचंड जीत और कांग्रेस की पराजय ने बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद को भी नई संजीवनी दे दी है। ज्ञात हो कि 2024 लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाने के लिए बनी इंडिया गठबंधन की आखिरी बैठक 3 महीने पहले हुई थी जिसके बाद अब तक एक भी बैठक नहीं हुई और इसी को लेकर पिछले दिनों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी कांग्रेस पर करारा हमला बोला था। नीतीश कुमार ने शायद नवंबर के शुरुआत में जो भविष्यवाणी की थी वह विधानसभा चुनाव के नतीजे के बाद बिल्कुल सही साबित हो रहे हैं, क्योंकि तीन राज्यों में कांग्रेस की करारी हार के बाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड्गे ने 6 दिसंबर को इंडिया गठबंधन की महत्वपूर्ण बैठक दिल्ली में बुलानी पड़ी, हालांकि वह मिटिंग टल गई। इसे भुनाने के लिए नीतीश कुमार की पार्टी ने नीतीश के पक्ष में माहौल बनाना शुरू कर दिया। एक बात तो साफ है कि तीन राज्यों में कांग्रेस को मिली करारी शिकायत ने एक बार फिर से इंडिया गठबंधन के अन्य दलों को नई ऊर्जा से भर दिया है और जनता दल यूनाइटेड जैसे क्षेत्रीय दल कांग्रेस को सीधा संदेश देने में जुट गये कि क्षेत्रीय दलों की अनदेखी कर कांग्रेस 2024

मल्लिकार्जुन खड्गे

लोकसभा चुनाव में बीजेपी को नहीं हरा सकती। किन्तु इन तमाम कयासो पर कांग्रेस ने पानी फेर दी। 19 दिसम्बर की चौथी बैठक में नीतीश कुमार को कुछ भी नहीं मिला। वह देखते ही रह गये और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड्गे पहले संयोजक और अब पीएम फेश के नाम पर आवाजे उठने लगी। नीतीश कुमार की तो कही चर्चा भी नहीं हुई। बहरहाल, बैठक से पूर्व जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश महासचिव निखिल मंडल ने कांग्रेस की विधानसभा चुनाव में हुई हार के बाद सोशल मीडिया पर नीतीश कुमार के पक्ष में माहौल बनाना शुरू कर दिया। निखिल मंडल ने सोशल मीडिया पर लिखा कि 'इंडिया गठबंधन को अब नीतीश कुमार के अनुसार चलना चाहिए। इंडिया गठबंधन के सूत्रधार नीतीश कुमारी अब विपक्षी गठबंधन की नैया को पार कर सकते हैं।' निखिल मंडल के पोस्ट से स्पष्ट है कि कांग्रेस की विधानसभा चुनाव में हार के बाद क्षेत्रीय दलों के हौसले बुलंद हो गए हैं और अब इन दलों ने कांग्रेस पर दबाव की राजनीति बनाना शुरू कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक, जनता दल यूनाइटेड और लालू प्रसाद की आरजेडी, कांग्रेस की हुई हार से गदगद हैं, क्योंकि इंडिया गठबंधन की तीसरी बैठक के बाद इस तरीके का देश में माहौल बन रहा था कि कांग्रेस अकेले अपने दम पर बीजेपी को 2024 में चैलेंज करने की कोशिश कर रही थी और सहयोगी दलों की अनदेखी की जा रही थी। सूत्र बताते हैं की जनता दल यूनाइटेड और राजद को इस बात का डर था कि अगर विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की बड़ी जीत होती है तो फिर वह क्षेत्रीय दलों की आगे और ज्यादा अनदेखी करेगी और खासकर बिहार जैसे राज्य में जब सीटों के बंटवारे का सवाल उठेगा तो कांग्रेस लोकसभा चुनाव में ज्यादा सीटों की मांग करेगी और साथ ही 2025 के विधानसभा चुनाव में भी पहले से अधिक संख्या में सीट की मांग करेगी। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की हार ने नीतीश और लालू प्रसाद के ऊपर से दबाव काफी कम कर दिया है और अब इसके उलट कांग्रेस क्षेत्रीय दलों के दबाव में नजर आ रही है। अब सीटों के बंटवारे को लेकर दोनों क्षेत्रीय दलों के नेताओं की बारगेनिंग कैपेसिटी कई गुना ज्यादा बढ़ चुकी है। विधानसभा चुनाव में अगर कांग्रेस की बड़ी जीत होती तो साफ है कि लोकसभा चुनाव में भी बिहार में कांग्रेस 40 में से ज्यादा से ज्यादा सीटों की मांग करती मगर विधानसभा चुनाव में असफल होने के बाद नीतीश और लालू अब कांग्रेस को अपने इशारों

पर नचायेंगे! दिगर बात है कि जब से विपक्षी गठबंधन इंडिया बनाया गया है, तब से यह आम धारणा थी कि नीतीश कुमार को इसका संयोजक बनाया जाएगा। मगर ऐसा नहीं हुआ और उन्हें पूरी तरीके से साइड लाइन कर दिया गया। हालांकि 2024 में विपक्ष का नेतृत्व नीतीश कुमार करते, तो नीतीश के सामने चुनौतियां बहुत बड़ी होती। क्योंकि नीतीश को हाल ही में महिलाओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणी के लिए आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। वही बिहार के मुख्यमंत्री उस समय एक और विवाद में फंस गए जब उन्होंने बिहार विधानसभा के अंदर पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को अपमानित किया। बीजेपी और मांझी ने नीतीश कुमार के कृत्य को 'दलित विरोधी' करार दिया। और तो और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद भी नीतीश के लिए एक बड़ी चुनौती हैं, क्योंकि नेतृत्व के मुद्दे पर जनता दल यूनाइटेड और राजद के बीच आंतरिक दरार चल रही है। राजद लंबे समय से तेजस्वी यादव को राज्य के अगले सीएम के रूप में पेश करने की कोशिश कर रहा है, जिससे नीतीश कुमार काफी असहज हैं। बिहार के मुख्यमंत्री जानते हैं कि तेजस्वी को सत्ता सौंपने के किसी भी कदम से जनता दल यूनाइटेड में विभाजन हो जाएगा।

बहरहाल, 6 दिसम्बर की मिटिंग टलने के बाद 17 दिसम्बर की तारीख तय की गई, वह भी नहीं हुई तो 19 दिसम्बर का दिन तय किया गया। राष्ट्रीय राजधानी के अशोक होटल में हुई इस बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, पार्टी नेता राहुल गांधी और संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, जनता दल (यू) से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पार्टी अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, तृणमूल कांग्रेस से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और पार्टी महासचिव अभिषेक बनर्जी, राष्ट्रीय जनता दल से लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार तथा शिवसेना (यूबीटी) से उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे बैठक में शामिल थे। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और पार्टी महासचिव रामगोपाल यादव, द्रमुक से तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन और वरिष्ठ नेता टी आर बालू, नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला, पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) की प्रमुख महबूबा मुफ्ती, राष्ट्रीय लोक दल के अध्यक्ष जयंत चौधरी, अपना दल (के) से कृष्णा पटेल एवं पल्लवी पटेल और कई अन्य नेताओं ने बैठक में भाग लिया। विपक्षी गठबंधन 'इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इन्क्लूसिव अलायंस' की दिल्ली बैठक में ये फैसला किया गया कि जनवरी, 2024 के दूसरे हफ्ते तक सीट बंटवारे को अंतिम रूप देना है। इस बैठक में ये भी तय किया गया कि प्रधानमंत्री पद के चेहरे के बारे में फैसला चुनाव में जीत के बाद होगा। हालांकि, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने विपक्षी गठबंधन की ओर से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में दलित चेहरे के तौर पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम का प्रस्ताव दिया। बैठक में कुल 28 दलों के नेता शामिल हुए। बैठक के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे

नरेन्द्र मोदी

ने संवाददाताओं से कहा, कि गठबंधन की आज चौथी बैठक में 28 दलों के नेताओं ने हिस्सा लिया। खुशी की बात है कि सभी ने एक होकर यह फैसला किया कि आगे किस तरह से मिलकर काम करना है। उन्होंने कहा कि सभी दलों ने 8-10 जनसभाएं करने का फैसला किया। खड़गे ने कहा कि पहले प्रदेश स्तर पर सीटों के तालमेल पर बात होगी और अगर कोई मुद्दा आया, तो राष्ट्रीय स्तर पर बात होगी। प्रधानमंत्री पद के चेहरे से जुड़े सवाल पर खड़गे ने कहा कि पहले जीत के आना है, इसके बाद इस बारे में बात होगी। उन्होंने कहा कि हम पहले जीतने की कोशिश करेंगे, उसके बाद सांसद लोकतांत्रिक ढंग से फैसला करेंगे।

बिडम्बना है कि इंडिया एलायंस की चौथी इस मिटिंग में भी सीटों को बंटवारा नहीं हो सका। अब ये समझने की जरूरत है कि सीटों के बंटवारे का मसला कितना गंभीर है। सीटों के बंटवारे का मसला का विपक्षी गठबंधन इंडिया के बिखराव की वजह बनने जा रहा है, या सिर्फ टकराव का मुद्दा भर है? क्या विपक्षी दलों के नेता आपस में मिलजुल कर टकराव खत्म कर पाएंगे? दूसरी ओर अखिलेश यादव सीट बंटवारे को लेकर बात फाइनल होने तक कांग्रेस के साथ दूरी बनाए रखना चाहते हैं। इसके पीछे वजह मध्य प्रदेश चुनाव के दौरान खुलकर सामने आई दोनों दलों की तल्खी को बताया जा रहा है। सपा और कांग्रेस अगर साथ-साथ नजर आते हैं और मध्य प्रदेश जैसे हालात बनते हैं तो सपा को ये आशंका है कि उसे नुकसान हो सकता है। सपा लोकसभा चुनाव में किसी अगर-मगर जैसे हालात के साथ नहीं उतरना चाहती और यही वजह है कि पार्टी तब तक कांग्रेस के साथ खड़े होने से परहेज करना चाहती है जब तक सीटों पर बात फाइनल नहीं हो जाता। वही विदित हो कि 2018 में देखा जा चुका है कि पांचों राज्यों में हार के बावजूद बीजेपी 2019 में बेहतरीन प्रदर्शन के साथ सत्ता में शानदार वापसी करने में सफल रही। इस बार तो जोश पहले से ही हाई है। ऐसे में अपना-अपना अस्तित्व बचाने की जितनी फिक्र क्षेत्रीय दलों को है, कांग्रेस नेतृत्व को भी निश्चित रूप से होगी। सिर्फ इसलिए नहीं कि सीटें कम हो जाने से विपक्षी खेमे की राजनीति करना भी मुश्किल हो जाएगा। वही अरविंद केजरीवाल ने भले ही पीएम पद के लिए मल्लिकार्जुन के नाम पर हामी भरी हो किन्तु राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को अभी से बताने लगे हैं कि उत्तर भारत में तो अब आम आदमी पार्टी ही सबसे बड़ा विपक्षी दल है। देखा जाये तो उत्तर और दक्षिण भारत में फर्क करने वाली राजनीति को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ही बढ़ावा दिया है। पहले तो दक्षिण भारत के नेताओं का हिंदी विरोध से ही काम चल जाता था, फिर सनातन धर्म को लेकर विवाद खड़ा करने की कोशिश होने लगी। अब तो उत्तर भारत के लोगों को 'अनपढ़' बताकर बयानबाजी होने लगी है। अब विपक्षी गठबंधन इंडिया में मुख्य तौर पर टकराव के दो ही मुद्दे हैं-एक प्रधानमंत्री पद पर दावेदारी और दूसरा सीटों का बंटवारा। कांग्रेस जब तक सीटों के बंटवारे पर समझौते को राजी नहीं होगी, क्षेत्रीय दलों के नेता नहीं मानने वाले, चाहे राहुल गांधी उनकी विचारधारा को लेकर कितने भी बयान क्यों न देते रहें। जब तक एक सीट पर बीजेपी के खिलाफ एक उम्मीदवार की रणनीति अपनायी नहीं जाती, बीजेपी का बाल भी बांका नहीं होने वाला है! ●

विपक्ष के लिए भाजपा की पीआर मशीन से मुकाबले का वक्त यही है सही!

● तारिक अनवर/महेश कुमार

अगर केंद्र में कांग्रेस की सरकार होती तो उत्तराखंड में इतना बड़ा बचाव अभियान (सुरंग ढहने से 17 दिनों से फंसे 41 मजदूरों को बचाने के लिए जो चला) चलाना संभव नहीं होता। बिहार में कुछ समुदायों को छोड़कर हर तीसरा या चौथा व्यक्ति राजनीति पर अनौपचारिक बातचीत के दौरान यही राय रखता है। वे उस काम के लिए भी उन्हें श्रेय देते हैं जो उनकी सरकार ने नहीं किया है। दिलचस्प बात यह है कि जिन मतदाताओं को सरकार के कार्यों की समीक्षा करनी चाहिए और सत्ताधारियों की गलतियों को उजागर करना चाहिए, वे सरकार की कथित विफलताओं का बचाव करते नजर आते हैं। इससे पता चलता है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की जनसंपर्क (पीआर) मशीनरी लगातार मोदी की कथित अजेयता को बढ़ावा देने की दिशा में काम कर रही है - एक ऐसा इलाका जहां विपक्षी दल लगातार संघर्ष करते नजर आते हैं या बुरी तरह पिछड़ रहे हैं। रणनीतिक संदेश, सरकार समर्थक समाचार प्रसारण और अपने कार्यकर्ताओं को संगठित करने के माध्यम से, भगवा पार्टी को कई लोग किसी भी तरह के संकट को अवसर में बदलने के लिए जाने जाते हैं। जब लोगों की राय का तथ्यों के साथ विरोधाभास होता है, तो वे अपनी जानकारी की प्रामाणिकता पर जोर देने लगते हैं क्योंकि उनके स्रोत टीवी समाचार चौनल, व्हाट्सएप पर संदेशों की झड़ी और पार्टी का स्थानीय नेतृत्व होता है। दूसरी ओर, विधानसभा और लोकसभा चुनावों में लगातार हार के बावजूद, विपक्ष की जमीन पर कोई उपस्थिति नजर आ नहीं है। यहां तक कि मौजूदा क्षेत्रीय दल भी एक मजबूत और प्रभावी विचार पेश करने में असमर्थ हैं। बिहार के दरभंगा जिले के सोनकी गांव के रहने वाले मदन मंडल कहते हैं कि महंगाई आसमान छू रही है और महंगाई नियंत्रण से बाहर है, लेकिन लोगों की आमदनी भी बढ़ गई है। स्थानीय बाजार में सब्जियां बेचने वाले 55 वर्षीय व्यक्ति का कहना है कि, इस सब के परिणामस्वरूप, कोई भी भूखा नहीं सोता। लेकिन 10 साल पहले ऐसा नहीं था। वे खुद रोजाना 200 रुपये से अधिक भी कमाने के लिए संघर्ष करते हैं और, इनका खुद का मानना है कि यह आय गुजारा करने के लिए काफी नहीं है। फिर भी, उनका मानना है कि मूल्य वृद्धि अपरिहार्य है क्योंकि सरकार देश को समृद्ध और मजबूत बनाने के लिए कठोर निर्णय ले रही है। कमरतोड़ महंगाई के बावजूद, वे बड़े आत्मविश्वास के साथ कहते हैं-जो आंकड़ों से अनभिज्ञ और बिना किसी दिलचस्पी के कहते हैं कि हर जगह समृद्धि है। गांवों में जाओ और लोगों से बात करो। वे अब अच्छा भोजन खरीदने में सक्षम हैं। मांसाहारी भोजन अब विलासिता नहीं है, देश के भीतरी इलाकों में भी यह सच है, जहां ज्यादातर दिहाड़ी मजदूर रहते हैं। आप लगभग हर घर के बाहर मोटरसाइकिलें खड़ी देखेंगे। जब उनसे पूछा गया कि इस तरक्की के बावजूद लोग अमानवीय हालात में आजीविका कमाने के लिए बड़े शहरों में पलायन करने पर क्यों मजबूर हैं, तो उन्होंने कहा कि, सरकार हमें मुफ्त राशन देती है। हमें घरों का निर्माण (प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत) मौद्रिक सहायता मिलती है। हर जगह शौचालयों का निर्माण किया गया है। परिवहन आसान हो गया क्योंकि राज्य के दूरदराज के गांवों में भी अच्छी सड़कें हैं। जब यह बताया गया कि ये योजनाएं पिछली सरकारों से चली आ रही हैं और एक कल्याणकारी राज्य में यह उनका अधिकार है, तो उन्होने कहा कि पहले यह अप्रभावी ढंग से लागू था। वर्तमान सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि ऐसी योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचे। हालाँकि, बहुत कुछ करने की जरूरत है क्योंकि हर जगह भ्रष्टाचार है।

दिलचस्प बात यह है कि मतदाता

राज्य में भौतिक बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए नीतीश कुमार सरकार द्वारा किए गए कार्यों को नजरअंदाज करते हुए केंद्र को श्रेय दे रहे हैं। सहरसा के रहने वाले दिलीप मंडल, जो राजस्थान के जयपुर में एक कढ़ाई कार्यशाला के मालिक हैं, राजनीतिक रेवड़ियाँ (सरकार द्वारा गरीबों को वित्तीय या सामग्री हस्तांतरण) बांटने का जोरदार विरोध करते हैं। लेकिन साथ ही, वह महंगी बिजली और उज्ज्वला योजना में सब्सिडी बंद होने की भी शिकायत करते हैं। रेवड़ियों के खिलाफ प्रचार युद्ध सबसे पहले भाजपा और उसके सहयोगियों ने शुरू किया था, जिसमें यह दावा किया गया था कि योजनाओं के जरिए धन या सामग्री का वितरण वित्तीय रूप से अस्थिर हैं और अनिवार्य रूप से आर्थिक संकट का कारण बनता है। हालांकि भगवा पार्टी ने हाल के चुनावों में लोगों को लुभाने और जीतने के लिए बड़े पैमाने पर इस तरह की रेवड़ियों की घोषणा की है, लेकिन उसने सफलतापूर्वक इसके खिलाफ एक कहानी भी तैयार कर ली है। विपक्षी दल के कार्यकर्ता इस सार्वजनिक चर्चा का मुकाबला करने में विफल रहे हैं। बिहार पुलिस के पूर्व सब-इंस्पेक्टर ललन सिंह कहते हैं कि विपक्षी गठबंधन बिहार में जाति जनगणना का लाभ उठाने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन जनगणना के आधार उसके पास जनता को देने के लिए कुछ भी नहीं है। उनका मानना है कि, लोगों को राज्य या देश की आबादी में उनके हिस्से के बारे में बताने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, जब तक कि यह व्यक्तियों के जीवन पर (सकारात्मक तरीकों से) प्रभाव नहीं डालता है,श्श उन्होंने तर्क दिया कि इंडिया गठबंधन को संख्यात्मक रूप से महत्वपूर्ण ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) और ईबीसी (अत्यंत पिछड़ा वर्ग) मतदाता जो षकिसी भी अन्य क्षेत्रीय दलों की तुलना में मोदी पर भरोसा करते हैं, पर जीत हासिल करने के लिए बहुत कुछ करना होगा।

क्या नितीश कुमार को बदनाम करना अब पाखंड नहीं माना जाता है, जिन्हें कभी विकास पुरुष के रूप में जाना जाता था, केवल इसलिए कि उन्होंने भाजपा से नाता तोड़ लिया? वह इससे असहमत हैं और कहते हैं, उन्होंने लोगों के जनादेश का अनादर किया। जब उनसे मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में जनादेश के प्रति भाजपा द्वारा प्रदर्शित इसी तरह के अनादर पर उनकी राय के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने अस्पष्ट रूप से जवाब दिया, अब यह सब इतिहास है। समस्तीपुर जिले के मगरदही गांव के निवासी सहदेव पासवान कहते हैं कि लोग मोदी, मोदी का जाप सिर्फ

इसलिए कर रहे हैं क्योंकि विपक्षी नेता या उनके कार्यकर्ता अपने निर्वाचन क्षेत्रों में कहीं नहीं दिख रहे हैं। उनका कहना है कि, भाजपा का मुकाबला करने के मामले में विपक्ष की जनता में पहुंच और पीआर मशीनरी बेहद कमजोर है। हालांकि वे खुद भाजपा के समर्थन वाले एनडीए को अपना समर्थन देंगे क्योंकि उनके नेता (दिवंगत रामविलास पासवान) गठबंधन के साथ थे, उन्होंने खुलासा किया, वे ईबीसी श्रेणी बनाने और उनके उत्थान के लिए कल्याणकारी कार्यक्रम शुरू करने के लिए सीएम नीतीश की प्रशंसा करने में संकोच नहीं करते हैं। वे कहते हैं कि, अगर विपक्षी दल और उसके कार्यकर्ता तुरंत मैदान में उतरें और हर गांव और ब्लॉक स्तर पर सावधानीपूर्वक योजना के साथ घर-घर अभियान शुरू करें, तभी वे सोशल इंजीनियरिंग के पक्ष में होने के बावजूद मोदी को हराने की स्थिति में आ सकते हैं। दरभंगा के बरुआरा गांव में 10 एकड़ जमीन के मालिक अरुण झा भी कहते हैं कि बिहार सरकार द्वारा की गई जाति जनगणना का चुनावी नतीजों पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा क्योंकि 2024 का चुनाव पार्टी या व्यक्तियों के दबदबे पर लड़ा जाएगा। उनके मुताबिक, जद(यू), राजद, कांग्रेस और वाम दलों को सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को रोकने और राम मंदिर निर्माण के नाम पर प्रचार को रोकने में मजबूत प्रचार रणनीति अपनानी होगी। विपक्ष के मुद्दे में कृषि, बेरोजगारी, महंगाई, भारतीय क्षेत्र में चीनी घुसपैठ, जातिगत अत्याचार आदि के मुद्दे शामिल होने चाहिए। उनके अनुसार, चुनावी मुद्दों में कृषि के मुद्दे प्रमुख होने चाहिए क्योंकि राज्य में किसान दयनीय स्थिति में हैं। डीएपी उर्वरक की भारी कमी के कारण, किसानों को इसे काले बाजार से अत्यधिक कीमतों पर खरीद रहे हैं। चूंकि राज्य में कोई एपीएमसी (कृषि उपज बाजार समिति) नहीं है, इसलिए किसानों को ऐसा करना पड़ता है। गेहूं और धान को स्थानीय खरीदारों को औने-पौने दामों पर बेचते हैं और वे उसे पंजाब और हरियाणा में एपीएमसी में ऊंचे दामों पर बेच देते हैं, लोग अपनी कृषि उपज, पैक्स (प्राथमिक कृषि ऋण सोसायटी) को नहीं बेचते हैं। क्योंकि उन्हें तत्काल भुगतान की जरूरत होती है-जो उन्हें केवल स्थानीय खरीदारों से मिलता है। 65 वर्षीय झा ने कहा कि, लेकिन विपक्ष ऐसे मुद्दों को भुना सकता है, जो सीधे तौर पर लोगों को प्रभावित कर रहे हैं, यह तभी हो सकता है जब वे स्थिति को मोड़ने के लिए पूरी ताकत से मैदान में उतरें। ड्राइंग रूम की राजनीति अब काम नहीं करने वाली है। ऐसा क्यों है कि मतदाता अतिराष्ट्रवाद, सांप्रदायिकता और देश के विकास की आंशिक रूप से सच्ची कहानियों के बारे में बात कर रहे हैं, जबकि वे ऊंची कीमतों के इस युग में अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं? ऐसा क्यों है? क्या वे कोविड के दौरान कुप्रबंधन के लिए सरकार से सवाल करते हैं? वे मूल्य वृद्धि पर सरकार का बचाव क्यों कर रहे हैं, यह कहते हुए कि यह अपरिहार्य है? ऐसा क्यों है कि बेरोजगारी पर सरकार से सवाल

पूछने के बजाय, लोग खुद यह कहकर बचाव कर रहे हैं कि इसे समायोजित करना असंभव है क्योंकि सरकारी क्षेत्र में इतनी बड़ी संख्या में लोग काम करते हैं? झा के अनुसार, इसका एक उत्तर यह है कि उन्हें (मतदाताओं को) दैनिक आधार पर सरकार समर्थक प्रचार खिलाया जाता है और विपक्ष इसका मुकाबला करने के लिए जमीन पर कहीं नहीं है। गया जिले के रहने वाले 54 वर्षीय किसान बैद्यनाथ यादव कहते हैं कि बिहार में ष्एम-वाई (मुस्लिम-यादव) समीकरणष अभी भी बरकरार है, लेकिन विपक्ष को गैर-यादव ओबीसी और दलित मतदाताओं के बीच काम करने की जरूरत है जो इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। उनका दावा है, श्बीजेपी एम-वाई ब्लॉक का मुकाबला करने के लिए मतदाताओं के इन हिस्सों का सफलतापूर्वक ध्रुवीकरण कर रही है। बिहार में हुई नवीनतम जाति जनगणना के अनुसार, राज्य की आबादी में मुस्लिम 17.7 प्रतिशत हैं, जबकि यादव 14.27 प्रतिशत हैं। अन्य प्रमुख समुदाय हैं कुशवाह (4.21 प्रतिशत), ब्राह्मण (3.65 प्रतिशत), राजपूत (3.45 प्रतिशत), मुसहर (3.8 प्रतिशत), कुर्मी (2.87 प्रतिशत), भूमिहार (2.86 प्रतिशत), मल्लाह उर्फ साहनी (2.60 प्रतिशत) और बनिया (2.31 प्रतिशत) हैं।

☞ **उतने प्रभावशाली नहीं जितना हमें होना चाहिए :-** यहां तक कि राज्य में इंडिया गठबंधन के घटक भी स्वीकार करते हैं कि वे अपने मतदाताओं तक पहुंच बनाने में उतने प्रभावी नहीं हैं जितना उन्हें होना चाहिए। "यह सच है कि जमीन पर हमारी उपस्थिति उतनी मजबूत नहीं

है, लेकिन जल्द ही हम पूरी ताकत के साथ हर पंचायत और वार्ड में होंगे। हम 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले कोई कसर नहीं छोड़ेंगे", जेडी (यू) प्रवक्ता नीरज कुमार कहते हैं, जो बिहार विधान परिषद के सदस्य भी हैं। वह स्वीकार करते हैं कि सोशल मीडिया पर चुनावी लड़ाई से चुनाव नहीं जीतने जा रहे हैं, लेकिन साथ ही, वह अपने राज्य में मतदाताओं के बीच अपनी पार्टी की अनुपस्थिति से इनकार करते हैं। उन्होंने कहा कि, हम अपने युवाओं को आरक्षण और संविधान विरोधी ताकतों के बारे में जागरूक करने और देश में पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और शोषित समुदायों की आवाज को दबाने के खिलाफ चर्चा करने के लिए श्भीम संवादश आयोजित कर रहे हैं। यह प्रयास इतना सफल और प्रभावशाली है कि भाजपा को इसके जवाब में अंबेडकर समागम लॉन्च करना पड़ा लेकिन यह पूरी तरह से फ्लॉप शो है। उनका कहना है कि संवाद उन सामाजिक मुद्दों को उठाकर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का मुकाबला करने का एक प्रयास है जो लोगों के दैनिक जीवन को प्रभावित करते हैं। राष्ट्रीय जनता दल (राजद), कांग्रेस और वामपंथी दलों के साथ गठबंधन में बिहार पर शासन कर रही जद (यू) भी केंद्रीय योजना, बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना का नाम कथित तौर पर बदलने को लेकर भाजपा सरकार पर आक्रामक रूप से निशाना साध रही है। यह योजना अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए छात्रावास के निर्माण के लिए थी। वे कहते हैं, हम लोगों को यह बताने जा रहे हैं कि केंद्र, जो खुद को दलित मुद्दों का चैंपियन होने का दावा करता है, ने 2022-23 के दौरान इस योजना के तहत बिहार को एक पैसा भी नहीं दिया है।

केंद्र की बीजेपी सरकार ने बिहार के दलित नेता और देश के तत्कालीन उपप्रधानमंत्री बाबू जगजीवन राम के नाम पर बनी योजना को अन्य दो केंद्र प्रायोजित योजनाओं के साथ मिला दिया है। इसे अब प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना का नाम दिया गया है। अपनी प्रचार रणनीति के हिस्से के रूप में, जद (यू) गांवों में पर्चे भी बांट रहा है-जिसमें समाज के हर वर्ग के लिए राज्य सरकार के काम और उसके प्रभावों पर प्रकाश डाला गया है। कुमार का आरोप है कि भाजपा अपने चुनाव अभियान के लिए सरकार को उपलब्ध सार्वजनिक डेटा का उपयोग कर रही है। "यह एक अनैतिक प्रथा है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वे आधार को हर योजना से जोड़ने के लिए इतने उत्सुक हैं। पिछले कुछ वर्षों में उन्होंने जो भारी धनराशि अर्जित की है, उससे उनके कार्यकर्ताओं को निर्वाचन क्षेत्रों में मौजूद रहने और काम करने में

मदद मिलती है। लेकिन हम इतना नीचे नहीं गिर सकते हैं। हम पूरी ताकत के साथ सत्ताधारियों से मुकाबला करेंगे, आम जनता के लिए अपने काम को उजागर करेंगे और कभी भी किसी अनैतिक आचरण में शामिल नहीं होंगे।

कहा जाता है कि भगवा पार्टी ने मध्य प्रदेश में हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनाव में सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों का सीधा प्रचार किया था। कथित तौर पर इसने अपने 40 लाख कार्यकर्ताओं तक पहुंचने के लिए राज्य सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों का डेटाबेस वितरित किया। कुमार स्वीकार करते हैं कि इंडिया गठबंधन में अंदरूनी कलह है और अगर विपक्षी एकता 2024 में भाजपा को हराना चाहती है तो इससे चतुराई से निपटना होगा। उनके पास अपने ही नेताओं के लिए एक संदेश है :- उन्हे दूसरी और तीसरी पंक्ति के नेताओं को आत्म-प्रचार बंद करना चाहिए, अपने संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में जाना चाहिए और राज्य सरकार के कार्यों के बारे में प्रचार करना चाहिए। तभी हम जीत हासिल कर पाएंगे।श्श भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीआई) के विधायक संदीप सौरव भी स्वीकार करते हैं कि विपक्षी गठबंधन के पास अभी तक कोई परिभाषित प्रचार रणनीति नहीं है, भले ही केंद्र में मोदी सरकार के 10 वर्षों के बाद सत्ता विरोधी लहर इतनी मजबूत नहीं है कि इंडिया गुट उस पर काबू पा सके। सौरव के अनुसार, जबकि भाजपा ने 2024 के लिए अपना चुनावी युद्ध कक्ष तैयार कर लिया है, यहां तक कि अपनी प्रचार रणनीति पर विचार-विमर्श करने और उसे अंतिम रूप देने के लिए इंडिया गठबंधन की पहली बैठक भी नहीं हुई है। इसके अलावा, वे कहते हैं, उनकी पार्टी एक सरकार की सहयोगी है-(बिहार में जेडी-यू के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार)-जिसके ष्शराबबंदी, सरकारी शिक्षकों के मुद्दे आदि जैसे दोषपूर्ण फैसले उनके लिए कड़ी चुनौती पेश कर रहे हैं। जब पार्टी, नेता और कार्यकर्ता प्रचार के लिए लोगों के पास जाते हैं तो उन्हें बचाव करना होता है और उनसे निपटना होता है। वे कहते हैं कि, नीतीश कुमार सरकार ने शराब के व्यापार और इसके सेवन पर प्रतिबंध लगा दिया। लेकिन यह निर्णय न केवल अपने उद्देश्य में विफल रहा, बल्कि आत्मघाती साबित हुआ। इससे अवैध उत्पादन, तस्करी और व्यापार को बढ़ावा मिला और वह भी घटिया और जानलेवा शराब का जरिया बना। जो लोग पहले इसका सेवन कर रहे थे, वही अभी भी जारी रखे हुए हैं। शराबबंदी से एकमात्र अंतर इसकी कालाबाजारी का आया।

इसके अलावा, इसने पुलिस को अत्याचार में शामिल होने और जिसे चाहें उसे फंसाने का लाइसेंस दे दिया। निषेधाज्ञा के अलावा, शिक्षकों की नियुक्ति और संविदा शिक्षकों को राज्य कर्मचारियों के अधिकार देने के तरीके को कैसे नियमित किया गया है, इससे राज्य में सत्तारूढ़ दलों के लिए स्थिति और खराब हो सकती है। उनके अनुसार, सरकार ने शिक्षकों की नियुक्ति के नाम पर बेरोजगार युवाओं को धोखा दिया है। बीपीएससी (बिहार लोक सेवा आयोग) द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा के माध्यम से नियुक्त किए गए अधिकांश शिक्षक मौजूदा शिक्षक हैं। इसका मतलब है, रिक्त पदों पर कम नई नियुक्तियाँ की गई हैं। दूसरी चुनौती, जो संभावित रूप से बिहार में इंडिया गठबंधन की संभावनाओं को प्रभावित कर सकती है, वह बताते हैं कि हालांकि सरकार ने कई विरोध प्रदर्शनों के बाद, मौजूदा शिक्षकों को राज्य कर्मचारियों का दर्जा देने की लंबे समय से चली आ रही मांगों को स्वीकार कर लिया है, लेकिन उनके अधिकार छीन लिये हैं। उन्हें अब अपने संगठन या यूनियन बनाने की अनुमति नहीं है; उनकी मौजूदा यूनियनों की मान्यता रद्द कर दी गई; वे सोशल मीडिया पर सरकार के खिलाफ कुछ भी नहीं लिख सकते हैं; उन्हें सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक स्कूलों में रहना होगा। भले ही कक्षाएं शाम 4 बजे खत्म हो जाएं; और गर्मी की छुट्टियों के दौरान भी उन्हें कोई छुट्टी नहीं मिलेगी। सौरव कहते हैं कि, कम से कम बिहार में शिक्षक समुदाय को हल्के में नहीं लिया जा सकता है। राज्य के लगभग हर गांव में अच्छी-खासी संख्या में शिक्षक हैं, जो चुनाव में काफी अहम भूमिका निभाते हैं। उनकी नाराजगी से सरकार को अपूरणीय क्षति हो सकती है। हम बार-बार इन चिंताओं को नीतीश जी की जानकारी में ला रहे हैं, लेकिन वह अपने नौकरशाहों के अलावा कभी किसी की नहीं सुनते हैं।श्श ऐसा कहने के बाद, उन्होंने निष्कर्ष निकाला, मोदी सरकार के खिलाफ नाराजगी और सत्ता विरोधी लहर है और इंडिया गठबंधन लोगों को अपने पक्ष में मतदान करने के लिए मनाने की पूरी कोशिश करेगा।

☞ **बीजेपी को हराने की अपनी ताकत पहचानें** :- चुनावी रणनीतिकार से राजनीतिक कार्यकर्ता बने प्रशांत किशोर का कहना है कि आप भाजपा या किसी भी पार्टी को तब तक नहीं हरा सकते, जब तक आप उनकी ताकत को नहीं समझते हैं। भाजपा की ताकत क्या है? यह आवश्यक रूप से मोदी या अमित शाह या आरएसएस नहीं है। वे चार चीजों के कारण चुनाव जीत रहे हैं: एक, उनका वैचारिक आधार-जो हिंदुत्व है; दो, उग्र या नव-राष्ट्रवाद, जिसे मोदी ने हर सभा में यह दोहराकर एक अतिरिक्त जोर के साथ जोड़ा कि हमारे आने के बाद से भारत विश्वगुरु बन गया है, जी-20 की मेजबानी के आसपास पीआर अभ्यास और महान शो के माध्यम से उन्होंने तीन, प्रत्यक्ष लाभार्थी- जैसा कि हिंदी में कहा जाता है श्रमार्थी; चौथा, संगठनात्मक और वित्तीय ताकत,श्श जन सुराज अभियान के संस्थापक प्रमुख बताते हैं, जिनकी कंपनी ने 2014 में भाजपा को सत्ता में लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उनका कहना है कि अगर कोई भी गठबंधन, चाहे वह इंडिया हो या कोई और, जो भाजपा से मुकाबला कर रहा है, जब तक कि वह भगवा पार्टी को चार में से तीन मोर्चों पर नहीं हरा देता, उसके पास सत्ताधारी को सत्ता से बाहर करने का ज्यादा मौका नहीं है।● (साभार)

22 हजार बी.एड धारक शिक्षकों पर लटकी तलवार

के.के. पाठक के नये फरमान का प्राथमिक शिक्षक संघ कर रहा विरोध

● अमित कुमार

शिक्षा विभाग की अस्थिरता थमने का नाम नहीं ले रही। जहां पटना उच्च न्यायालय ने बिहार के 22 हजार बी.एड. डिग्री धारकों को सेवामुक्त कर दिया है तो दूसरी तरफ शिक्षकों पर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के.के. पाठक के फरमानों के वार रूक नहीं रहे और इसे लेकर बिहार प्राथमिक शिक्षक संघ ने के. के. पाठक के फरमानों को वापस लेने को लेकर चुनौती दे डाली है। इन तमाम घटनाओं के बीच माध्यमिक शिक्षा निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव ने राज्य के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों एवं सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना को आधिकारिक पत्र जारी करते हुए कहा है कि विभागीय वेबसाइट पर एचआरए के संदर्भ में मन्तव्य देने के लिए शिक्षकों को निर्देशित करें। दरअसल शिक्षा विभाग ने शिक्षकों को उनकी नियुक्ति स्थल के आसपास आवास दिलाने के लिए एक नीति तैयार की है। इस नीति के तहत हर हाल में हर शिक्षक को एचआरए लेकर रहना है। वही दूसरा विकल्प है कि विभाग उन्हें आवास मुहैया करायेगा। बता दें कि विभाग ने शिक्षकों को मकान उपलब्ध कराने के लिए निविदाएं भी आमंत्रित की थीं। जिनमें अच्छे खासे आवेदन भी आये। शिक्षा विभाग निजी मकान मालिकों से लीज पर आवास लेकर शिक्षकों को रेंट पर आवंटित करेगा और इस दिशा में शिक्षा विभाग मकान मालिकों से जल्दी ही एमओयू करेगा। ज्ञात हो कि एचआरए की बिहार में तीन कैटेगरी हैं। पटना में शिक्षकों को उनकी बेसिक सेलरी का 16 फीसदी एचआरए दिया जाता है। अन्य नगरीय निकायों में बेसिक सेलरी का आठ और ग्रामीण क्षेत्रों में बेसिक सेलरी का चार फीसदी हाउस रेंट दिया जाता है। सूत्रों के मुताबिक एक से पांच वर्ग के शिक्षकों की बेसिक सेलरी 25 हजार है। इसके हिसाब से इस वर्ग के शिक्षको को पटना में चार हजार, अन्य शहरी क्षेत्रों में दो हजार और ग्रामीण क्षेत्रों में एक हजार रुपये एचआरए देय होगा। सर्वाधिक एचआरएच कक्षा 11 और 12 वीं के शिक्षकों का होगा, जिनका पटना में एचआरए करीब 5120, अन्य शहरी क्षेत्रों में एचआरएस 2560 और ग्रामीण क्षेत्रों में 1280 रुपये होगा।

बहरहाल, शिक्षकों को आवास रेंट मुहैया कराने के साथ-साथ महिला शिक्षकों को स्कूटी चलाने के प्रशिक्षण के लोकलुभावन स्कीम के साथ शिक्षा विभाग कार्य करने को तैयार हुई है किन्तु इन सब के बावजूद बिहार शिक्षा विभाग

के अपर मुख्य सचिव के.के. पाठक ने शिक्षा विभाग के कर्मचारियों व शिक्षकों के लिए एक नया आदेश जारी किया है। जिसके तहत स्कूल टाइम में शिक्षकेतर कर्मी, शिक्षकों व टोला सेवकों की ड्यूटी चुनाव कार्य के लिए नहीं लगाई जाएगी। इन सभी की ड्यूटी शाम पांच बजे के बाद लगायी जायेगी। इस संबंध में के. के. पाठक ने सभी जिलों के डीएम को एक पत्र लिख आदेश जारी किया है। जारी आदेश पत्र में कहा गया है कि आवश्यकता होने पर शिक्षा विभाग के कर्मचारियों व शिक्षकों को चुनावी ड्यूटी पर लगाया जा सकता है। हालांकि चुनाव कार्य के लिए किसी भी विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों व शिक्षकेतर कर्मियों की ड्यूटी सुबह 9:00 बजे से शाम के 5:00 बजे तक नहीं लगायी जायेगी, यानी किसी भी कीमत पर विद्यालय की पढ़ाई बाधित ना हो। गौरतलब है कि 2024 में लोकसभा चुनाव है, जिसको लेकर तैयारियां शुरू हो गई है। निर्वाचन आयोग मतदाता सूची अपडेट करने में लगा हुआ है। इसके साथ ही बीते दिनों निर्वाचन विभाग ने राज्य के सभी विधानसभा क्षेत्रों में सहायक निर्वाचक निबंधक पदाधिकारियों (एइआरओ) की नियुक्ति की अधिसूचना जारी की है। इन पदाधिकारियों की जिम्मेदारी है कि मतदाता सूची की तैयारी में वह निर्वाचक निबंधक पदाधिकारी (आरइओ) का सहयोग करेंगे। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए के.के. पाठक द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि अक्सर यह देखा जाता रहा है कि शिक्षा विभाग के शिक्षकों, शिक्षकेतर कर्मियों व टोला सेवकों को चुनाव संबंधित कार्य यानी बीएलओ के कार्य में लगाया जा रहा है, साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि शिक्षा विभाग इस बात से भी पूरी तरह अवगत है कि बिना शिक्षा विभाग के कर्मियों के सहयोग के जिले में चुनाव का काम नहीं हो सकता है। इसलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए आपसे शिक्षा विभाग यह अनुरोध करता है कि यदि आप शिक्षा विभाग के शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मी व टोला सेवकों की ड्यूटी चुनाव कार्य के लिए लगाते हैं, तो यह ध्यान दें कि चुनाव कार्य के लिए ड्यूटी शाम 5:00 बजे के बाद ही लगायी जाई। इसके साथ ही जारी आदेश में यह भी कहा गया है कि किसी भी शिक्षक, टोला सेवक व कर्मियों की ड्यूटी प्रात: 9:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक नहीं लगायी जाये, ताकि किसी भी हालत में विद्यालय की पढ़ाई बाधित ना हो सके। साथ ही आदेश में कहा गया है कि चुनाव संबंधी कार्य शाम 5:00 बजे के बाद लिया जाये, क्योंकि चुनाव कार्य के लिए अतिरिक्त मानदेय दिया जाता है. इसलिए शिक्षक व कर्मियों से अतिरिक्त घंटे कार्य लिया जा सकता है। बता दें कि मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम सभी 243 विधानसभा क्षेत्रों में चलाया जा रहा है। इन पदाधिकारियों के मातहत ही सभी बूथ लेबल ऑफिसर काम करते हैं। निर्वाचन विभाग द्वारा की गयी गजट अधिसूचना में एइआरओ की जिम्मेदारी विभिन्न पदाधिकारियों को दी गयी है,

जिनमें प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी और नगरपालिका क्षेत्रों में कार्यपालक पदाधिकारी शामिल हैं। मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के बाद जब चुनाव की घोषणा होती है तो इन्हीं पदाधिकारियों को सहायक निर्वाचन पदाधिकारी के रूप में नामित किया जाता है। चुनाव में इन पदाधिकारियों को निर्वाचन पदाधिकारी (आरओ) को सहयोग करना होता है। दरअसल शिक्षा विभाग के कर्मियों और शिक्षकों की चुनाव कार्य के लिए अक्सर ड्यूटी लगाई जाती है। इस वजह से देखा गया है कि बच्चों की पढ़ाई बाधित होती है, क्योंकी शिक्षक स्कूल की टाइमिंग में ही चुनावी कार्य निपटाते हैं। ऐसे में वो बच्चों को सही ढंग से पढ़ा नहीं पाते हैं। वहीं इससे पहले जब जाति आधारित गणना के लिए शिक्षकों की ड्यूटी लगाई गई थी, तो के.के. पाठक ने एक आदेश जारी कर कहा था कि शिक्षकों की ड्यूटी सिर्फ गणना के लिए लगाई जाए। इसके अलावा शिक्षकों से कोइ भी प्रशासनिक कार्य नहीं कराया जाए। साथ ही गैर शैक्षणिक कार्यो में शिक्षकों की ड्यूटी लगाने से पहले इस बात का ध्यान रखना भी जरूरी है कि बच्चों की पढ़ाई बाधित नहीं हो।

गौरतलब हो कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के.के. पाठक के नये फरमान के बाद शिक्षक संघ उनसे नाराज है। इसी को लेकर बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के कार्यालय में अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ के राष्ट्रीय महासचिव कमलाकांत त्रिपाठी ने पत्रकारों से कहा कि शिक्षा विभाग बिहार सरकार के अपर मुख्य सचिव के.के. पाठक द्वारा प्रतिदिन जारी किये जा रहे तुगलकी फरमान और शिक्षकों

अध्यक्ष मनोज कुमार ने कहा कि आजादी के बाद से आज तक जितने भी अवकाश तालिका बने हैं सब में सारी प्रमुख छुट्टियां शामिल की गयी है। पहली बार ऐसा हुआ जब रविवार को भी सार्वजनिक छुट्टी होने के बावजूद छुट्टी घोषित किया गया है। विभाग द्वारा पहले तो सभी प्रधानाध्यापकों को शाम चार बजे के बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भाग लेना अनिवार्य किया गया। उसके बाद अब पांच बजे तक विद्यालय चलाने की बाध्यता की गयी है। ठंड का मौसम है, ऐसे में शाम पांच बजे अंधेरा हो जाता है। यातायात का साधन नहीं मिलता। महिला शिक्षकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। विशेष क्लास हेतु चार बजे के बाद बच्चे भी स्कूल में रुकने के लिए तैयार नहीं है और न ही अभिभावक अपने बच्चों को चार के बाद स्कूल में रुकने देना चाहते हैं। वही संघ के वरीय उपाध्यक्ष रामचंद्र डबास ने कहा कि बिहार में सरकार द्वारा निर्धारित नियमों और अधिनियमों का उल्लंघन हो रहा है, जिससे संपूर्ण राज्य में शैक्षणिक अराजकता फैलने की स्थिति उत्पन्न हो गयी है। बिडम्बना है कि के.के. के फरमान को तुगलकी

आने-जाने की अनुमति नहीं प्रदान की जाएगी। शिक्षकों ने स्कूल के आस-पास ही किराए पर मकान ले लिया है, इसका प्रमाण पत्र आगामी माह में मांगा जाएगा। उन्होंने कहा कि मैक्सिमम 15 किलोमीटर की दूरी से स्कूल आने की अनुमति दी जाएगी। इससे ज्यादा कि किसी भी हाल में नहीं। दिगर बात है कि बिहार के सरकारी स्कूलों में नियुक्त अतिथि शिक्षकों की टेंशन बढ़ गई है। बिहार के प्राथमिक से लेकर उच्च

को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य भर में 5440 अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति की गई थी। इसको लेकर जिलेवार स्कूलों की सूची जारी की गयी। जिन स्कूलों में विषयवार शिक्षकों की कमी थी, वहां संबंधित विषय में अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति की गयी, लेकिन अब इन शिक्षकों को हटाया जा रहा है, जिससे अतिथि शिक्षकों में बेचैनी बढ़ गयी है। वहीं अगर पटना जिला की बात करें तो यहां जिला शिक्षा कार्यालय द्वारा 243 अतिथि शिक्षकों की सेवा समाप्त करने को लेकर आदेश जारी किया गया है। इस संबंध में जिले के राजकीय, राजकीयकृत, प्रोजेक्ट और उत्क्रमित उच्च माध्यमिक स्कूलों के प्राचार्यों को पत्र लिखा गया है। अब गौर फरमाने वाली बात है कि अतिथि शिक्षकों को हटाए जाने के संबंध में पटना जिला शिक्षा पदाधिकारी अमित कुमार ने बताया कि बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा के माध्यम से नवचयनित शिक्षकों ने जिस विषय में योगदान दिया है, उस विषय के अतिथि शिक्षकों को नियमावली के अनुसार हटाया जाएगा। इधर, उच्चतर माध्यमिक अतिथि शिक्षक संघ ने प्लस टू अतिथि शिक्षक की जगह को रिक्त नहीं मनाने की मांग

प्राथमिक शिक्षक संघ की आंदोलन की तैयारी

(आज शिक्षा प्रतिनिधि)

पटना। बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ ने चेतावनी दी है कि शिक्षकों को पांच बजे शाम तक स्कूलों में रोके जाने का आदेश वापस नहीं होगा, तो आंदोलन किया जायेगा।

अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ के राष्ट्रीय महासचिव श्री कमलाकांत त्रिपाठी ने गुरुवार को यहां प्रेस कान्फ्रेंस में कहा कि शिक्षा विभाग ने अपने सभी अव्यावहारिक आदेश वापस नहीं लिये, तो 10 दिसंबर को होने वाले संघ की बैठक में बड़े आंदोलन का फैसला लिया जायेगा। बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ आजादी के पूर्व का संगठन है। इसे राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त है। बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के कार्यवाहक अध्यक्ष मनोज कुमार ने कहा कि आजादी के बाद से आज तक जितने भी अवकाश तालिका बने हैं, सब में सारी प्रमुख छुट्टियां शामिल की गयी हैं। पहली बार ऐसा हुआ जब रविवार को भी सार्वजनिक छुट्टी होने के बावजूद छुट्टी घोषित किया गया है एवं त्योहारो पर मिलने वाली छुट्टियो में कटौती की गई है। पहले तो सभी प्रधानाध्यापकों को संध्या चार के बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भाग लेना अधिकार अधिनियम में स्पष्ट कहा गया है कि एक शैक्षणिक सत्र में 1 से 5 वर्ग के लिए कुल 800 घंटा एवं वर्ग 6 से 8 के लिए के लिए प्रत्येक शैक्षणिक सत्र में शिक्षण कार्य हेतु

अनिवार्य किया गया। उसके बाद अब शाम पांच बजे तक विद्यालय चलाने की बाध्यता की गयी है। ठंड के मौसम में शाम पांच बजे अंधेरा हो जाता है। यातायात का साधन नहीं मिलने से महिला शिक्षकों को काफी परेशानी हो रही है। विशेष क्लास हेतु अपराह्न चार बजे के बाद बच्चे भी स्कूल में रुकने के लिए तैयार नहीं हैं और न ही अभिभावक अपने बच्चों को चार बजे के बाद स्कूल में रुकने देना चाहते हैं। 1000 घंटा निर्धारित किया गया है। संध्या पांच बजे तक विद्यालय का समय बढ़कर शिक्षा के अधिकार अधिनियम का उल्लंघन और पीड़ादायक है। अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ के वरीय उपाध्यक्ष रामचंद्र डबास ने भी अपनी बातें रखीं। बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के वरीय उपाध्यक्ष नुनुमणि सिंह, रामअवतार पांडेय एवं उपाध्यक्ष घनश्याम यादव भी थे।

की है। संघ ने कहा कि रिक्त नहीं मानते हुए मासिक पारिश्रमिक फिक्स कर सेवा 60 वर्ष करने की अनुशंसा सरकार करे। छह वर्ष हो चुका है, अब अतिथि शिक्षकों को हटाया जा रहा है। पहले 25 दिन के अनुसार पारिश्रमिक 25000 रुपये दिये जाते थे, लेकिन प्राचार्य द्वारा 20 या 22 दिन का ही कार्य दिखाया जा रहा है। वही दूसरी तरफ बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित 88 हजार शिक्षकों के स्कूलों में योगदान किये जाने की रिपोर्ट जिलों ने शिक्षा विभाग को भेज दी है। इन सभी शिक्षकों ने स्कूलों में बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया है। फिलहाल जिलों ने प्रत्येक शिक्षक के नाम और योगदान की तिथि के साथ ऑनलाइन रिपोर्ट विभाग को उपलब्ध करा दी है। आधिकारिक सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक शिक्षा विभाग ने भी करीब-करीब यह मान लिया है कि फिलहाल इससे अधिक नवशिक्षक शायद ही योगदान दें, क्योंकि योगदान के लिए जो शिक्षक रह गये हैं, उनमें अधिकतर करीब नियोजित शिक्षक हैं। दो से चार हजार ऐसे शिक्षक भी हैं जो दूसरी जगह त्यागपत्र देने गये हैं। दरअसल यह वह शिक्षक हैं जो पहले दूसरी जगह नौकरी करते थे। अपने पिछले संस्थान में त्यागपत्र और वहां से एनओसी लाने के बाद ही उन्हें विद्यालय अध्यापक के रूप में योगदान देना है। इसके अभाव में योगदान नहीं लिया जायेगा। फिलहाल ऐसे सभी शिक्षकों को 30 नवंबर तक योगदान देने के लिए कहा गया था। हालांकि सूत्रों के अनुसार नियोजित शिक्षक राज्यकर्मी के दर्जे का इंतजार कर रहे हैं। अगर उन्हें आसान शर्तों पर राज्यकर्मी का दर्जा मिल जाता है, तो संभव है कि वह विद्यालय अध्यापक के रूप में योगदान न करें। विभाग ने जिलों को निर्देश दिये थे कि जो शिक्षक योगदान कर चुके हैं, उसकी रिपोर्ट 26 नवंबर तक भेजने की बात कही गई थी। मालूम हो कि आयोग द्वारा एक लाख 20 हजार 336 शिक्षकों का चयन किया। इनमें एक लाख दस हजार ने ही औपबंधिक पत्र प्राप्त किया है। बहरहाल, बिहार में शिक्षक भर्ती के पहले चरण की बहाली को अभी कुछ दिन भी नहीं हुए थे कि शिक्षकों ने इस्तीफा देने का सिलसिला शुरू हो गया है। दूसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा से पहले ही पहले चरण के 50 से ज्यादा शिक्षकों ने नौकरी छोड़ दी है। शिक्षक बहाली के बाद अलग-अलग जिलों में शिक्षकों के इस्तीफा देने का सिलसिला जारी है। इस्तीफा देने वाले ज्यादातर नवनियुक्त शिक्षक उत्तर प्रदेश से आने वाले हैं। हालांकि बिहार से आने वाले कई शिक्षकों ने भी इस्तीफा दिया है।

अब तक जो आंकड़े सामने आए हैं उसके मुताबिक सबसे ज्यादा समस्तीपुर जिले में नवनियुक्त शिक्षकों ने इस्तीफा दिया है। समस्तीपुर जिले में अब तक 30 शिक्षक इस्तीफा दे चुके हैं। मुजफ्फरपुर में 17 नवनियुक्त शिक्षकों ने इस्तीफा दिया है जबकि बेगूसराय में 4 और मधुबनी में भी एक नवनियुक्त शिक्षक ने इस्तीफा दिया है। दरअसल, इन शिक्षकों की तरफ से इस्तीफा दिए जाने के बाद आधिकारिक तौर पर जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय की तरफ से सूचना भी जारी की गई है। मुजफ्फरपुर जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय की तरफ से जो जानकारी दी गई है कि जिन शिक्षकों ने इस्तीफा दिया है उनका चयन केंद्रीय विद्यालय के लिए हो गया है। इसी का हवाला देते हुए इन शिक्षकों ने बिहार में शिक्षक की नौकरी छोड़ी है। कुछ मामलों में शिक्षकों ने दूसरे किसी प्रतियोगिता परीक्षा में चयन हो जाने के कारण भी बिहार शिक्षक की नौकरी छोड़ दी है। बता दें कि केंद्रीय विद्यालय में चयन, दूसरे विभागों में नौकरी का मिलना और उत्तर प्रदेश से आने वाले शिक्षकों को बिहार शिक्षक की नौकरी रास नहीं आ रही है। यही वजह है कि अभ्यर्थी बेहतर विकल्प मिलने के बाद बिहार शिक्षक की नौकरी से इस्तीफा दे रहे हैं। फिलहाल बिहार के अलग-अलग राज्यों से इस्तीफा देने वाले शिक्षकों के आंकड़े अलग-अलग तौर पर सामने आ रहे हैं। संभव है कि शिक्षा विभाग इस्तीफा के बाद आने वाले दिनों में उन व्यक्तियों के बारे में आधिकारिक तौर पर जानकारी साझा करे। फिलहाल इस्तीफा के बाद शिक्षा विभाग की तरफ से कोई अधिकारी बयान देने को तैयार नहीं है। हालांकि बिहार में इस वक्त बीपीएससी की तरफ से शिक्षक बहाली का दूसरा चरण चल रहा है। एक तरफ जहां शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने के लिए बीपीएससी दूसरे चरण की परीक्षा का आयोजन कर रही है तो वहीं दूसरी तरफ पहले चरण में नियुक्ति के बाद योगदान करने वाले शिक्षकों के इस्तीफा से कई स्कूलों में पद खाली हो रहे हैं। शिक्षा विभाग से जुड़े सूत्रों के मुताबिक आने वाले दिनों में इस्तीफा देने वाले शिक्षकों की संख्या और ज्यादा बढ़ सकती है।

विदित हो कि अतिथि शिक्षकों के बाद बीएड डिग्री धारक प्राथमिक शिक्षकों का मामला कई महीनों से पटना उच्च न्यायालय में चल रहा था और अब पटना हाईकोर्ट का रिजर्व जजमेन्ट आ गया है। बिहार प्राथमिक शिक्षक पद पर पिछले 2 वर्षो से नियुक्त बीएड डिग्री धारक नियोजित शिक्षकों (छठे चरण) को नौकरी से हटाने का फैसला सुनाई है। पटना हाईकोर्ट ने कहा कि जो लोग डीएलएड होंगे, वही प्राथमिक शिक्षक बन सकते है। पहले सरकार ने इन्हें प्राथमिकता देने की बात कही थी। इसपर हाईकोर्ट ने कहा कि जो लोग डीएलएड डिग्री धारक होंगे, वही प्राथमिक शिक्षक बन पाएंगे। एक से पांच वर्ग तक के लिए 22 हजार नियोजित शिक्षक बहाल हुए थे वहीं प्राथमिक शिक्षक का कहना है कि अभी ऑर्डरशीट आया नहीं है। केवल अफवाह उड़ाया गया है। 2022 में छठे चरण में 42 हजार नियोजित शिक्षक बहाल हुए

थे। इसमें एक से पांच वर्ग तक के लिए 22 हजार नियोजित शिक्षक बहाल हुए थे। इनको सरकार द्वारा बहाली के दो वर्ष के अंदर ब्रिज कोर्स करवाना था। इसे बिहार सरकार ने अब तक नहीं करवाया है। सरकार को यह कोर्स नियुक्ति के दो वर्ष के अंदर कराना था। वही 2 दिसंबर को हाईकोर्ट ने बी.एड शिक्षकों के मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था। शिक्षक संघ का कहना है कि विगत 2 दिसंबर को हाईकोर्ट ने बी.एड शिक्षकों के मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। इसके बाद से बीएड योग्यता धारी शिक्षकों की सांसे अटकी हुई हैं। सभी शिक्षक कोर्ट के आदेश का इंतजार कर रहे थे, इसी बीच कोर्ट का फैसला आने के पूर्व ही सोशल मीडिया पर बीएड योग्यता प्राप्त शिक्षकों को नौकरी से हटा देने की बात वायरल हो गई हैं। इसकी जांच होनी चाहिए कि क्या मामला है। बीएड उम्मीदवारों को प्राथमिक शिक्षक के रूप नियुक्ति के लिए पात्र नहीं माना जा सकता है। बताया गया कि रिट याचिकाओं को इस निष्कर्ष के साथ स्वीकार किया जाता है कि 'एनसीटीई' द्वारा जारी अधिसूचना-28.06.2018 अब लागू नहीं है और बीएड उम्मीदवारों को प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं माना जा सकता है। कहने की जरूरत नहीं है कि सरकार द्वारा की गई गई नियुक्तियों पर दोबारा काम करना होगा और वर्ष 2010 की एनसीटीई की मूल अधिसूचना के अनुसार योग्य उम्मीदवारों को केवल उसी पद पर जारी रखा जा सकता है जिस पर उन्हें नियुक्त किया गया है। राज्य सरकार यह भी निर्णय लेगा कि क्या इस तरह के पुनर्कार्य पर रिक्त होने वाले पदों को प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र उम्मीदवारों से राज्य के पास उपलब्ध मेरिट सूची से भरा जाएगा। पटना हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देकर प्राइमरी क्लासेस को पढ़ाने के लिए बीएड डिग्रीधारियों को अयोग्य घोषित किया है। कोर्ट का कहना है कि प्राइमरी क्लासेस यानी कक्षा 1 से 5वीं तक के स्कूली बच्चों को को केवल डीएलएड वाले ही पढ़ा सकते हैं। इस फैसले के बाद सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या अब बिहार में 22 हजार बीएड शिक्षकों की नौकरी चली जाएगी? दरअसल, 6 दिसम्बर को पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश विनोद चंद्रन और जस्टिस राजीव राय की खंडपीठ ने प्राइमरी टीचर्स के लिए बैचलर ऑफ एजुकेशन (बीएड) डिग्री धारकों को किसी प्रकार की राहत नहीं दी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में पटना हाईकोर्ट ने बीएड डिग्रीधारियों को प्राइमरी स्कूलों में पढ़ाने के लिए सक्षम नहीं माना है। बेंच ने एक साथ तीन अलग-अलग मामलों पर सुनवाई के बाद अपना फैसला सुनाया है। कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 141 के तहत सुप्रीम कोर्ट के फैसले से खुद को बंधा हुआ बताया है और राज्य सरकार को इस फैसले का पालन करने के लिए कहा है। पटना हाईकोर्ट ने एनसीटीई की ओर से 28 जून 2018 को जारी अधिसूचना को कानूनी तौर पर गलत करार दिया है। उक्त अधिसूचना में प्राइमरी स्कूलों में पहली से 5वीं क्लास तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए बीएड डिग्री धारकों को योग्य माना गया था। पटना हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए स्पष्ट किया कि राज्य के प्राइमरी स्कूलों में बीएड डिग्री धारकों की नियुक्ति नहीं की जाएगी। इससे पहले सर्वोच्च न्यायलय ने 11 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने फैसला सुनाया था कि प्राथमिक विद्यालय के क्लास एक से पांच तक की शिक्षक नियुक्ति में बीएड उम्मीदवार को शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं माना जा सकता है। बता दें कि बिहार में छठे चरण की शिक्षक नियुक्ति 2021 में हुई थी। इस नियुक्ति प्रक्रिया के बाद पटना हाईकोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई थीं जिसमें बीएड पास अभ्यर्थियों को प्राइमरी स्कूलों में शिक्षक के पद पर नियुक्ति पर रोक लगाने की मांग की थी। इस मामले में राज्य सरकार ने एनसीटीई की तरफ से 2018 की एक अधिसूचना का हवाला देते हुए कहा था कि एनसीटीई ने बीएड पास अभ्यर्थियों को क्लास एक से पांच तक के शिक्षक पद पर नियुक्ति की मंजूरी दे दी है लेकिन अब कोर्ट ने सरकार की इस दलील को खारिज करते हुए बीएड पास अभ्यर्थियों को बड़ा झटका दे दिया है।

गौरतलब हो कि कोर्ट ने राज्य सरकार से कहा है कि छठे चरण में क्लास 1 से 5 तक के लिए जिन बीएड पास अभ्यर्थियों की नियुक्ति की गई है अब उन्हें नए सिरे से नियुक्ति प्रक्रिया का पालन करना होगा। कोर्ट ने सरकार एनसीटीई की तरफ से साल 2010 में जारी मूल अधिसूचना के मुताबिक उम्मीदवारों को नियुक्त करने के लिए कहा है। पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से यह भी कहा है कि जो शिक्षकों के पद खाली हुए हैं उसे कैसे भरा जाए, इसपर भी सरकार फैसला ले। 2021 और 2022 में प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्तियों से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए पीठ ने कहा कि 'ये कहने की जरूरत नहीं है कि, की गई नियुक्तियों पर फिर से काम करना होगा'। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या पटना हाईकोर्ट के फैसले के बाद 2020-21 में बहाल हुए करीब 22 बीएड शिक्षकों की नौकरी चली जाएगी? फिलहाल पटना हाईकोर्ट के घेरे में आने वाले बीएड शिक्षकों को घबराने की जरूरत नहीं है। वे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी ये नहीं बताया कि 11 अगस्त 2023 को प्राइमरी लेवल के लिए बीएड शिक्षकों पर आया फैसला कब से लागू होगा। कोर्ट का फैसला भविष्यलक्षी है या भूतलक्षी है? कोर्ट इसे जल्द ही स्पष्ट कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट में अर्नब घोष की याचिका पर सुनवाई होनी है, जिसमें उम्मीद की जा रही है कि कोर्ट इस फैसले को भविष्यलक्षी यानी फैसले की तारीख के बाद से लागू कर सकता है। अगर ऐसा होता है तो हाईकोर्ट को भी उस फैसले को मानना होगा और बीएड शिक्षकों की नौकरी बच जाएगी। इससे पहले मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने भी ऐसे ही मामलों में याचिकाकर्ताओं को सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करने के लिए कहा है।●

शिल्पकारों की बस्ती पर चला बुल्डोजर
मूर्तियां गढ़ने वाले अपनी तकदीर नहीं गढ़ सके

● **विजय विनीत**

ये तस्वीर शिल्पकारों की एक ऐसी बस्ती की है जिसे विकास की शर्त पर उजाड़ दिया गया और वहां रहने वाले शिल्पकारों को कड़ाके की ठंड में ठिठुरने के लिए छोड़ दिया गया। बनारस में रोहनिया-कैंट मार्ग सड़क के किनारे मूर्तियां गढ़ने वाले करीब पांच सौ फनकार कई पीढ़ियों से यहीं रह रहे थे। इन शिल्पकारों की यादें अब तहस-नहस हो गई हैं। अगर कुछ बचा है तो टूटे-फूटे मूर्तियों व पत्थर के टुकड़े और लंगड़ाकर चलता हुआ इतिहास। वो इतिहास जो अपने जख्मों को सहला रहा है। मानो आंसू बहाते हुए खुद पर हुए जुल्म की बेजुबां दास्तां सुना रहा हो। बनारस के चांदपुर में जीटी रोड के किनारे कई पीढ़ियों से मूर्तियों को गढ़ने वाले शिल्पकारों के करीब 87 परिवार रहा करते थे। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने सड़क चौड़ी करने के लिए इनकी झोपड़-पट्टियों को एक झटके में ही गिरा दिया। मूर्तिकार कृष्ण कुमार यहीं अपने परिवार के साथ रहते थे। 05 दिसंबर 2023 की सुबह उनके लिए एक दुख का पैगाम लेकर आई। वह सुबह सोकर जागे भी नहीं थे कि पुलिस और सरकारी मशीनरी बुल्डोजर लेकर पहुंच गई। वहां रहने वाले लोगों को जल्दी से अपना घर खाली करने का अल्टीमेटम दे डाला। थोड़ी ही देर में उनकी झोपड़-पट्टियां तोड़ी जाने लगीं। कुछ ही देर में टेंट और प्लास्टिक से बने घरों को मिट्टी में मिला दिया गया। शिल्पकारों की बस्ती ढहाने पहुंचे अफसरों का कहना था कि जिन स्थानों पर मूर्तियां गढ़ी जा रही थी वह जमीन सरकार की है और झोपड़-पट्टियों में अस्थायी घर बनाकर रहने वाले सैकड़ों लोग अवैध रूप से रह रहे थे।

☞ **ठंड में सिकुड रहे कला शिल्पी :-** 'न्यूजक्लिक' से बातचीत में कृष्ण कुमार कहते हैं, मैं सुबह सो रहा था तभी एक पुलिस वाला आया और उसने मुझे डंडा दिखाकर जल्दी से घर

खाली करने की धमकी दी। मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। बाद में उन लोगों ने मेरा घर गिरा दिया। बाद में हमें चांदपुर से करीब नौ किमी दूर लोहता रेलवे स्टेशन के नजदीक लखमीपुर गांव में एक निछद्‌म बगीचे में जाकर झोपड़ी लगाने का निर्देश दिया गया। हमें न तो किसी जमीन का पट्टा दिया गया और न ही झोपड़ी लगाने के लिए कोई आर्थिक मदद। सरकारी हुक्मरानों ने घर देने का वादा काफी पहले किया था, लेकिन आज तक हमें घर नहीं मिल सका। लखमीपुर में तीन बरस पहले भी शिल्पकारों को उसी बगीचे में छोटी-छोटी झोपड़ियां बनाने के लिए जगह दी गई थी। बाद में कुछ दबंगों ने जमीन को अपना बताते हुए शिल्पकारों से झगड़ा किया और बाद में खदेड़कर भगा दिया। मूर्तियां गढ़ने वाले फनकारों को अब दोबारा वहीं भेजा गया है। बांस-बल्ली गाड़कर पॉलिथीन लगाने की कोशिश कर रहे शिल्पकार कृष्ण कुमार कहते हैं, लखमीपुर गांव में पचास परिवारों को 12 फीट चौड़ी और 16 फीट लंबी जमीन दी गई है। हमें लखमीपुर भेजते समय हुक्मरानों ने यह नहीं सोचा कि हमारी मूर्तियां कैसे बिकेंगी? विकास के नाम पर हमें लावारिश हाल में छोड़ दिया गया। पहले सड़क के किनारे मूर्तियां बेचकर दो पैसे कमा लिया करते थे। किसी तरह से जिंदगी चल रही थी। हमारा हुनर मिट्टी में मिल जाएगा। हमारा वही हाल है जैसे लोग अपनी बकरियों को चरने के लिए खेतों में छोड़ दिया करते हैं। हमें कोई व्यवस्था नहीं दी गई। न पीने के साफ पानी का इंतजाम है और न ही शौचालय का। हम खुले आसमान के नीचे आ गए हैं। हमारी सैकड़ों मूर्तियां तहस-नहस हो

गई हैं। आवास के लिए हमारी बस्ती के लोग बनारस के कलेक्टर से, बीजेपी के जिलाध्यक्ष एमएलसी हंसराज विश्वकर्मा से मिलकर अर्जी दे चुके हैं। लेकिन, नतीजा वही ढाक के तीन पात। अब तो हम साइकिल से गांव-गांव जाकर सिर्फ सिलबट्टे ही बेच पाएंगे। सब ध्वस्त हो गया। वहां दो पैसा कम मिलता था लेकिन जिंदगी चल जा रही थी। अब साइकिल पर सील-लोढ़ा बेचेंगे।ष

☞ **घुटन भरे रास्ते पर धकेले गए :-** कृष्ण कुमार के पिता कैलाश जाने-माने मूर्तिकार हैं। इनके दो छोटे भाई कमलेश और महेश की चिंता यह है कि इनके पास अब कोई काम नहीं है। दोनों युवक पहले पत्थरों पर नाम की खुदाई करके पेट भरने के लिए पैसे कमा लिया करते थे। कभी देवी-देवताओं की मूर्तियां बनाते तो कभी युग पुरुषों की प्रतिमाएं। पत्थर के पिलर, गुंबद, जाली, नक्काशीदार मेहराब, घोड़ा-हाथी, सीलबट्टा आदि बनाने में इन्हें महारत हासिल है। विंध्य पहाड़ियों से निकले लाल बलुआ पत्थरों पर इनके हाथ की कारीगरी देखने लायक होती है। इन्होंने हर धर्म और हर संप्रदाय से जुड़े देवी-देवताओं की मूर्तियां बिना भेदभाव के गढ़ा। साथ ही गली-कूचों में घूमकर लोगों तक पहुंचाया भी। छल-कपट से कोसों दूर शिल्पकारों ने अपनी कला को न सिर्फ कद्रदानों तक पहुंचाया, बल्कि अपने हुनर को दिल खोलकर बांटा। अपने जैसे फटेहाल लोगों की मदद की। वह भी बिना किसी लिंग भेद और वर्ग के आधार पर। मूर्तिकार कैलाश कहते हैं, हम जनजाति समुदाय के लोग हैं। करीब 80 साल पहले अयोध्या से यहां आकर चांदपुर में सड़क के किनारे बस गए थे। अहरौरा से पत्थर लाकर मूर्तियां गढ़ा करते थे। सड़क के किनारे रखकर उन्हें बेच दिया करते थे। जब से हम लखमीपुर आए हैं तभी से गांव के कुछ दबंग हमें भगा रहे हैं। जिस स्थान पर हमें बसने के लिए कहा गया है वहां आम और महुआ का बगीचा है। बंजर की जमीन है, इसलिए हर कोई अपनी दावेदारी जता रहा है। लखमीपुर में स्थायी रूप से बसने के लिए हमें अभी तक कोई कागज नहीं दिया गया है। किसी भी दिन हमें यहां से भी खदेड़ दिया जाए तो कोई अचरज की बात नहीं है। सरकार ने हमें एक अंधेरे, घुटन भरे मुस्तकबिल की ओर धकेल दिया है। शिल्पकारों की सालों पुरानी बस्ती के उजाड़े जाने से शिल्पकारों की जिंदगी की तमाम कहानियां भी दफन हो गई हैं। वो कहानियां जो बलुआ पत्थरों पर छेनी-हथौड़ी की आवाज से निकला करती थीं। इसी बस्ती में रहने वाले विनोद बनारस के उन हजारों शिल्पकारों में से एक हैं जो रोटी और रोजगार के लिए जिंदगी से जंग लड़ रहे थे। चांदपुर चौराहे से खदेड़े जाने के बाद अब वो मुफलिसी की पीड़ा झेल रहे हैं। विनोद कहते हैं, हम अपनी तकदीर के लिए मूर्तियों के रंग का एक छींटा भी नहीं बचा सके हैं। कद्रदानों की कमी और सरकारी नुमाइंदों की बेरुखी से हमारा हौसला पहले से ही टूटा हुआ था। अब यह समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर हम अपनी जिंदगी की निश्चित शक्ल कैसे गढ़ पाएंगे?

☞ **प्याज-रोटी के भरोसे चलती है जिंदगी :-** लोक संस्कृति और कला को समृद्धशाली बनाने वाले ये शिल्पियों पर भले ही मुसीबत आई हो, लेकिन इनकी उंगलियों में गजब का हुनर रचा-बसा है। मगर ऐसे हुनर का क्या फायदा जो रहने को छत, दो वक्त की रोटी और तन ढंकने के लिए कायदे का कपड़ा भी मयस्सर न करा सके। मायूसी से यह सवाल करती है 56 वर्षीया कंचन देवी। इन्हें मूर्तियों के साथ ही पत्थरों का सिलबट्टा बनाने में महारत हासिल हैं। कंचन भी छेनी हथौड़ी से पत्थरों पर मनमोहक मूर्तियां गढ़ती है। कंचन देवी के कुनबे के बच्चों ने कभी स्कूल का मुंह नहीं देखा, लेकिन उनकी उंगलियों में गजब का हुनर रचा-बसा है। इनकी बेटियां मूर्तियों पर गजब का चटक रंग भरती हैं। बच्चों के स्कूल नहीं जा पाने की कंचन को आज भी कसक है। वह कहती है, जानती हूं, हमारे कुनबे के छोटे-छोटे बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है। मगर पास में फूटी कौड़ी नहीं। काम में हाथ नहीं बटाएगी तो हम खाएंगे क्या? जहां तक सिलबट्टे की बात है तो अब इसका चलन पुराना हो गया है। छेनी और हथौड़ी की मदद से पटिया पर हमें नक्काशी करनी पड़ती है। कंचन कहती हैं, एक सिलौटी बनाने में हमें कम-से-कम दो घंटे का समय लगता है। एक सिलबट्टा हम 350-400 रुपये में बेचते हैं। सिलबट्टा नहीं बिकता तो उसे लेकर हम गांव-गांव में घूमते हैं। किसी दिन सभी सिलौटी बिक जाती है और किसी दिन खाली हाथ लौटना पड़ता है। बारिश के दिनों में हमें मुश्किलों का सामना करना पड़ता है क्योंकि उस वक्त सिलबट्टे की बिक्री कम होती है। मिक्सी मशीन आने के बाद इसके कद्रदान नहीं रह गए हैं। बाजार में हम जैसे लोग पीसे जा रहे हैं। हमारी जिंदगी किसी अफसाने से कम नहीं। अयोध्या से बनारस आकर हमारी कला तो जरूर निखरी है, लेकिन कद्रदानों से मायूसी ही मिली है। त्योहारों पर हमारी मूर्तियों बिक्री ठीक-ठाक हो जाती थी, लेकिन अब दो वक्त की रोटी जुटा पाना मुहाल हो जाएगा। कला-संस्कृति के इन पुजारियों को गाहे-बगाहे पुलिस भी परेशान करती है। पुलिस सुविधा शुल्क वसूलती है तो कुछ लोग फोकट में मूर्तियां चाहते हैं। गाहे-बगाहे सिरफिरे भी इन्हें तंग करते हैं। परिवार और इज्जत का सवाल जुड़े होने के

कारण ये मूर्तिकार उफ् तक नहीं करते। शिल्पकार कैलाश गिहार कहते हैं, जब से लोग आर्ट गैलरियों से मूर्तियां खरीदने लगे हैं तब से हमारा धंधा चौपट हो गया है। अगर हम गली-गली घूमकर मूर्तियां और सिलबट्टे बेचना बंद कर दें तो दो वक्त की रोटी जुटा पाना भारी पड़ेगा। ऑफ सीजन में तो वैसे भी रोटी और प्याज के भरोसे ही जिंदगी चलती है। कई बार सूदखोरों से कर्ज लेकर किसी तरह जिंदगी की गाड़ी खींचनी पड़ती है। यह किसी तरह ही हमारी जिंदगी का संबल है। लाचारी है, इसलिए धंधा नहीं छोड़ पा रहे हैं। मूर्तिकला के धंधे को चलाने के लिए ऋण और सरकार का नाम लेते ही शिल्पकार करण विश्वकर्मा के चेहरे की लकीरें तन जाती हैं। दरअसल इन्हें सरकारी तंत्र के रवैये से बेहद नफरत है। कारण, इसके पास अपना न आधार है, न राशन कार्ड। सस्ता अनाज इनके लिए सपना है। यह त्रासदी केवल करण और उसके परिवार की नहीं, बल्कि मूर्तियां गढ़ने वाले सभी शिल्पकारों की जिंदगी के दस्तावेज हैं। अपनी किस्मत को कोसते हुए करण कहते हैं, पांच सौ लोगों की आबादी भले ही लखमीपुर में बसाई गई है, लेकिन पास में कोई शौचालय नहीं होने के कारण रात में ही खेतों में जाना पड़ रहा है। सरकारी हैंडपंप भी आसपास नहीं है। औरतें साड़ी का पर्दा बनाकर नहाती हैं।

☞ **चिंता में डूबे मूर्तिकार** :- 30 वर्षीय शिल्पकार मिथिलेश कुमार ने जब से होश संभाला है तभी से छेनी-हथौड़ी से मूर्तियां गढ़ रहे हैं। वह कहते हैं, हमारे पास इतनी दौलत नहीं है कि बच्चों को पढ़ा सकें। हमारे दादा कन्हैया ने तीन बरस की उम्र में ही हमें मूर्तियां गढ़ने का हुनर सिखाना शुरू कर दिया था। कोरोना के संकटकाल में दिक्कतें बहुत आई। उस समय बस किसी तरह से हम जिंदा बच पाए। छत पाने के लिए हम दौड़ते-दौड़ते थक गए, पर किसी ने हमारी नहीं सुनी। किसी योजना का हमें कोई लाभ नहीं मिला। हम पिछले दस बरस से बीजेपी को वोट देते आ रहे हैं। हम चाहते हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी हमें भी सरकारी आवास दिलाएं और खेती के लिए जमीन भी। हमारी मूर्तियां भी लालपुर के संकुल में बेची जाएं। गांव के लोग मैग्जीन से जुड़े कला संपादक अमन विश्वकर्मा कहते हैं, चांदपुर में मूर्तियों को गढ़ने वाले फनकार इंसानी सभ्यता की कामयाबी के बड़े प्रतीक बन गए थे। इनका हुनर बनारस के इतिहास को गढ़ा करता था। साथ ही इस बात को भी तस्दीक किया करता था कि इंसान के हाथों का हुनर, दिमाग का खुलापन, कैसे पत्थरों पर खूबसूरत मूर्तियां उकेर सकता है। शिल्पकारों की मूर्तियां सिर्फ कल्पना भर नहीं थीं, वो एक तल्ख सच्चाई भी बयां किया करती थीं। उजाड़े जाने के बाद इन शिल्पकारों के चेहरे पर अब चिंता की गहरी लकीरें उभर आई हैं, जिसे देखकर आसानी से समझा जा सकता है कि उनकी बस्ती के टूटने से इंसानियत ने कितना बड़ा नुकघ्सान उठाया होगा। इसे एक धरोहर की बर्बादी की मिसाल मानी जा सकती है। बनारस के वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप कुमार कहते हैं, बनारस में लोग कभी न जाने के लिए आते हैं, लेकिन इस शहर से बहुत कुछ चला गया। जिंदगी की एक लय और सुकून ही नहीं, हजारों फनकारों का हुनर भी गुमशुदा हो गया। वो फनकार जिनकी अदा पर बनारस फिदा होता था। जिनके हुनर का हर कोई दीवाना हुआ करता था। अब सिर्फ बेचौनियां भरी पड़ी हैं। आडंबर है, बेबसी है, खलबली है। मौजूदा समय में बाजार तो हैं, लेकिन तौर-तरीके बदल गए हैं। अनूठे शहर बनारस में भी सिर्फ वही बच रहा है जो बदली हुई जरूरतों के हिसाब से खुद को बदलने की कोशिश कर रहा है। कुछ जाने-अनजाने में कुछ सरकार और नौकरशाही की अनदेखी के चलते। लोग कहते हैं कि समय बदल रहा है, लेकिन वक्त के साथ जो चीजें बदल रही हैं अब उनका कहीं कोई जिक्र नहीं होता। होता भी है तो सिर्फ किस्से और कहानियों में। अब न उनके खरीदार बचे हैं और न पहले जैसे कारीगर। पीएम नरेंद्र मोदी के बनारस में चांदपुर के मूर्तिकारों को स्थायी रूप से बसाने से पहले जिस तरह से उनकी बस्ती ढहा दी गई, उससे लगता है कि अब वो भी कुछ दिनों में किस्से-कहानियों के हिस्से बनकर रह जाएंगे। (साभार) ●

(लेखक बनारस के वरिष्ठ पत्रकार हैं)

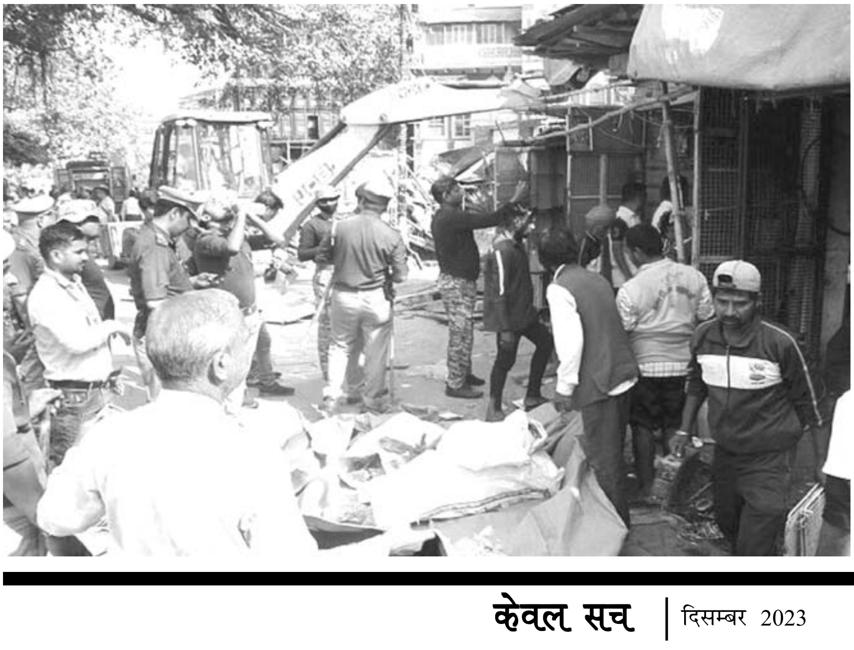

फर्रूखाबाद की धरती से पूरे विश्व में बिखरी है रूहानियत की खुशबू

● ब्रजेश सहाय, उप संपादक

उत्तर प्रदेश के गंगा नदी किनारे बसने वाले जनपद फर्रूखाबाद का नाम आध्यात्मिक नगरी के लिए भी जाना जाता है, क्योंकि ये धरती महान सूफी संत सत्गुरु हजरत मौलाना शाह फजल अहमद नक्शबंदी रहमतल्लाह व उनके शिष्य परमसंत महात्मा रामचन्द्र लाला जी महाराज की जन्मस्थली है। जिनके अनुयायी दुनियाभर के लगभग 150 देशों में हैं और पूरे वर्ष भर इनकी समाधियों पर दर्शन को आते रहते हैं। हुजूर महाराज मौलाना शाह फजल अहमद नक्शबंदी रहमतल्लाह के आस्तांना शाह विलायत रायपुर की व्यवस्था देख रहें उनके वंशज सूफी शाह हुसैन नक्शबंदी बताते हैं कि हुजूर महाराज मौलाना शाह फजल अहमद नक्शबंदी रहमतल्लाह व उनके शिष्य महान सूफी संत महात्मा रामचन्द्र लाला जी महाराज ने अपना पूरा जीवन आध्यात्म की इस खेती को सींचने और दीन-हीन मानवता के उद्गार और उनके दिलों में ईश्वर की तड़प

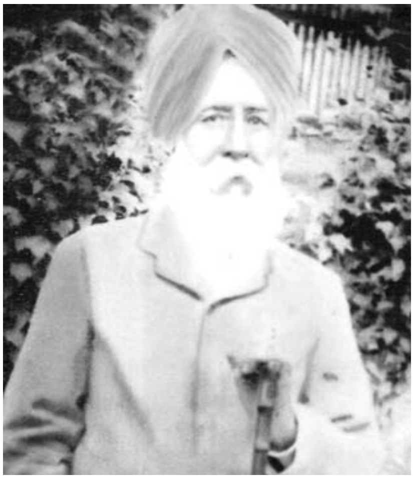

हुजूर महाराज मौलाना शाह फजल अहमद नक्शबंदी (रहमतल्लाह)
जन्मस्थली:- रायपुर
खास तहसील :- कायमगंज जनपद, फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश।
जन्मदिवस :- 26 जनवरी 1857
निर्वाण दिवस :- 30 नवंबर 1907

शाह-हुसैन गुलामाने-गुलाम
आस्तांना शाह विलायत, रायपुर कुंवरपुर इमलाक निकट ईदगाह, परौरी मार्ग कायमगंज, फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश। मोबाइल- 8303216812

पैदा करने में लगा दिया। हुजूर महाराज मौलाना शाह फजल अहमद नक्शबंदी रहमतल्लाह का जन्म फर्रूखाबाद की तहसील कायमगंज के कस्बा रायपुर में 1857 में हुया था और उन्होंने अपनी पूरी जिन्दगी खिजमत-ए-खल्क में लगा दी। आप कहते थे कि रुहानियत यानि आध्यात्मिक विद्या सभी मजहबी (धार्मिक) बन्धनों से मुक्त है और कोई भी धर्मावलंबी अपने धर्म के रीती-रिवाज को मानते हुए बिना किसी धर्म -परिवर्तन के किसी भी दूसरे धर्म के सत्गुरु से रुहानियत यानि आध्यात्मिक विद्या सीख सकता है। उन्होंने इस सिद्धांत को सिर्फ कहा ही नहीं बल्कि अपने जीवन में कर के भी दिखाया। उन्होंने आध्यात्मिक जगत में हिन्दू धर्म के दो ऐसे महारत्न तराशे, (महात्मा रामचन्द्र लाला जी महाराज तथा उनके छोटे भाई महात्मा रघुवर दयाल जी महाराज) जिनके शिष्य परम्परा से आज हजारों नहीं बल्कि लाखों लोग फैजयाब यानि लाभान्वित हो रहें हैं। वे अक्सर दो लाइन पढते हुए बोला करते थे- **जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। काम करो तलवार से, पड़ी रहन दो म्यान॥**

उक्त पंक्तियों को सुनाते हुए आप हिन्दू भाईयों से कहते थे कि 'तुम मेरे पास आत्मज्ञान सीखने आये हो, अवश्य सीखों। परंतु मेरी रहनी सहनी की नक्ल हरगिज न करें'। जिस समाज, जाति, धर्म, कुल में तुम्हारा जन्म हुआ है, उसके रीति-रिवाजों का पालन करो। बाहरी जीवन तुम्हारे कुल व जाति के अनुसार हो। आत्मिक क्षेत्र में हमारा तुम्हारा सम्बन्ध है।

हुजूर महाराज मौलाना शाह फजल अहमद नक्शबंदी रहमतल्लाह ने अपने शिष्य महात्मा रामचन्द्र लाला जी महाराज को सिलसिला नक्शबंदिया में 11 अक्टूबर 1896 को कुल्ली तौर पर इजाजत खिलाफत यानि आचार्य पदवी प्रदान करते हुए फरमाया कि 'मेंरे सत्गुरु पीरोमुर्शिद परम संत मौलवी अहमद अली खान मऊरशीदाबादी ने फरमाया था कि रुहानियत में आने वाले वक्त में तुमसे लोगों को बहुत फायदा पहुंचेगा, लेकिन अफसोस मैं इस काबिल नहीं हुआ और इस फर्ज को पूरे तौर पर अदा नहीं कर

महात्मा रामचन्द्र लाला जी महाराज
फतेहगढ़, उत्तर प्रदेश
जन्मदिवस :- 1873
निर्वाण दिवस :- 1934

सका और अब वक्त रुकसती यानि (अंत समय) का है, लेकिन मुझको पूरी उम्मीद है कि इस फर्ज-कर्तव्य को तुम पूरा करोगे और मेरे गुरु की पेशनगोई यानि भविष्यवाणी को पूरा करोगे और अगर तुमने ये काम पूरा किया तो दीन और दुनिया दोनों में सुर्खरह होगे'। और वही हुआ भी। महात्मा लाला रामचन्द्र लाला महाराज के नाम पर आज बढ़ी संख्या में विश्वविख्यात सत्संग स्थापित है, जिनमें रामाश्रम श्रीकृष्ण सत्संग गाजियाबाद, रामश्रम सत्संग मथुरा, श्रीरामचन्द्र मिशन शाहजहांपुर, सहज मार्ग, हार्टफुलनेस, अखिल भारतीय सूफी सत्संग व रामाश्रम खुदागंज, आदि है, जो इस रुहानी शिक्षा को लगातार आगे फैलाने का काम कर रहें हैं और इन सत्संगों के द्वारा पूरे विश्व में जगह-जगह सेंटर संचालित किए जा रहे हैं, जिससे लाखों लोग लाभान्वित हो रहे हैं। महात्मा रामचन्द्र लाला जी महाराज की समाधि फर्रूखाबाद के मोहल्ला नवादिया तालैयालैन स्थित फतेहगढ़ में है, जहां हर वर्ष गुड-फ्राइडे पर भंडारे का आयोजन किया जाता है। महात्मा रामचन्द्र लाला जी महाराज के सत्गुरु हुजूर महाराज मौलाना शाह फजल अहमद नक्शबंदी (रहमतल्लाह) के परिवार से आने वाले सूफी शाह-हुसैन नक्शबंदी कहते कि पीरोमुर्शिद यानि सत्गुरु की सच्ची खिजमत यानि सेवा ये है कि इस फानी दुनिया यानि (खत्म हो जाने वाले संसार) से ऊपर उठें और उस मालिक यानि ईश्वर का प्रेम हासिल कर लें और एक बात गाठ बांध लें कि जिस दिन भी किसी कामिल मुर्शिद यानि सत्गुरू को मजबूती से पकड़ लेगे, पूरे यकीन के साथ उसके बन जायेगे। पूरी तरह से उसके सामने आत्मसमर्पण कर देगे, तो उस ही दिन अपने को ईश्वर के पास खड़ा पायेंगे। वह कहते हैं कि हुजूर महाराज फरमाते थे कि पीर रहबर (पथ-प्रदर्शक) हैं, क्योंकि जिस बात का पता तुम खुद तलाश करके भी न लगा सके उसके मिलने की तरकीब उसने बता दी। इस वास्ते उसकी बहुत इज्जत करनी चाहिए और वह बहुत बड़ी इज्जत के काबिल है। उसकी खिदमत (जिस्मानी शारीरिक सेवा) उतनी ही करनी चाहिए, जिसमें उसको कोई जिस्मानी परेशानी न पहुंच पाए। बाकी जिस्म यानि शरीर को पीर यानि गुरु नहीं समझना चाहिए। वह जो चीज है, वह है अर्थात गुरु आत्मिक शक्ति। जो शिष्य के अन्त:करण की अक्ष्यानता के अंधकार को दिव्यज्ञान के प्रकाश में बदल दे। वही पीर यानि सत्गुरु है। वह कहते थे कि वास्तव में जो सत्गुरु होते हैं वह कभी भी अपनी पूजा नहीं कराते हैं और न ही कराना चाहते हैं। जो भी उनके पास आता है, असली ध्येय व इष्ट की ओर उसका रुझान कर देते हैं और ईश्वर से प्रार्थना किया करते हैं-"हे स्वामी, तेरी ही दया-कृपा से इस सेवक ने तेरे बन्दों को तेरी याद दिलाकर तेरे सामने पेश कर दिया। बस अब ये तेरा काम है कि तू इन पर अपनी दया कृपा की दृष्टि कर तथा सन्मार्ग पर चलने का साहस तथा अपना प्रेम व अनुराग इनको प्रदान करे"।

हुजूर महाराज मौलाना शाह फजल अहमद साहब नक्शबंदी रहमतल्लाह की दरगाह यानि समाधि उत्तर प्रदेश के जनपद फर्रूखाबाद की तहसील कायमगंज के कुंवरपुर इमलाक में हैं और वहां की व्यवस्था को उनके वंशज सूफी शाह-हुसैन नक्शबंदी देखते हैं।●

निशाने पर मदरसे : बार-बार जांच और रूके मानदेय को लेकर प्रदर्शन

● **असद रिजवी**

उत्तर प्रदेश में मदरसों में पढने वाले छात्र और पढ़ाने वाले अध्यापक दोनों संकट का सामना कर रहे हैं। मदरसा परिषद की परीक्षाओं से पहले जाँच से परीक्षाएं, जिसमें करीब एक लाख 30 हजार छात्र शामिल होंगे, प्रभावित होने की आशंका है। इसके अलावा लगभग 21,000 से अधिक आधुनिक मदरसा शिक्षकों को पिछले 6 वर्षो से मानदेय मिला है। 18 दिसम्बर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के मौके पर सरकार की मदरसों के प्रति उदासीनता का दर्द उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद और आधुनिक मदरसा शिक्षकों से छलकता नजर आया। बोर्ड ने सरकार को एक पत्र लिखाकर कहा कि जाँच के लिए कम से कम परीक्षाएं समाप्त होने का इंतजार किया जाये। वहीं आधुनिक मदरसा शिक्षकों ने कहना है अगर आम चुनाव 2024 तक उनका बाकी मानदेय नहीं मिला तो वह अध्यापन कार्य त्यागने पर मजबूर होंगे। उत्तर प्रदेश में 2017 में जब से योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) की सरकार सत्ता में आई है तब से चौथी बार मदरसों की जाँच होने जा रही है। दूसरी तरफ केंद्र सरकार से मिलने वाला मानदेय रुकने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने आधुनिक मदरसा शिक्षकों का "अतिरिक्त राज्यांश" रोक भी दिया है। प्रदेश के मदरसा परिषद ने सरकार को एक पत्र लिखकर कहा है कि अधिकारी अनुमति के बिना मदरसों की जाँच कर उत्पीड़न कर रहे हैं। परिषद के चेयरमैन डॉ. इफ्तेखार अहमद जावेद ने अल्पसंख्यक अधिकार दिवस पर प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ व हज मंत्री, धर्मपाल सिंह से कहा है कि जाँच को लेकर स्पष्ट आदेश जारी नहीं होने के कारण "असमंजस" की स्थिति है और परीक्षाओं से पहले मदरसों में अफरा तफरी का महौल पैदा हो गया है। मदरसों का डाटा मदरसा शिक्षा के "पोर्टल" पर उपलब्ध है और मदरसा परिषद की परीक्षाएं 13 फरवरी से होनी हैं, ऐसे में अगर जाँच करना आवश्यक है तो वार्षिक परीक्षाओं के बाद की जाये। यह चौथी बार जाँच की बात सामने आई है, लेकिन परीक्षाओं को देखते हुए इसको स्थगित करना आवश्यक है। वही परिषद से अनुमति लिए बगैर ही, रजिस्ट्रार मदरसा परिषद के पत्र पर निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण के आदेश से, अनुदानित और गैर-अनुदानित मदरसों की जांच की कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई। परिषद के चेयरमैन डॉ. इफ्तेखार जावेद ने संबंधित मंत्री को 5 दिसम्बर को एक पत्र संख्या 2884/म.शि.प./2023 को पत्र भेजा था। इसके बाद मंत्री धर्मपाल सिंह ने उनके पत्र को संज्ञान में लेते हुए विभागीय उच्च अधिकारियों के साथ बैठक में जांच की कार्यवाही को रोकने हेतु "मौखिक" आदेश जारी किए हैं।● (साभार)

हिन्दू राष्ट्र के एजेंडे पर यूजीसी और एनसीईआरटी

● राम पुनियानी

नयी शिक्षा नीति (एनईपी) हमारी शिक्षा व्यवस्था के ढांचे और स्वरुप में आमूलचूल परिवर्तन लाने वाली है. सरकार द्वारा नियमित रूप से ऐसे निर्देश जारी किये जा रहे हैं जिनसे विद्यार्थियों के मनो-मस्तिष्क में हिन्दू राष्ट्रवादी विचार और सिद्धांत बिठाये जा सकें. सरकार ने सबसे पहले विद्यार्थियों के आंदोलनों और उनके प्रतिरोध को कमजोर करने और उनमें भागीदारी करने वालों को डराने-धमकाने का अभियान शुरू किया. इन आंदोलनों के नेताओं पर राष्ट्रद्रोही का लेबल चस्पा कर दिया गया. तत्कालीन मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने प्रस्तावित किया कि प्रत्येक केन्द्रीय विश्वविद्यालय के प्रांगण में एक बहुत ऊंचे खम्बे पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाए. यह भी प्रस्तावित किया गया कि जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालय (जेएनयू) के कैंपस में सेना का एक टैंक स्थापित किया जाए. वह इसलिए क्योंकि वहां के विद्यार्थी ऐसे मसले उठा रहे थे जो सरकार को पसंद नहीं थे.

हाल में इसी तर्ज पर कई निर्देश / आदेश जारी किये गए हैं. इनमें से एक यह है कि आरएसएस के प्रचारक और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् (एबीवीपी) के संस्थापक दत्ताजी दिदोलकर की जन्म शताब्दी को मनाने के लिए एक साल तक चलने वाले आयोजनों में विद्यार्थियों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए. एक हिन्दू राष्ट्रवादी को राष्ट्रनायक का दर्जा देने का इस प्रयास का फोकस महाराष्ट्र के कॉलेजों पर है. क्या हिन्दू राष्ट्रवादी नेताओं को हीरो बनाने का यूजीसी का यह प्रयास उचित है? क्या हमें उन नायकों को याद नहीं करना चाहिए जो भारतीय राष्ट्रवाद के हामी थे और जिन्होंने ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार के खिलाफ संग्राम का नेतृत्व किया था? आरएसएस से जुड़े दिदोलकर न तो स्वाधीनता संग्राम का हिस्सा थे और ना ही वे भारतीय संविधान के मूल्यों में आस्था रखते थे. यूजीसी ने एक और सर्कुलर जारी कर कहा

है कि कॉलेजों में 'सेल्फी पॉइंट' बनाए जाने चाहिए जिनकी पृष्ठभूमि में प्रधानमंत्री मोदी का चित्र हो. कहने की जरुरत नहीं कि यह 2024 के आमचुनाव की तैयारी है. किसी भी प्रजातान्त्रिक देश में ऐसा नहीं होना चाहिए. क्या सरकार को किसी भी एक पार्टी के शीर्ष नेता का प्रचार करना चाहिए? क्या यह प्रजातान्त्रिक मानकों का उल्लंघन नहीं है? प्रजातान्त्रिक और संवैधानिक मूल्यों का इस तरह का खुल्लमखुल्ला मखौल क्या सरकार द्वारा अपनी शक्तियों के घोर दुरुपयोग के श्रेणी में नहीं आता? इससे भी एक कदम आगे बढ़कर, यह निर्देश जारी किया गया है कि कक्षा सात से लेकर कक्षा बारह तक के विद्यार्थियों को इतिहास के पाठ्यक्रम के भाग के रूप में 'रामायण' और 'महाभारत' पढाया जाना चाहिए (टाइम्स ऑफ इंडिया, 22 नवम्बर, 2023). एनसीआरटी के एक्सपर्ट पैनल के अनुसार इससे देश के लोगों में देशभक्ति और स्वाभिमान के भाव जागृत होंगे और वे अपने देश पर गर्व करना सीखेंगे! भारत के ये दो महान महाकाव्य निश्चित तौर पर हमारे पौराणिक साहित्य का हिस्सा हैं. वे उस समय के सामाजिक मूल्यों और मानकों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिस समय वे लिखे गए

थे. हम इन महाकाव्यों से उस समय के समाज के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं. रामायण भारत में ही नहीं वरन श्रीलंका, थाईलैंड, बाली और सुमात्रा सहित एशिया के कई देशों में अत्यंत लोकप्रिय हैं. रामायण के कई अलग-अलग संस्करण हैं. रामायण के मूल लेखक वाल्मीकि थे. गोस्वामी तुलसीदास ने जनभाषा अवधी में उसका अनुवाद कर उसे आम जनता तक पहुँचाया. सोलहवीं सदी से रामायण उत्तर भारत की जन संस्कृति का हिस्सा बनी हुई है. भगवान राम की वह कथा जो हिन्दू राष्ट्रवादियों को प्रिय है, इस कथा के कई अलग-अलग पाठों में से एक है. पौला रिचमेन की पुस्तक 'मेनी रामायन्स' (ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस), भगवान राम की कहानी के अलग-अलग संस्करणों के बारे में बताती है. इसी तर्ज पर ए.के. रामानुजन ने एक लेख लिखा था जिसका शीर्षक था "श्री हंड्रेड रामायंस: फाइव एग्जामपिल्स एंड थ्री थॉट्स ऑन ट्रांसलेशन". यह अत्यंत अर्थपूर्ण लेख दिल्ली विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम का हिस्सा था. मगर बाद में एबीवीपी के विरोध के कारण इसे हटा दिया गया.

हिन्दू राष्ट्रवादी रामकथा के एक विशिष्ट संस्करण को बढ़ावा देना चाहते हैं. रामानुजन बताते हैं कि इस कथा के कई स्वरुप है - जैन और बौद्ध स्वरुप हैं, और महिलाओं का संस्करण भी है, जिसकी लेखिका आंध्रप्रदेश की रंगनायकम्मा है. आदिवासियों की अपनी रामकथा है. अम्बेडकर ने अपनी पुस्तक "हिन्दू धर्म की पहेलियाँ" में हमारा ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित किया है कि राम ने शम्बूक की केवल इसलिए हत्या कर दी थी क्योंकि वह शूद्र होते हुए भी तपस्या कर रहा था. इसी तरह, राम ने छुपकर और पीछे से वार कर बाली को मार दिया था. बाली कुछ पिछड़ी जातियों ही श्रद्धा के पात्र हैं. कहा जाता है "इडा पीडा जावो, बगीचे राज्य येवो" (हमारे दु:ख और तकलीफें खत्म हों और बाली का राज फिर से कायम हो). अम्बेडकर राम की इसलिए भी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं क्योंकि राम ने मात्र इसलिए सीता को जंगल में छोड़ दिया था क्योंकि उन्हें अपनी पत्नी के चरित्र पर संदेह था. पेरियार भी द्रविड़ों पर आर्य संस्कृति लादने के लिए राम की आलोचना करते हैं. ठीक-ठीक क्या हुआ था यह साफ नहीं है मगर यह महाकाव्य हमें उस काल के बारे में कई महत्वपूर्णब बातें बताता है. उसी तरह महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित विश्व की सबसे लम्बी कविता 'महाभारत' भी हमें उस युग में झाँकने का मौका देती हैं. ये दोनों ग्रन्थ ज्ञान के स्त्रोत हैं. मगर उन्हें इतिहास के रूप में पाठ्यक्रम में शामिल करना एक अलग मसला है, जिसका सम्बन्ध हिन्दू राष्ट्रवाद से ज्यादा और विद्यार्थियों को इतिहास के सच से परिचित करवाना कम है. यह भी कहा गया है कि पाठ्यपुस्तकों में इंडिया की जगह भारत शब्द का इस्तेमाल किया जाए. ऐसा बताया जा रहा है कि चूँकि हमारे देश को इंडिया नाम अंग्रेजों ने दिया था अत: वह गुलामी का प्रतीक है. इस तथ्य को जानबूझकर छुपाया जा रहा है कि हमारे देश के लिए इंडिया से मिलते-जुलते शब्दों का प्रयोग अंग्रेजों के भारत आने से बहुत पहले से हो रहा है. ईसा पूर्व 303 में मेगस्थनीज ने इस देश को इंडिका बताया था. सिन्धु नदी के नाम से जुड़े हुए शब्द भी लम्बे समय से इस्तेमाल हो रहे हैं. हमारे संविधान में प्रयुक्त वाक्यांश "भारत देट इज इंडिया" का कोई जवाब नहीं है. मगर हिन्दू राष्ट्रवादी एजेंडा के चलते 'इंडिया' शब्द उन्हें असहज करता है. वे भारत के इतिहास को नए सिरे से कालखंडों में विभाजित करना चाहते हैं. इतिहास के सबसे पुराने कालखंड, जिसे अंग्रेज हिन्दूकाल कहते हैं, को वे 'क्लासिक' (श्रेष्ठ या उत्कृष्ट) काल कहना चाहते हैं. उद्देश्य है इस कालखंड में प्रचलित मूल्यों को हमारे समाज के लिए आदर्श निरुपित करना. ये मूल्य, जो 'मनुस्मृति' में वर्णित हैं, वही हैं जिनके विरुद्ध अम्बेडकर ने विद्रोह का झंडा उठाया था और 'मनुस्मृति' का दहन किया था. आज यूजीसी और एनसीईआरटी का मार्गदर्शक केवल और केवल हिन्दू राष्ट्रवादी एजेंडा है. भारतीय संविधान के मूल्यों से उन्हें कोई लेनादेना नहीं है. (साभार) ●

संसद सुरक्षा में हुई चूक से क्या सीखने की जरूरत?

● **महेश कुमार**

यह बड़ी राहत की बात है कि बुध वार, 13 दिसंबर, 2023 को संसद सुरक्षा में हुई चूक से किसी को नुकसान नहीं हुआ। हालांकि, यह एक दुखद संयोग है कि यह चूक उसी दिन हुई जिस दिन 2001 में संसद पर घातक और दुखद हमला हुआ था। बुधवार को, दर्शक दीर्घा से दो व्यक्तियों ने लोकसभा सदन में घुसकर धुआं छोड़ दिया था। इक्कीस साल पहले भी, 13 दिसंबर को बड़े पैमाने पर सुरक्षा में चूक हुई थी। तब हथियारबंद आतंकवादियों ने संसद परिसर में घुसकर अंधाधुंध गोलीबारी की थी, जिसमें केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के अधिकारियों और लोकसभा के निहत्थे वॉच एंड वार्ड कर्मचारियों सहित कई लोगों की मौत हो गई थी तथा राज्यसभा सचिवालयों को शीर्ष विध ायिका का सुरक्षा जिम्मा सौंपा गया था। लेकिन आज, हमें इतिहास में थोड़ी और गहराई में जाना होगा: 13 दिसंबर, 1946 को, भारत की अंतरिम सरकार के तत्कालीन प्रध ानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य-प्रस्ताव पेश किया था, जो अंततः हमारे संविध ान की प्रस्तावना बन गया था।

☞ **उद्देश्य प्रस्ताव में कहा गया :-** भारत एक संप्रभु, स्वतंत्र गणराज्य है, भारत को एक संघ होना चाहिए जिसमें पूर्व ब्रिटिश भारतीय इलाके, भारतीय राज्य और ब्रिटिश भारत के बाहर के अतिरिक्त इलाके और उन भारतीय राज्य को शामिल होना चाहिए जो भारतीय संघ में शामिल होने का विकल्प चुनते हैं, संघ में शामिल इलाके स्वायत्त इकाइयां होंगी, जो संघ में निर्दिष्ट या निहित इलाकों को छोड़कर सरकार और प्रशासन की सभी शक्तियों और जिम्मेदारियों का इस्तेमाल करेंगी। सभी संप्रभु और स्वतंत्र भारत की शक्तियाँ और अधिकार, साथ ही इसका संविधान, लोगों के जरिए हासिल होना चाहिए, सभी भारतीयों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक निष्पक्षता की गारंटी दी जानी चाहिए; स्थिति और अवसर की समानता; कानून के सामने समानता; और बुनियादी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए जो अभिव्यक्ति, आस्था, विश्वास, पूजा, व्यवसाय, संघ और कार्रवाई की-कानून और सार्वजनिक नैतिकता के अधीन होगी, अल्पसंख्यकों, पिछड़े और आदिवासी समुदायों, गरीबों और अन्य वंचित समूहों को बेहतर ढंग से संरक्षित किया जाना चाहिए, गणतंत्र की क्षेत्रीय अखंडता, साथ ही भूमि, समुद्र और वायु पर इसके संप्रभु अधिकारों को सभ्य देश होने के नाते न्याय और कानून के अनुसार संरक्षित किया जाना चाहिए, देश, विश्व-शांति की प्रगति और मानवता की भलाई के लिए पूर्ण और स्वेच्छा से योगदान देगा।

☞ **राष्ट्रपति केआर नारायणन की टिप्पणियां :-** 25 जनवरी 2002 को, भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति केआर नारायणन ने गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर दिए अपने भाषण में, दिसंबर 2001 के सुरक्षा उल्लंघन के संदर्भ में उद्देश्य- संकल्प को लागू करने का आह्वान किया था। उन्हें बड़ा दु:ख हुआ कि नेहरू द्वारा प्रस्ताव पेश करने की वर्षगांठ पर आतंकवादी हमला हुआ था। अपने भाषण में, उन्होंने राष्ट्र से लोकतांत्रिक तरीकों को अपनाकर और किसी भी आस्था में विश्वास रखने के बावजूद लोगों की एकता को बनाए रखते हुए, लोकतंत्र को आतंकवाद से बचाने की अपील की थी। नारायणन ने हमारे नागरिकों के कुछ वर्गों को उनकी आस्था के आधार पर आतंकवाद के लिए गलत तरीके से दोषी ठहराए जाने का भी जिक्र किया था और राष्ट्र से ऐसे पूर्वाग्रहों को त्यागने का आग्रह किया था। आज, संसद की सुरक्षा के उल्लंघन के संदर्भ में, हुकूमत को नागरिकों को शारीरिक नुकसान से बचाने के प्रति सचेत रहना चाहिए-शुक्र है कि सुरक्षा में हुई चूक बिना किसी नुकसान के टल गई, अन्यथा कुछ भी हो सकता था।

दरअसल, अगर संसद की सुरक्षा की रक्षा नहीं की जा सकती है, तो सवाल यह उठाता है कि राजनीतिक हुकूमत लोगों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित कर सकती है जिससे उसकी क्षमता पर सवाल उठता है। सुरक्षा के मामले में देश के अल्पसंख्यकों सहित हमारे विशाल वंचित वर्गों की सुरक्षा और देखभाल शामिल है। यह सब, विशेष रूप से संसद और उसके सदस्यों और कर्मचारियों सहित, देश के हर कोने को भौतिक रूप से सुरक्षित करने के साथ-साथ राज्य के कर्तव्यों का हिस्सा है। आज उद्देश्य-संकल्प का उल्लेख करने का कारण यह है कि ऐतिहासिक जाति-आधारित भेदभाव के कारण कई अधिकार खतरे में हैं क्योंकि बहुसंख्यकवाद सत्तारूढ़ शासन की नीतियों को तेजी से परिभाषित और निर्देशित कर रहा है। क्या देश के सभी संस्थानों की अखंडता में आई गिरावट पर ध्यान दिए बिना, घटना की बरसी पर उसी पवित्र स्थल पर एक दुखद घटना का होना, संसद में सुरक्षा में आई चूक को देखना वास्तव में संभव है? हमारे संविधान और लोकतंत्र की सुरक्षा को लेकर खतरे की घंटी बज रही है। हमारे इतिहास में 13 दिसंबर का बड़ा महत्व है। इसलिए, हमारे देश को हर तरह से सुरक्षित रखने के लिए-सभी प्रकार की सुरक्षा चूकों से दूर रखने के लिए हुकूमत जिसकी भी हो उसे नेहरू द्वारा 13 दिसंबर, 1946 को प्रस्तावित उद्देश्य-प्रस्ताव में निर्धारित मूल्यों को बनाए रखना होगा। (साभार) ●

(लेखक भारत के राष्ट्रपति केआर नारायणन के ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटि रह चुके हैं। विचार निजी हैं।)

डीपफेक का एक नया खतरा
लाइव वीडियो कॉल के जरिए ठगी और ब्लैकमेलिंग

● राज कुमार

डीपफेक: सावधान हो जाइये! अगर आप सोच रहे हैं कि ये सिर्फ हीरोइनों तक ही सीमित हैं, तो आप गलत सोच रहे हैं। डीपफेक वीडियो का ये काला कारोबार महिला खिलाड़ियों, महिला राजनेता, इंस्टाग्राम इंफलुएंसर, यूट्यूबर, एक्टिविस्ट, पत्रकारों आदि तक पैर पसार चुका है। ये कभी भी आपके दरवाजे पर दस्तक दे सकता है। जिस एआई (Artificial intelligence) के बारे में कहा जा रहा है कि ये लोगों की जिंदगी को आसान बनाएगी वो एआई लोगों की जिंदगी को नरक बना सकती है। 6 नवंबर को एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना का एक डीपफेक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इस घटना को एक दिन भी नहीं बीता कि एक्ट्रेस कटरीना कैफ का डीपफेक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। लेकिन ये सिर्फ एक-दो फोटो वीडियो का मामला नहीं है बल्कि इंटरनेट अभिनेत्रियों के डीपफेक वीडियो से भरा पड़ा है। देसीफेक डोट कोम, डीपफेक पोर्न ड्यूड डॉट कोम, मिस्टर डीपफेक, सी फेक, अडल्ट डीपफेक, सैक्स सेलेब्रेटी फेक, डीपफेक पोर्न, रियल डीपफेक, इस तरह की सैकड़ों वेबसाइट पर सेलेब्रेटी के डीपफेक पोर्न वीडियो भरे पड़े हैं। डीपफेक वीडियो/फोटो में बड़ी तादाद पोर्न की है। डीपट्रेस की एक स्टडी के अनुसार डीपफेक वीडियो में 96% पोर्न वीडियो हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या फिल्मों में काम करने वाली लड़कियों की कोई प्राइवेसी और मानवीय गरिमा नहीं है। क्योंकि वो फिल्मों में काम करती हैं, तो उनके फोटो, वीडियो के साथ कुछ भी किया जा सकता है? उनके फेक अश्लील वीडियो और फोटो इंटरनेट पर डाले जा सकते हैं? अगर आप सोच रहे हैं कि ये सिर्फ हीरोइनों तक ही सीमित हैं, तो आप गलत सोच रहे हैं। डीपफेक वीडियो का ये काला कारोबार महिला खिलाड़ियों, महिला राजनेता, इंस्टाग्राम इंफलुएंसर, यूट्यूबर, एक्टिविस्ट, पत्रकारों आदि तक पैर पसार चुका है। ये कभी भी आपके दरवाजे पर दस्तक दे सकता है। रश्मिका के इस डीपफेक वीडियो को खतरे की घंटी समझिये। आप यूट्यूब सर्च बार में डीपफेक टाइप करेंगे तो सजेशन आएंगे। डीपफेक टेक्नोलोजी, डीपफेक वीडियो कैसे बनाएं, डीपफेक एप, डीपफेक टुटोरियल, डीपफेक वीडियो एडिटिंग, डीपफेक एआई बोट, हाऊ टू डीपफेक। यानी यूट्यूब पर भारी संख्या में लोग ऐसे वीडियो की खोज रहे हैं जो डीपफेक वीडियो बनाना सिखा पाएं। डीपफेक वीडियो बनाने की ट्रेनिंग शुरू हो चुकी है। अभी तक डीपफेक के मामले विदेशों तक ही सीमित थे। लेकिन रश्मिका के डीपफेक वीडियो ने भारत में भी इसके दरवाजे खोल दिए हैं। मेरा अनुमान है कि भविष्य में इस तरह के मामलों में बढ़ोतरी होगी और इसके दायरे में साधारण लड़कियां भी आ सकती हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये सोफिस्टिकेटेड तकनीक अब आसानी से हर किसी को उपलब्ध है और ये बिल्कुल फ्री है। बस आपके पास स्मार्टफोन और इंटरनेट होना चाहिए। आपको बस किसी का फोटो या वीडियो इस एप पर अपलोड करना है, उसके बाद सारा काम एआई कर देगी। इस एडिटेड वीडियो को डाउनलोड करके, सोशल मीडिया पर शेयर कर सकते हैं। आज से कुछ साल पहले तक पहले इस तरह का सोफस्टिकेटेड फेक वीडियो बनाना होता था तो बहुत मेहनत लगती और फिर भी इस तरह के वीडियो नहीं बन पाते। लेकिन आज ये काम चुटकियों में हो रहा है। ऐसी बहुत सारी वेबसाइट और एप हैं,

जहां आसानी से किसी भी वीडियो पर किसी का भी चेहरा लगाया जा सकता है। दो अलग-अलग लोगों की अलग-अलग फोटो को एक साथ लगाया जा सकता है। आपको लगेगा कि ये दोनो एकसाथ हैं। ये एप बैकग्राउंड को सिंक्रोनाइज कर देती हैं और ब्लैक एंड व्हाइट फोटो को कलर बनाकर, कलर फोटो के साथ जोड़ सकती है। आपके लिए पहचान पाना मुश्किल हो जाएगा कि ये अलग-अलग जगह की फोटो है और दोनों व्यक्ति साथ नहीं थे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की मदद से इस तरह की वीडियो आसानी से तैयार की जा सकती है। इंटरनेट पर ऐसी सैकड़ों फ्री एप और सॉफ्टवेयर मौजूद हैं जो एक क्लिक पर किसी भी तस्वीर पर किसी का भी चेहरा लगा सकते हैं। किसी वीडियो पर आपका चेहरा लगा सकते हैं। आपकी आवाज को कॉपी किया जा सकता है और आपसे कुछ भी बुलवाया जा सकता है। वीडियो भी आपका होगा और आवाज भी हूबहू आपकी होगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी और सीजीआई यानी कंप्यूटर जेनरेटेड इमेज के जरिये ये सब संभव है। इन तमाम बातों से स्पष्ट है कि हमें सावधान हो जाना चाहिए। इस तकनीक का मिसयूज किया जा सकता है, किया जा रहा है। आपको जागरूक होना ही पड़ेगा। इस तरह की काफी वेबसाइट है जो किसी की भी फोटो से उसके कपड़े उतार सकती हैं। यानी आप किसी का भी न्यूड फोटो बना सकते हैं और वो भी बिल्कुल फ्री। इस तरह की भी वेबसाइट हैं जिनपर किसी का भी फोटो अपलोड करके ड्राइंग टूल के जरिये उसके कपड़े हटाये सकते हैं। इन वेबसाइट के होमपेज पर लिखा होता है, undress any photo with AI for FREE.

गाजियाबाद में एक आम नागरिक को एक स्कैमर ने पूर्व एडीजी की शक्ल में डीपफेक वीडियो कॉल कर ब्लैकमेल किया। देश में शायद इस तरह का यह पहला मामला है। अभी तक डीपफेक फोटो/वीडियो का मामला विदेशों तक ही सीमित था। लेकिन फिल्हाल ये भारत में भी पैर पसार चुका है। ये मामला अब सिर्फ सेलेब्रिटी के डीपफेक वीडियो तक ही सीमित नहीं है, बल्कि साधारण लोग भी इसकी चपेट में आने लगे हैं। अब तो सिर्फ डीपफेक वीडियो नहीं, बल्कि डीपफेक लाइव वीडियो कॉल के जरिये नागरिकों को ठगा जाने लगा है और ब्लैकमेल किया जाने लगा है। एक ऐसा ही मामला गाजियाबाद के कविनगर पुलिस स्टेशन में दर्ज हुआ है। गाजियाबाद के रहने वाले अरविंद शर्मा को एक वाट्सअप कॉल आता है जिसमें सामने से एक वर्दीधारी आईपीएस अधिकारी बोल रहा होता है। अधिकारी कहता है कि या तो पैसे दीजिये वर्ना आपको उठा लेंगे और आपके अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर डाल देंगे, आपके परिवार वालों को भेज देंगे। वीडियो में जो अधिकारी दिख रहा था, वो कोई छोटा-मोटा पुलिस अफसर नहीं, बल्कि आइपीएस अफसर और पूर्व एडीजी प्रेम प्रकाश थे। लेकिन आपको हैरानी होगी ये जानकर कि ये डीपफेक वीडियो कॉल था। इस वीडियो में पूर्व एडीजी प्रेम प्रकाश की शक्ल में स्कैमर थे, जो अरविंद शर्मा को ब्लैकमेल कर रहे थे। स्कैमर ने पूर्व एडीजी प्रेम प्रकाश की शक्ल में डीपफेक वीडियो कॉल किया था। ये ऐसी वीडियो कॉल थी कि कोई भी धोखा खा सकता था। यानी डीपफेक तकनीक और एआई के जरिये किसी दूसरे व्यक्ति की शक्ल में आपसे लाइव कॉल भी की जा सकती है। देश में शायद इस तरह का यह पहला मामला है।

वही गाजियाबाद के रहने वाले अरविंद शर्मा ने हाल ही में नया स्मार्टफोन खरीदा था। उस वक्त अरविंद शर्मा सोच रहे होंगे कि नई तकनीक और सोशल मीडिया से जुड़ेंगे लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि ये टेक्नोलॉजी उनके जीवन को नरक बना देगी। उन्होंने इस नये स्मार्टफोन में फेसबुक डाउनलोड किया और फेसबुक चलाने लगे। 4 नवंबर को उन्हें फेसबुक मैसेंजर पर एक वीडियो कॉल आई। जैसे ही अरविंद शर्मा ने कॉल को उठाया तो सामने एक महिला नग्न अवस्था में थी। अरविंद की समझ में नहीं आया कि ये क्या मामला है। उन्होंने हड़बड़ाहट में कॉल काट दी। लेकिन स्कैमर तब तक इसे रिकॉर्ड कर चुके थे। अरविंद शर्मा को ब्लैकमेल करने के लिये ये कुछ 8-10 सेकेंड का कॉल ही स्कैमर के लिए काफी था। इसके बाद अरविंद शर्मा के पास वाट्सअप पर एक वर्दीधारी पुलिस अफसर का वीडियो कॉल आता है और यहां से ब्लैकमेलिंग का सिलसिला शुरू हो जाता है। स्कैमर लगातार अरविंद शर्मा को ब्लैकमेल करते रहे और पैसे एंठते रहे। धीरे-धीरे करके अरविंद शर्मा से स्कैमर ने 74 हजार रुपये ठग लिए। अरविंद शर्मा एक क्लर्क हैं। उनके लिए 74000 रुपये कोई छोटी रकम नहीं है। वो इस ठगी के मकड़जाल में ऐसे फंसे कि अपने सहकर्मियों से कर्ज तक लेना पड़ गया। शर्म और बदनामी के डर से किसी को इस परेशानी के बारे में बता भी नहीं पा रहे थे। वो अकेले कुढ़ते रहे और बदनामी के डर से आत्महत्या तक के ख्याल उनके मन में आने लगे। इस घुटन से तंग आकर एक दिन अंततः अरविंद ने पूरा मामला परिवार को बता दिया। अगली बार जब स्कैमर का कॉल आया तो अरविंद शर्मा की बेटी मोनिका ने दूसरे फोन से उसे रिकॉर्ड कर लिया और कहा कि आपका चेहरा रिकॉर्ड हो रहा है। स्कैमर समझ गए कि

पकड़े गए हैं। स्कैमर ने डरकर फोन काट दिया। मोनिका और अरविंद शर्मा को अभी भी पता नहीं था कि ये वीडियो कॉल डीपफेक है। मोनिका अपने पिता के साथ कविनगर पुलिस स्टेशन गई और शिकायत दर्ज करा दी। तब उन्हें पता चला कि ये डीपफेक वीडियो कॉल थी और अरविंद शर्मा साइबर ठगी का शिकार हुए हैं। मामला रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी प्रेम प्रकाश तक भी पहुंचा, जिनके वीडियो का इस्तेमाल करके अरविंद शर्मा को डीपफेक कॉल की गई थी। पूर्व एडीजी प्रेम प्रकाश ने इसे गंभीरता से लिया और वीडियो जारी करके लोगों को इस स्कैम के बारे मे सतर्क किया। कमाल की बात ये है कि डीपफेक वीडियो कॉल के लिए पूर्व एडीजी प्रेम प्रकाश के जिस वीडियो का इस्तेमाल किया गया था, उस वीडियो में एडीजी प्रेम प्रकाश साइबर ठगी के बारे में सावधानियां बरतने की सलाह दे रहे थे और जागरूकता फैला रहे थे। असल में एडीजी प्रेम प्रकाश एक यूट्यूब चौनल चलाते हैं और उनके वीडियो यूट्यूब पर उपलब्ध हैं, जिनका इस्तेमाल करके स्कैमर डीपफेक वीडियो कॉल कर रहे थे।

आप समझ गये होंगे कि कितनी आसानी से ये काम किया जा सकता है। इसके परिणाम भयानक हो सकते हैं। इनका इस्तेमाल ब्लैकमेलिंग के लिए किया जा सकता है, किसी को बदनाम करने और उनके चरित्रहनन के लिए किया जा सकता है। मानसिक उत्पीड़न के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इस तरह के मामले किसी को डिप्रेशन से लेकर हत्या और आत्महत्या तक धकेल सकते हैं। सच को झूठ और झूठ को सच बनकर पेश कर सकते हैं। आपको याद होगा जंतर-मंतर पर यौन उत्पीड़न के खिलाफ धरना दे रही महिला पहलवानों को जब पुलिस ने गिरफ्तार किया तो एक तस्वीर सोशल मडिया पर वायरल की गई थी। जिसमें ये महिला पहलवान हंस रही थी। ये फोटो फेक था। असल में एक एप के जरिये ओरिजनल फोटो को एडिट किया गया था और इनके चेहरे के एक्सप्रेशन बदल दिए गए थे। आजकल कुछ फोन में इस तरह के फिल्टर इनबिल्ड आने लगे हैं। यानी आपको किसी थर्ड पार्टी एप की भी

POLICE COMMISSIONERATE GHAZIABAD
@ghaziabadpolice

दिनांक 27.11.23 को वादिया द्वारा थाना कविनगर पर सूचना दी गयी कि उनके पिता जी के साथ कुछ लोगों के द्वारा वीडियो कॉल करते हुए पुलिस अधिकारी बनकर धमकाया गया तथा उनसे 74000 रूपये ट्रान्सफर करा लिए गये । उक्त सम्बन्ध में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। घटना के अनावरण 1/2

Translate post

0:01 / 0:26

1:52 PM · Nov 30, 2023 · **21.7K** Views

जरूरत नहीं है। इस तरह के फेक फोटो और वीडियो मात्र सच को झूठ और झूठ को सच ही नहीं बना देते हैं बल्कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पैदा कर सकते हैं, दंगे भड़का सकते हैं, हेल्थ इमरजेंसी पैदा कर सकते हैं, लोकतंत्र को कमजोर कर सकते हैं, किसी की इमेज खराब कर सकते हैं, यहां तक कि देश की सुरक्षा के लिए भी खघ्तरा बन सकते हैं। सोचकर देखिये अगर युद्ध या बॉर्डर टेंशन के समय अगर देश के सबसे बड़े नेता या फौज के सबसे बड़े अफसर का कोई डिमोरलाइज करने वाला डीपफेक वीडियो वायरल कर दिया जाए तो क्या होगा। एक डीपफेक वीडियो युद्ध का पासा बदल सकता है। रूस-यूक्रेन युद्ध के दौरान ऐसी घटना हो चुकी है। यूक्रेन के राष्ट्रपति का डीपफेक वीडियो वायरल किया गया जिसमें वो यूक्रेनी सैनिकों को कह रहे थे कि हथियार डाल दो और रूस के सामने सरेंडर कर दो। बाद में प्रेजिडेंट जेलेंस्की ने वीडियो बनाकर इसका खंडन किया और बताया कि उनका डीपफेक वीडियो वायरल किया जा रहा है उसे सही ना माने वो फेक है। एआई का इस्तेमाल करके आपको लाखों का चूना लगाया जा सकता है। एआई की मदद से यूके की कंपनी के सीईओ को एक कॉल आई। सीईओ को लग रहा था कि वो अपने बॉस से बात कर रहा है। लेकिन उसके पीछे स्कैमर थे जो एआई की मदद से उसके बॉस की आवाज में बात कर रहे थे। सीईओ को उसके बॉस ने कहा कि तुरंत 2,43,000 डॉलर फलां अकाउंट में ट्रांसफर करो और सीईओ ने कर दिया। सीईओ को रत्ति भर भी शक नहीं हुआ कि दूसरी तरफ उसके बॉस नहीं बल्कि स्कैमर हैं।

इसमें कोई दो राय नहीं कि डीपफेक के खतरे बहुत हैं, लेकिन इनसे घबराने की जरूरत नहीं है। बल्कि आपको इन्हें समझने, जागरूक और सावधान होने की जरूरत है। अगर आपके पास ऐसा कोई वीडियो आता है तो उसे फ्रेम बाई फ्रेम गौर से देखिये। वीडियो में बालों पर गौर करें। क्या बाल कुछ अजीब लग

रहे हैं। दांतों पर खासतौर पर गौर करें क्या दांत आपको असली लग रहे हैं या इनका पैटर्न और बनावट कुछ असामान्य है। अगर कोई ज्वैलरी वगैरह पहन रखी है तो उस पर गौर करें। देखें कि क्या उसमें जरूरत से ज्यादा चमक है। आंखों को ध्यान से देखें। क्या पुतलियां असामान्य लग रही है। वीडियो में देखें कि क्या पलक झपकने का पैटर्न बनावटी है। बोलते हुए होंठों की मूवमेंट ध्यान से देखें। क्या उसमें स्वाभाविक फ्लो है। या होंठो और उसके आस-पास की मांसपेशियां रोबोटिक ढंग से हिल रही है। स्किन के रंग पर ध्यान दें। क्या स्किन कलर में कंसिस्टेंसी है या कहीं पे कैसा और कहीं पे कैसा है? आस-पास के माहौल में कैसी रोशनी है, इस पर गौर करें। क्या वीडियो में व्यक्ति में जिस तरह की लाइट है और बैकग्राउंड में जिस तरह की लाइट है, उसमें कोई अंतर है? कुछ अजीब है। अगर आप ऐसा करके भी नहीं पहचान पा रहे हैं कि वीडियो ओरिजनल है या डीपफेक है। लेकिन आपको शक है कि इस वीडियो में कोई तो गड़बड़ है, तो इसे आगे फारवर्ड ना करें। गूगल पर वीडियो के बारे में सर्च करें और देखें कि क्या इस वीडियो का फैक्ट-चेक किया गया है। अगर आपको फैक्ट चेक नहीं मिलता है तो फैक्ट चेक वेबसाइट को ये वीडियो भेजें और उन्हें फैक्ट चेक करने की रिक्वेस्ट करें। वही अगर आपके पास वाट्सअप या फेसबुक आदि के जरिये किसी अनजान व्यक्ति का वीडियो कॉल आता है, तो उसे ना उठाएं। ये एक पुराना स्कैम है। अकेले ही ना कुढ़ते रहे बल्कि अपने परिवार या मित्रों को परेशानी के बारे में बताएं। अगर कोई इस तरह से आपको ब्लैकमेल कर रहा है, तो तुरंत पुलिस में शिकायत दर्ज कराएं और साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 पर कॉल करके मामले की जानकारी दें। वीडियो को ध्यान से फ्रेम बाइ फ्रेम देखें। खासतौर पर गौर करें कि होंठों की मूवमेंट कैसी है? क्या बोलते हुए होंठ और होंठों के आस-पास की मांसपेशियां मैकेनिकल ढंग से हिल रही हैं? क्या स्पीच और होंठों की मूवमेंट में तालमेल है? वीडियो को बारीकी से देखें। भविष्य में इस तरह के मामलों में बढ़ोतरी का अनुमान है। इसलिए नई तकनीक के बारे में जानें, इसे समझें और मीडिया लिट्रेसी हासिल करें। डरें नहीं बल्कि सतर्क और सावधान रहें। (साभार) ●

एनसीआरबी डेटा :देश में किसान-मजदूरों के आत्महत्या के मामले बढ़े!

"जब छब्त्ठ के आकंडे कहते हैं कि पारिवारिक कारणों या बीमारी से ज्यादातर मजदूरों ने आत्महत्या की है तो इसका एक बहुत बड़ा कारण आर्थिक तंगी भी है।" बीते कुछ सालों में केंद्र और सरकारों ने किसान-मजदूरों को लेकर बड़े-बड़े दावे किए हालांकि NCRB यानी राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के ताजा आंकड़ों में इन दावों की हकीकत कुछ और ही नजर आती है। NCRB के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में किसान-मजदूरों की आत्महत्या में बढ़ोतरी हुई है। आंकड़ों के अनुसार, पिछले साल 2022 में, इस तरह की 01 लाख 70 हजार 924 आत्महत्याएं दर्ज की गई थीं जबकि 2021 में ये आंकड़ा 1,64,033 था। यानी साल 2021 की तुलना में 4. 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। हालांकि रिपोर्ट में कहा गया है कि ज्यादातर मामलों में मजदूरों ने पारिवारिक समस्याओं और बीमारी के कारण आत्महत्या की है। जहां पारिवारिक समस्याएं 31.7% और बीमारी 18.4% थी, वहीं बेरोजगारी और पेशेवर मुद्दे क्रमश: 1.9% और 1.2% थे। 4 दिसंबर, 2023 को जारी रिपोर्ट के मुताबिक, लगातार तीसरे साल महाराष्ट्र में आत्महत्या के सबसे अधिक मामले (22,746) दर्ज किए गए, इसके बाद कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश का नंबर है। इन आकड़ों को देखें तो पता चलता है कि खुदकुशी के मामले में देश का मेहनतकश वर्ग सबसे ऊपर है। इस आकड़ों मे एक तिहाई आत्महत्या किसान और खेत मजदूरों ने की है। इसके बाद सबसे अधिक आत्महत्या के मामले दैनिक दिहाड़ी मजदूरों के हैं, जिसकी संख्या 44,713 है जो कुल आंकड़े का करीब 26.4 प्रतिशत है। ये आंकडा पिछले साल की तुलना मे 1% अधिक था। इसके अलावा प्रोफेशनल यानी पेशेवरों की बात करें, तो खुदकुशी के मामले में इनकी संख्या 9.2 प्रतिशत है, जिसमें 14,395 वेतनभोगी और 18,357 स्व-रोजगार वाले लोग शामिल हैं। बेरोजगारी के कारण होने वाली आत्महत्या को देखें तो यह 9.2 प्रतिशत है, जहां साल 2021 में इस तरह के 3,541 मामले रिपोर्ट किए गए, वहीं 2022 में यह संख्या मामूली रूप से कम - 3,170 दर्ज की गई। देशभर में मजदूरों की आत्महत्या में बढ़ोतरी दिखाने वाले इन आंकड़ों को लेकर हमने सेंट्रल ट्रेड यूनियन सीटू के राष्ट्रीय सचिव सुदीप्त घोष से बात की। उन्होंने कहा कि सबसे चिंताजनक बात ये है कि ये आंकड़े हर साल बढ़ रहे हैं। सुदीप्त घोष कहते हैं, 'पिछले कुछ सालों में लोगों की क्रय शक्ति कम हुई है जबकि महंगाई लगातार बढ़ रही है। इसके साथ ही बेरोजगारी अपने चरम पर है। इसी का परिणाम है कि लोगों की सेविंग यानी बचत भी 5 प्रतिशत तक कम हुई है। जब NCRB के आकंडे कहते हैं कि पारिवारिक कारणों या बीमारी से ज्यादातर मजदूरों ने आत्महत्या की है तो इसका एक बहुत बड़ा कारण आर्थिक तंगी भी है।" NCRB के अनुसार, 1,09,875 यानी 64.3 प्रतिशत आत्महत्या करने वाले व्यक्तियों की वार्षिक आय एक लाख रुपये से कम है। पिछले पांच वर्षों में आत्महत्याओं की संख्या में 27.06 प्रतिशत की भारी वृद्धि हुई है और शहरी क्षेत्रों में आत्महत्या दर (16.4) अधिक थी। सुदीप्त ने कहा कि 'ये आंकड़े सरकारों के झूठे विकास के दावों की पोल खोलते हैं। पहले, किसान आत्महत्या जरूर करते थे लेकिन मजदूरों के मामले में ऐसा नहीं था। मजदुर काम के लिए प्रवास जरूर करते थे और कुछ भी करके अपना जीवनयापन करते थे लेकिन बीते सालों में मजदूर भी अपनी जान दे रहे हैं। ये आंकड़ा बड़े शहरों मे भी बढ़ रहा है जो ज्यादा गंभीर है। ये दिखाता है कि मजदूर नाउम्मीद और हताश हैं और यही कारण है कि वे अपनी जान दे रहे हैं'। अपने टेलीग्राम ऐप पर जनवादी नजरिये से ताजा खबरें, समसामयिक मामलों की चर्चा और विश्लेषण, प्रतिरोध, आंदोलन और अन्य विश्लेषणात्मक वीडियो प्राप्त करें। न्यूजक्लिक के टेलीग्राम चौनल की सदस्यता लें और हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित हर न्यूज स्टोरी का रीयल-टाइम अपडेट प्राप्त करें। (साभार)

डॉ. अनूपा कुमारी की दबंगई से विकास कार्य बाधित

● अरविंद मिश्रा

राजगृह बुद्ध सर्किट NH 82 फोरलेन पर वजीरगंज प्रखंड है, यहां नवगठित नगर पंचायत वजीरगंज में 15 वार्ड है, 2023 के चुनाव के बाद वजीरगंज को भी नगर पंचायत का दर्जा मिला, और इस और इस नवगठित नगर पंचायत को चुनाव के बाद विकास कार्य और बैठक का कार्य नगर निगम गया के अधीन कुछ माह तक संचालित होता रहा, 2023 के चुनाव के बाद तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी अभिलाषा शर्मा ने चकाचक वजीरगंज नगर पंचायत बनाने के लिए मुख्य पार्षद सहित सभी पार्षदों के साथ बोर्ड की बैठक की, कई एजेंडा भी बोर्ड में पारित हुए, बस स्टैंड निर्माण, सड़क निर्माण ,गली-गली पक्का निर्माण ,लाइट प्याऊ, पेयजल की सुविधा जैसी कई जनहित की योजनाओं को शामिल किया गया , आम जनता को लगा की अब वजीरगंज नगर पंचायत भी विकसित और समृद्ध होगा, विकास से परिपूर्ण होगा, लेकिन वजीरगंज की जनता को निराशा हाथ लगी, क्योंकि अभिलाषा शर्मा के ट्रांसफर के बाद नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी अनूपा कुमारी को प्रभाव मिला, और डा0 अनुपा कुमारी के आने के बाद नगर पंचायत विवादास्पद हो गया, क्योंकि कार्यपालक पदाधिकारी अपने शुभ लाभ के चक्कर में अपने साथ पांच खास व्यक्तियों को लेकर आई, जिनके जिम्मे नगर पंचायत के विकास की जिम्मेवारी अपने मनमाने तरीके से कार्यपालक पदाधिकारी ने सौंपी, जो सरकारी कर्मचारी नहीं थे, वह सारे के सारे कार्यपालक पदाधिकारी के चहते थे, जब मुख्य पार्षद बलदेव दास और अन्य पार्षदों को कार्यपालक पदाधिकारी के मन माने रवैया से चयन करने पर नाराजगी व्यक्त की, फिर पदाधिकारी बनाम जनप्रतिनिधि की लड़ाई शुरू हो गई, और विकास विवादों में फंस कर रह गया, कार्यपालक पदाधि कारी अपने तरीके से अपने करीबियों के माध्यम से कार्य करवाना चाहती थी, और मुख पार्षद और उनके सहयोगी पार्षद और उनके प्रतिनिधि चाहते थे की बोर्ड सर्वे सर्वा है, और जो सरकार का और नगर पंचायत और नगर विकास का जो गाइडलाइन है उसके अनुरूप ही कार्य हो, लेकिन बोर्ड की बैठक में बराबर शोर शराबा होता रहा, कभी-कभी स्थितियां अ नियंत्रित होने पर पुलिस प्रशासन को भी बुलाना पड़ा, शेड्यूल के अनुसार कई योजनाओं को कलमबद भी किया गया,

लेकिन विवाद के कारण करोड़ , करोड़ राशि जो वजीरगंज नगर पंचायत के विकास के लिए स्वीकृत हुई थी, उसमें से एक पैसा भी खर्च अब तक नहीं हो पाया, वजीरगंज नगर पंचायत गंदगी का अंबार बन गया, अपने, अपने वार्ड को चकाचक, विकसित और समृद्ध बनाने का सपना वार्ड सदस्यों को टूट कर रह गया, यह भी बता दें कि वजीरगंज नगर पंचायत आरक्षित सीट था, और इस आरक्षित सीट से बालदेव दास मुख्य पार्षद चयनित हुए, उम्र दराज होने के साथ-साथ अनुसूचित जाति होने के वजह से भी कार्यपालक पदाधिकारी डॉ० अनूपा देवी तरहीज नहीं देती थी, यह मुख्य पार्षद का आरोप है, इसके साथ ही मुख्य पार्षद का कहना है कि कार्यपालक पदाधिकारी पूर्व में भी जिन जिन नगर पंचायत में रही है वहां भी विकास सदा अवरुद्ध रहा, क्योंकि बोर्ड को सदैव मनमाने तरीका से अपने खास आदमियों से चलाना चाहती है, ताकि लूट,पाट खूब होता रहे, वजीरगंज नगर पंचायत में भी अपने दबंग ता और मनमानी तरीके से कार्य करने की जो उनकी पूर्व से प्रवृत्ति रही वही करना शुरू कर दी,तभी तो बोर्ड में लिए गए निर्णय के विरुद्ध अवैध रूप से अपने साथ रखे दो व्यक्तियों को पत्र के माध्यम से लेखपाल कार्यपालक सहायक के पद पर रख लिए, बोर्ड में लिए गए निर्णय बिंदुओं को अनुपालन नहीं कर मनमानिक तरीके से सभी कार्यों को अवरूद्ध कर कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा किया जाता है, जिससे वार्ड पार्षद क्षुब्ध रहते हैं, बोर्ड की बैठक की कार्यवाही पंजीकरण के द्वारा सत्यापन नहीं

किया जाना घोर अनिमियता दर्शाता है, कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा कार्यालय से निर्गत पत्र एवं कार्यवाही किसी भी वार्ड पार्षद ,मुख्य पार्षद ,उप मुख्य पार्षद को नहीं देती है, जिससे पार्षदों को पता चले की किस योजना का चयन और क्रियान्वयन कब किया जा रहा है वार्ड पार्षदों को कहना है कि बोर्ड के बैठक की कार्यवाही में अंकित प्रस्ताव में रहने के बावजूद भी पूरे नगर पंचायत क्षेत्र में सफाई नगण्य है, सफाई का काम आउटसोर्सिंग के माध्यम से होना है, लेकिन जब टेंडर की प्रक्रिया पूरी नहीं होने पर, साफ सफाई का कार्य दैनिक मजदूरों के द्वारा एक माह तक किया गया था, लेकिन सफाई कर्मी को आज तक कोई भी पेमेंट नहीं मिला, जिसके वजह से सफाई कर्मी हड़ताल पर चले गए थे, और पूरा वजीरगंज नगर पंचायत गंदगी से जुझ रहा था, गंदगी से बज बजाती नालियां, से गंभीर बीमारियां होने का आशंका बनी रहती थी,मुख्य पार्षद और अन्य पार्षदों द्वारा कई बार पहल कार्यपालक पदाधिकारी के करने का प्रयास किया ताकि वजीरगंज नगर पंचायत भी विकसित स्वच्छ हो, लेकिन कार्यपालक पदाधिकारी के मनमानी रवैया और दबंग प्रवृत्ति से परेशान होकर उपमुख पार्षद न्याय हेतु आयुक्त महोदय गया को, जिलाधि कारी गया को नगर विकास एवं आवास विभाग के सचिव को अलग-अलग पत्र भेजकर विकास से वंचित करने वाली कार्यपालक पदाधिकारी को हटाने के लिए भी मांग किए हैं, दिए गए आवेदन में मुख्य पार्षद, ने अपने आवेदन में अपनी पीड़ा को इजहार करते हुए लिखा है कि जब से कार्यपालक पदाधिकारी डॉ अनुपा कुमारी नगर पंचायत में कार्यरत हुई है तब से

आज तक 3:00 बजे के पहले कार्यालय नहीं आती है, जब मन होता है तब आती है, जब नहीं होता है तो चली जाती है, कार्यपालक पदाधिकारी मुझे अनुसूचित जाति होने के वजह से काफी भेदभाव रखती है, जब भी मैं दूरभाष पर बात करना चाहता हूं तो मुझे बराबर डांट फटकार कर देती है, मुझ पर निगरानी रखने हेतु मेरे कार्यालय कछ में मेरे अनुमति के बिना सीसीटीवी कैमरा लगा दी है, लेकिन वह सीसी टीवी कैमरा किन के आदेश से मेरे कक्ष में लगाई है इसका उत्तर जानने के लिए मैंने पत्र भी लिखा लेकिन मुझे अब तक कोई जवाब नहीं मिला है, वजीरगंज नगर पंचायत में स्वच्छता पखवाड़ा मनाने के लिए किसी वार्ड पार्षद मुख्य पार्षद उपमुख पार्षद को कोई भी सूचना नहीं दी, केवल पेपर पर स्वच्छता पखवाड़ा मैडम और उनके सहयोगियों के द्वारा मनाया गया है, बोर्ड के बैठक करने के लिए कई बार पत्र लिखने के बाद भी कार्य पालक पदाधि कारी दिलचस्पी नहीं लेती है, और जो पूर्व में बोर्ड के द्वारा लिया गया फैसला था फैसलों को को भी कार्यपालिका पदाधि कारी ने कार्यरूप नही दिया, हद तो तब हो गई वजीरगंज नगर पंचायत में 7 छठ घाट है, लेकिन छठ जैसे महापर्व में भी किसी भी छठ घाट पर साफ सुथरा प्रकाश की व्यवस्था नहीं करवाई गई, नगर विकास विभाग द्वारा छठ घाटों के समुचित साफ सुथरा सफाई , रोशनी और विकास के लिए 3 लाख रु0 भी भेजा गया था, उसके बाद भी छठ जैसे महापर्व पर कोई भी राशि कार्यपालक पदाधिकारी के द्वारा नहीं किया गया, जब कार्यपालक पदाधिकारी के द्वारा छठ घाटों में उपेक्षा से परेशान होकर मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद समाजसेवियों और पूजा समिति के द्वारा प्रकाश की व्यवस्था एवं साफ सफाई की व्यवस्था कराई गई, वजीरगंज प्रखंड के समाजसेवी और मुख्य पार्षद के प्रतिनिधि काका जी कहते हैं कि हर डाल पर उल्लू बैठा है, परवाह किसे इस गुलशन की, आज कार्यपालक पदाधिकारी के मनमाने रवैया से वजीरगंज नगर पंचायत विकास से अवरुद्ध है और तो और कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा प्राइवेट कर्मी को लेखपाल बनाते हैं, अवैध बहाली करने का इनकी सदैव दिलचस्पी रही, स्थिति चाहे जो कार्यपालक पदाधिकारी और पार्षदों की स्वाभिमान की लड़ाई से विकास कार्य वजीरगंज नगर पंचायत का प्रभावित है, अब तो वक्त ही बताएगा की मुख्य पार्षद द्वारा गया के जिलाधिकारी महोदय, आयुक्त महोदय, नगर विकास विभाग के सचिव, को दिए गए आवेदन के आलोक में कार्यपालक पदाधिकारी को हटाया जाता है या नहीं, या फिर जिले के वरिष्ठ पदाधिकारी मुख्य पार्षद कार्यपालक पदाधिकारी को सामंजस्यता लाकर विकास कार्य करने के लिए पहल करते हैं या नहीं यह तो वक्त ही बताएगा, लेकिन एक साल चुनाव होने के बाद भी विकास के लिए तरस रहे हैं वजीरगंज नगर पंचायत की जनता।। अगले अंक में बहुत कुछ खुलासा होगा।●

आईपीएस विकास वैभव के राष्ट्र निर्माण की मुहिम को मिला अपार जन समर्थन

लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान के आह्वान पर हुआ वृहत जन संवाद कार्यक्रम का आयोजन
पचास हजार से अधिक लोगों ने लघुवादों से दूर रहकर लिया बिहार निर्माण का संकल्प

● **मिथिलेश कुमार**

जिले के जीडी कॉलेज ,बेगूसराय में लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान के माध्यम से नमस्ते बिहार कार्यक्रम आयोजित किया गया। पहली बार मुक्त आकाश में बृहत जन संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बेगूसराय के सभी प्रखण्डों के सभी पंचायतों से लोग जीडी कॉलेज आएं। ऐसा अनुमान किया जा रहा है कि लगभग 55 हजार लोगों की भीड़ ने गगनभेदी नारे के साथ आईपीएस विकास वैभव का उत्साह बढ़ाया। पहली बार किसी सामाजिक अभियान के माध्यम से इतने वृहत पैमाने पर जन जागृति का प्रयास किया गया। लघुवादों से दूर रहकर, लोगों को नव बिहार निर्माण का संकल्प दिलाने की शुद्ध विचारों को व्यक्त करने के कारण और लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान से प्रभावित होकर करोड़ो लोगों का समर्थन विकास वैभव को बिहार में मिलने लगा हैं। हजारों युवा जीडी कॉलेज बेगूसराय हाथों में तिरंगा झंडा लिए कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे थे। संवाद कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए आईजी विकास वैभव ने कहा कि युवाओं का दिनकर की जन्मभूमि से शंखनाद हुआ किस प्रकार से युवाओं का भविष्य उज्ज्वल हो इस गम्भीर मुद्दे पर आज बिहार में सबसे ज्यादा चिंतनशील लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान है। इसका असर यह हुआ है कि राष्ट्र निर्माण के लिए बिहार के युवा प्रेरित होने लगे हैं। लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान के मार्गदर्शक आईपीएस विकास वैभव की प्रेरणा से अब तक 75000 लोग वाट्स अप के माध्यम से जुड़ चुके हैं। लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान के द्वारा अब तक 35 जिलों में लगभग 1000 से ज्यादा कार्यक्रम आयोजित किया जा चुका हैं। बेगूसराय के लोगों की आंखे कार्यक्रम के दौरान आईपीएस विकास वैभव पर टिकीं दिखी। सभा स्थल पर

बिहार के वैभव से होगा राष्ट्र का विकास

लेट्स इंस्पायर बिहार के संस्थापक आईपीएस विकास वैभव का ईमानदारी से दिया गया संदेश आज तीव्रता से जन.जन का संदेश बनता जा रहा है। लोगों को बेहद गर्व हो रहा कि आईपीएस विकास वैभव बेगूसराय के लाल हैं और युवाओं के लिए चिंतनशील हैं। बिहार के कई प्रखंडों में लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान का कार्यक्रम अब तक सफलता से हो चुका है। इसी क्रम में आईपीएस विकास वैभव के द्वारा शुक्रवार को पटना के होटल मौर्या में एक प्रेसवार्ता किया गया। जहां, आईपीएस विकास वैभव ने कहा कि किसी सामाजिक अभियान के द्वारा पहली बार इतने बड़े पैमाने पर आयोजन को किया जा रहा हैं। यह सुखद है कि बिहार के लोगों का समर्थन इस कार्यक्रम को मिल रहा हैं। खास तौर से, महिलाओं और युवाओं में अभियान को लेकर अत्यधिक उत्साह हैं। उन्होंने कहां कि बिहार में शिक्षा, समता और उद्यमिता के विकास से ही बिहार सुंदर राज्य बनेगा और, अपने पुराने गौरव को प्राप्त करेगा। इसी के तहत बिहार के अब तक 35 जिलों में युवा संवाद किया जा चुका है। पहली बार बृहत जन संवाद जीडी कॉलेज बेगूसराय में किया जा रहा है। लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान के अंतर्गत बिहार के सभी जिलों में, भारत के महानगरों में तथा विदेशों में अभी तक सभागारों में हुए सहस्राधिक (1000+) कार्यक्रमों के पश्चात 10 दिसंबर को जीडी कॉलेज बेगूसराय में बृहत जन संवाद हो रहा है। लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान के अंतर्गत प्रथम बृहत जन संवाद में सभी के लिए संदेश है नमस्ते बिहार! उद्देश्य है जातिवाद, संप्रदायवाद, लिंग भेद आदि लघुवादों से मुक्त उज्ज्वलतम उत्कर्ष पर स्थापित अपना बिहार हो! इस संदेश का असर व्यापक रूप से बेगूसराय के लोगों में होने लगा हैं। विकास वैभव ने बिहार वासियों से 10 दिसंबर 2023 को दोपहर 11 बजे जीडी कॉलेज आने का आह्वान किया था। लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान के गार्गी चौप्टर की स्टेट कोर्डिनेटर डॉ प्रीति बाला ने कहा कि बिहार के विभिन्न विधानसभा, प्रखंडों, पंचायतों का भ्रमण करने पर सुखद संदेश प्राप्त हुआ है। लोग आईपीएस विकास वैभव द्वारा मार्गदर्शित अभियान से जुड़ने के लिए उत्सुक हैं। हर्ष के साथ 10 दिसंबर को जीडी कॉलेज आयेंगे और लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान के अंतर्गत होने वाले नमस्ते बिहार कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। कार्यक्रम को लेकर वैसे तो बिहार के सभी लोगों में उत्साह है पर, युवाओं के अंदर ज्यादा है। वे खासतौर से, आईपीएस विकास वैभव को सुनने के लिए और उनसे प्रेरणा लेने के लिए जीडी कॉलेज आयेंगे। इस अवसर पर अभियान के मीडिया प्रमुख अनूप नारायण सिंह ने सभी पत्रकारों एवं उनके माध्यम से पटना समेत पूरे बिहार के लोगों को न्योता देते हुए कहा कि आप सब जीडी कॉलेज में आइए और कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग हेतु अपनी सकारात्मक भूमिका निभाईए। कार्यक्रम में 10 दिसंबर को भोजपुरी गायक प्रमोद प्रेमी यादव गोलू राजा राकेश मिश्रा भवानी पांडे समेत दर्जनों बिहार के कलाकारों का भी वहां कार्यक्रम होना है। पटना से 200 गाड़ियों के काफिले के साथ 10 दिसंबर को प्रातः 7:00 बजे प्रस्थान होना है। उम्मीद है कि यह आयोजन आप सबकी उपस्थित से ऐतिहासिक होगा और, बिहार के वैभव से होगा राष्ट्र का विकास। मौके पर आदर्श आशीष श्यामल अहमद एके झा इंजीनियर कुमार राहुल उपस्थित थे।

मौजूद कई लोगों ने कहां कि आईपीएस विकास वैभव बिहार निर्माण का नेक प्रयास कर रहे है। विकास वैभव ने सभा स्थल पर मौजूद लोगों को ''मैं बदलूंगा बिहार, मैं करूंगा अपने पूर्वजों की भूमि का पुनरुद्धार'' का संकल्प दिलाया। उन्होंने कहा कि जब तक हम लघुवाद के नाम पर एक दूसरे के टांगों को खींचते रहेंगे बिहार का विकास संभव नहीं हो सकता है। इसलिए, संघर्ष नहीं सहयोग की नीति को अपनाना होगा। विकास वैभव द्वारा दिए गए संकल्प से सम्पूर्ण सभा स्थल गुंजायमान हो गया। मंच पर षबिहार के विभिन्न हिस्से से आए 50 सम्मानित सदस्यों ने

विकास वैभव का स्वागत किया। जिला समन्वयक ब्रजेश कुमार, युवा समाजसेवी अंकित, प्रियम, रणधीर, मृणाल और कैलाश सिंह के नेतृत्व में राष्ट्र कवि दिनकर के घर की मिट्टी से विकास वैभव को तिलक लगाया। 6000 के आस पास महिलाएं और छात्राएं भी सभा स्थल पर मौजूद रहीं। लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान के स्टेट कोर्डिनेटर राहुल कुमार सिंह ने कहा कि बिहार के जेल में सबसे ज्यादा 18 से 30 वर्ष के युवा कैदी हैं। बिहार के युवा भटक रहे हैं। यह चिन्तन का विषय है। युवाओं के भविष्य के लिए लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान साकारात्मक भूमिका में हैं और एक ईमानदार प्रयास कर रहा हैं। कार्यक्रम का स्वागत भाषण बेगूसराय लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान के मुख्य कोर्डिनेटर प्रभाकर कुमार राय ने किया। कार्यक्रम का संचालन प्रसिद्ध एंकर पल्लवी विश्वास ने किया। इस अवसर पर प्रमुख कलाकारों के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। ●

बिहार के भाजपाई को माला पहनने से फुर्सत नहीं!

● **डॉ० लक्ष्मीनारायण सिंह**

बिहार के भाजपाई को नारे लगवाने माला पहनने से फुर्सत कहां है कि सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को गांव,और मोहल्ले तक पहुंचाएं। भाजपा मीडिया प्रभारी डॉ लक्ष्मी नारायण सिंह पटेल ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता बढी है। उन्होंने कहा कि बीते दो आम चुनाव में देखा गया है कि जनता नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट देती है और उनकी लोकप्रियता में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया है। विपक्ष के लिए आगामी लोकसभा चुनाव 'करो या मरो' वाली स्थिति में है क्योंकि यदि तीसरी बार भाजपा सत्ता में आए तो हम लोग की राजनीति समाप्त हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने एनडीए सांसदों से कहा है कि 40 सीटों को जीतने में कोई कसर न रहे। उन्होंने बिहार के 27 सांसदों से मुखातिब थे। उन्होंने सांसदों से उनके लोकसभा क्षेत्रों का फीडबैक लिया। उन्होंने चुनाव की तैयारी को ले कई टिप्स दी। जिए प्रधानमंत्री का कहना था कि सांसद जनता के बीच जाएं, उनको केंद्र सरकार के काम बताए,लोगों को बताएं बताया जाए कि बिहार में विकास का उछाल देने में केंद्र की कितनी ज्यादा भूमिका है। प्रधानमंत्री अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर बैठक कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पब्लिक से संपर्क में रहें सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें। उन्होंने स्पष्ट कहा कि पब्लिक से बहुत गहरे संपर्क में रहे। उन्होंने कहा कि लोगों के सुख-दुख उनके शादी-विवाह त्योहार आदि से सरोकार बनाए रहे, इन कार्यों में शामिल होकर उनसे बहुत आत्मीयता से बात करके दुख की स्थिति में लोगों की अधिक से अधिक मदद की जाए। प्रधानमंत्री ने कहा कि विपक्ष द्वारा फैलाए जा रहे भ्रम को हर हाल में खत्म किया जाए। डॉ लक्ष्मी नारायण सिंह पटेल ने कहा कि बिहार के भाजपाइयों को पहचान करना बड़ा मुश्किल सा हो गया है। पहचान पोशाक से करें या चरित्र से करें। उन्होंने कहा कि अधिकांश बैठकों कि खानापूर्ति की जा रही है। 13 जुलाई को सरकार द्वारा कार्यकर्ताओं को पीटाई के विरुद्ध हस्ताक्षर अभियान चलाने की योजना थी। हस्ताक्षर अभियान चलाया गया कि नहीं चलाया गया। चलाया गया तो कब चलाया गया। मोदी जी द्वारा योजनाएं चलाई जा रही है परंतु अधिकांश योजनाएं बिहार सरकार की फाइलों की शोभा बढ़ा रही है। इस संदर्भ में अधिकांश सांसदों, विधायकों एवं संगठन के बड़े-बड़े पद पर बैठे पदाधिकारियों का कोई चिंता नहीं है जैसे लगता है कि सारी योजना मोदी जी का फिजूल योजना है। लक्ष्मी नारायण सिंह पटेल ने कहा योजनाओं को घर-घर पहुंचा कर संगठन को मजबूत किया जा सकता है। उदाहरण स्वरूप कुछ योजनाओं का आंकड़ा दे रहे हैं। प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना ,प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, प्रधानमंत्री जन औषधि योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षित सड़क योजना प्रधानमंत्री ग्रामीण परिवहन योजना राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा अभियान, प्रधानमंत्री ग्रामीण परिवहन योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा अभियान ,सौर सूजला योजना, प्रधानमंत्री युवा योजना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल, साक्षरता अभियान, मेक इन इंडिया स्वच्छ भारत अभियान, किसान विकास पत्र ,डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना आदि अनेकों योजना चलाई जा रही है अधिकांश योजनाएं लूट मची हुई है। पत्रकारों मीडिया प्रभारी एवं कार्यकर्ताओं को योजनाओं का सूची उपलब्ध नहीं कराई जा रही है और नहीं लाभार्थियों की सूची दिलवाई जा रही है। बिहार के अधिकांश सांसद विधायक अपने कार्यों पर जीत का कोई भरोसा नहीं है सिर्फ मोदी पर भरोसा रह गया है।●

बिहार पर बढ़ते कर्ज हर दिन 45 करोड़ रूपये सूद

● **डॉ० लक्ष्मीनारायण सिंह**

बिहार की खजाने की स्थिति ऐसी है कि सरकार के पास फिलहाल कर्ज लेकर अर्थव्यवस्था को गति देने के बदले दूसरा विकल्प निकालना पड़ेगा। वर्तमान में इस तिमाही मार्च तक राज्य सरकार हर हफ्ते दो हजार करोड़ कर्ज ली है और आगे बढ़ेगी। रिजर्व बैंक से और कर्ज रुपए ऋण लेने की तैयारी है। आमदनी का बड़ा हिस्सा ब्याज में देना पर रहा है। 2022 -23 मई सुद चुकाने के लिए 16,305 करोड़ देना पड़ रहा है। यानी हर दिन 45 करोड़ सुद के रूप में देना पड़ रहा है। बिहार में हर बच्चे 19 हजार रुपए कर्ज के साथ जन्म लेता है। यह कर्ज नहीं उसके पिता न ली है और नहीं उसके किसी अन्य परिजनों ने ली है इसके बाद भी वह जन्म के साथ कर्जदार है। डॉ० लक्ष्मी नारायण सिंह पटेल ने कहा है कि सरकार कर्ज न ले तथा कर्ज घटाने के लिए विधायक 75% वेतन घटाए तथा सारी सुविधाएं बंद करें बिजली, पानी, हवाई जहाज, ट्रेन मोबाइल आदि का उपयोग मुफ्त में न करें साथ ही सरकारी कर्मचारियों को वेतन 30/40 हजार सीमित करें। बेवजह विभाग को बंद करें। तथा 30/40 हजार रुपए वेतन पर दरोगा, डीएसपी, एसपी बीडीओ, सीओ, सडीओ, जिलाधिकारी, शिक्षक, प्रोफेसर आदि के लिए वैकेंसी निकालें। करोड़ों बेरोजगार कम वेतन पर भी नौकरी के लिए तैयार हो जाएंगे। इस से वेरोजगारी दूर होगी। कितना मजाक है धकि एक भाई दाने- दाने को मोहताज है और एक भाई गाड़ी और महल का कतार सजाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि पति और पत्नी में एक ही का नौकरी हो। कर्ज लेकर वेतन दे और ले यह सरकार बंद करे।●

मोदी का अंतरिक्ष की ओर बढ़ते कदम

● त्रिलोकी नाथ प्रसाद

भाजपा मीडिया प्रभारी डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सिंह पटेल ने भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा की भारत की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अंतरिक्ष की ओर बढ़ते कदम का पूरे दुनिया में सराहा जा रहा है। इस कदम में सबसे बड़ा श्रेय 140 करोड़ जनता का ताकत और वैज्ञानिकों का है।अंतरिक्ष खोज में तेजी से आगे बढ़ते भारत का चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर दुनिया के अब तक के सबसे कम लागत वाले सफल चंद्रयान 3 के बाद अगला अभियान गगनयान है। अंतरिक्ष के इस अगले मिल का पत्थर मिशन में वीनस ऑर्बिटल मिशन, मंगल ग्रह लैंडर, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन और 240 तक पहला भारतीय चंद्रयान पर उतरने का लक्ष्य है। दुनिया की छठी सबसे बड़ी अंतरिक्ष एजेंसी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने चंद्रयान 3 पर सिर्फ 613 करोड रुपए (74 मिलियन डॉलर) खर्च किए गए जो 2019 के असफल चंद्रयान दो की लागत 200 मिलियन डॉलर से आगे से भी काम है। चीन ने 2022 में मिशन मून पर 12 अरब डॉलर खर्च किए। दुनिया की सबसे बड़ी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने अपने चंद्रमा कार्यक्रम पर बजट के बीच अपने भावी चंद्रमा मिशन के लिए अब इसरो से मदद मांगी है। चंद्रयान 3 की सफलता ने भारत के अंतरिक्ष उद्योग को ऐसे मुकाम पर पहुंचा है जिसने देश की साइंस एंड इंजीनियरिंग सेक्टर को तमाम देशों के अंतरिक्ष मिशन के मुकाबले में सबसे आगे ला खरा किया है।

1960 के दशक में चंद्रमा अज्ञात इलाके की खोज के लिए अमेरिका और रूस के बीच अंतरिक्ष दूर के उलट मौजूदा हालात एकदम अलग है। आज अंतरिक्ष खोज एक मुकाबले के उद्योग के रूप में तेजी से आगे बढ़ रही है जिसमें प्राइवेट सेक्टर की भूमिका बस्ती जा रही है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पानी और बर्फ की मौजूदगी से यह प्रोटेक्शन की दृष्टि से भी भविष्य की चंद कॉलोनीयों के रूप में देखा जा रहा है। दुनिया की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में सिर्फ दो प्रतिशत हिस्सेदारी के बावजूद भारत की कॉस्ट इफेक्टिव इंजीनियरिंग ने अमेरिका जैसी महाशक्ति जिसकी अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में 40% हिस्सेदारी है का ध्यान अपनी और आकर्षित किया है। कोई शक नहीं कि चंद्रयान की सफलता भारत के अंतरिक्ष कारोबार के लिए मिल का पत्थर साबित होगी। साल 2040 तक दुनिया की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था 546 अरब डॉलर से बढ़कर 1000 अरब डालर

होने की संभावना है। अगले एक दशक में दुनिया की अंतरिक्ष बाजार में अपने हिस्सेदारी 5 गुना बढ़ाने के लिए भारत में इस विदेशी पूंजी निवेश के लिए भी खोला है। अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत का मौजूदा आठ अरब डॉलर का कारोबार प्रति वर्ष लगभग 4% से बढ़ रहा है। जबकि ग्लोबल बाजार की वृद्धि दर को दो प्रतिशत है । साल 2040 तक 40 अरब डालर होने की संभावना है। दुनिया के अंतरिक्ष उद्योग में तेजी से आगे बढ़ता भारत इस सेक्टर में रोजगार के नए अवसर भी बढ़ रहा है।●

महिला को गिरफ्तार करने से पहले सौ बार सोचना चाहिए!

● त्रिलोकी नाथ प्रसाद

भाजपा मीडिया प्रभारी डॉ लक्ष्मी नारायण सिंह पटेल ने पुलिस अधिकारियों से कहा है कि महिलाओं को गिरफ्तार करने के पहले सौ बार सोचना चाहिए। महिलाओं का गिरफ्तारी अब आम बातें हो गई है, जबकि जिस घटना से महिला को दूर तक कोई संबंध नहीं है। बताया जाता है कि बाढ़ थाना क्षेत्र के मलाही गांव के निकट घर में घुसकर युवक जितेंद्र को जख्मी करने के मामले में दो मुकदमे दर्ज किए गए हैं जबकि एक कट्टा और 4 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। इस केस में महिला समेत दो व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार गिरफ्तार खुशबु कुमारी का घटना से कोई लेना-देना नहीं है। बताया जाता है कि तिलक दहेज के मामले में अधिकांश घटना पति-पत्नी के बीच घटना होती है। पति द्वारा हत्या कर दी जाती है या आत्महत्या करने के लिए

विवश हो जाती है। ऐसे स्थिति में पति के खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए।घटना के बाद मृतक के 80 साल के सास,90 साल के ससुर,जिस भैसुर, देवर से दूर-दूर तक घटना से कोई मतलब नहीं है उसे भी घटना में मुकदमा दर्ज कर ली जाती है इतना ही नहीं जिस गोतनी एवं नन्द से इस घटना से कोई संबंध नहीं रहने के बावजूद मुकदमा दर्ज कर ली जाती है। पुलिस को अनुसंधान के बाद ही गिरफ्तार करनी चाहिए। बताया जाता है कि पुलिस के बड़े-बड़े अधिकारी बगैर घटना स्थल पर गए हुए निर्दोष के विरुद्ध भी सुपरविजन रिपोर्ट में दोषी बना दी जाती है। जिसके कारण निर्दोष भी जेल के शिकंजे में कैद हो जाती है। पुलिस को निर्दोष साबित करने में एक दिन भी नहीं लगती है जबकि न्यायालय में निर्दोष को साबित करने में दो-तीन दशक भी लग सकती हैं। ऐसे स्थिति में महिला हो या पुरुष जेल भेजने से पहले सौ बार सोचना चाहिए। कहीं निर्दोष को तो हम नहीं जेल भेज रहे हैं।●

किसान रोड मैप, किसान के समझ से परे

किसानों का दर्द : कर्ज से भोजन, इलाज और पढ़ाई

● डॉ० लक्ष्मीनारायण सिंह

भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था कि नौजवानों और किसानों की देश के प्रति सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। सेना का सरहद की सुरक्षा करना और किसानों को भोजन का इंतजाम करना। दोनों को संपन्न होना अति आवश्यक है। दुर्भाग्य से लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो गई। आज किसानों की ऐसी दुर्दशा है कि खेती करना नहीं चाहता जिसका कारण है कि खेती करना भारी नुकसान देह है दूसरी ओर कभी जल सैलाब तो कभी सुखाड़ से जुझना पड़ता है, जिसके कारण कर्ज से ही खाद ,बीज,भोजन, इलाज, पढ़ाई ,शादी आदि का इंतजाम करना पड़ता है। कर्ज के कारण धीरे-धीरे खेत बिक्री होते जा रहा है। किसानों के जीवन में चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा झलक रही है। किसान संगठन अनगिनत मिल जाएंगे जिन्हें किसान की समस्याओं से कोई लेना-देना नहीं उन्हें सिर्फ राजनीति चमकाना है। डॉ लक्ष्मी नारायण सिंह पटेल ने कहा कि सरकार को चाहिए कि100 रुपए किलो सभी अनाज खरीद कर बाजार में उचित मूल्य पर दे। ऐसी स्थिति में सवाल उठता है कि सरकार पैसा कहां से लाएगा। सरकार राशन में जो 2/3 रुपए किलो के हिसाब से देती है तथा स्कूल में, आंगनवाड़ी मुफ्त में देती है तो क्या किसान मुफ्त या 2/3 रुपए किलो देती है। सरकार 25/30 रुपए खरीद करती है तथा मुफ्त में देती है।पैसे के इंतजाम के लिए सर्वप्रथम विधायक सांसद, मंत्री को वेतन बंद या कम कर देना चाहिए। तथा सभी नौकरी वाले को आधा कर देना चाहिए। ज्यादा वेतन वाले आईएएस, आईपीएस को 40 /45 हजार महिना फिक्स कर देना चाहिए। उसी पैसे से अनाज खरीदा जा सकता है तथा 25/30 रुपए किलो अनाज बाजार में दिया जा सकता है। ऐसी योजनाओं से नौकरी छोड़कर खेती की ओर लोग आना चाहेंगे। खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार को प्रयास इसी तरह करना चाहिए। यदि बीडीओ, सीओ, आईएएस, आईपीएस, शिक्षक, प्रोफेसर आदि 40 हजार रुपए महीना पर काम करना नहीं चाहे ,तोघ सरकार वैकेंसी निकाले, लाखो लोग दौड़ पड़ेगें।

भाजपा मीडिया प्रभारी डॉ लक्ष्मी नारायण सिंह पटेल ने कहा कि बिहार सरकार द्वारा तीन बार कृषि रोड मैप लागू होने के बाद भी बिहार के किसान आमदनी के मामले में 28 में स्थान पर क्यों ! उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा की बिहार सरकार तीन बार कृषि रोड मैप पर लगभग तीन लाख करोड़ खर्च करने के बाद भी खद्यान उत्पादन दोगुना करने के लक्ष्य भी धरे के धरे रह गए। इतने पैसे में हर खेत में नहर बन जाता और सोलर प्लेट लग जाता है। पंजाब के किसानों को औसत आय 26 हजार 700 है, जबकि बिहार की किसानों की औसत प्रति व्यक्ति 7 हजार 542 रुपए है। बताया जाता है कि तीसरी कृषि रोड मैप पर 5 साल में 1.4 लाख करोड़ खर्च करने का लक्ष्य था जबकि एक लाख करोड़ रुपए भी खर्च नहीं कर पायी। पहले वाले खर्च नहीं हुआ और अब चौथे किसी रोड मैप के नाम पर 1.62 लाख करोड़ खर्च करने के लिए कोई औचित्य नहीं रह गया। बताया जाता है की तीसरी कृषि रोड मैप में जैविक कॉरिडोर का निर्माण को चालू करने और अलग कृषि फीडर लगाकर 8 लाख नए सिंचाई कनेक्शन देने जैसे लक्ष्य अभी तक क्यों नहीं पूरा किया गया। यदि सरकार के रजिस्टर में पूरा हो गया है तो कार्यो की सूची हर एक गांव में दीवारों पर चिपकाई जाए। उन्होंने कहा कि रोड मैप का भाषण जैसे हिंदी जानने वालों को अंग्रेजी में भाषण सुनाया जा रहा है, ऐसे भाषण महत्वहीन हो जाता है उन्होंने कहा कि जानकारी मिला है हरेक साल कि भांति किसानों के लिए आया हुआ बीज गैर किसानों को बांट दी जाएगी। उन्होंने कहा कि पिछले साल वाले बीच वितरण की सूची प्रखंड में टांगी जाए।●

एक्सीडेंट में भारत नंबर वन

अप्रशिक्षित चालकों के कारण बढ़ा है सड़कों पर जोखिम

● डॉ० लक्ष्मीनारायण सिंह

एक्सीडेंट में भारत वनः है। यह मैं नहीं बल्कि भारत के ट्रांसपोर्ट मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है। उन्होंने कहा कि एक्सीडेंट में हम नंबर वन हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया में ऐसे भी देश हैं जहां जीरो एक्सीडेंट होता है। जब मैं विदेश कॉन्फ्रेंस में जाता हूं मुझे बड़ा दुख होता है। मैं उसे देश से आया हूं जहां सबसे ज्यादा एक्सीडेंट होता है, जहां का मैं ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हूं यह बहुत ही गंभीर समस्या है। सड़क हादसों में कमी आने में बड़ों से उम्मीद कम ही रही है, लेकिन बच्चों से यह उम्मीद जरूर की जा सकती है। अब जागरूक होंगे। मेरा शिक्षकों से आवाहन है कि वे बच्चों को सड़क सुरक्षा के प्रशिक्षित करने में सहयोग करें। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने एक स्कूल के कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम में उन्होंने अपने मन की बात रखी की रोड सेफ्टी बड़ी समस्या है। प्रतिवर्ष 5 लाख एक्सीडेंट होते हैं डेढ़ लाख लोगों की मौत हो जाती है। डेढ़ लाख लोगों के हाथ –पैर टूट जाते हैं। इससे जीडीपी का 3% का नुकसान होता है। इनमें मरने वाले युवकों की 18 से 34 वर्ष के बीच होती है। कोई इंजीनियर होता है ,तो कोई डॉक्टर होता है इतने लोग किसी लड़ाई में भी नहीं मरते? उन्होंने कहा कि इन एक्सीडेंट को कम करने के लिए हमने रोड इंजीनियरिंग और ऑटोमोबाइल में काफी बदलाव किया, हमने इनफॉरमेशन में भी बदलाव की है और जुर्माना भी बढ़ाया लेकिन महत्वपूर्ण है मानव स्वभाव जब तक मन सेट नहीं बदल सकते तब तक एक्सीडेंट रुक नहीं सकता। मांइड सेट में यह लाना होगा की रेट लाइट पर पार नहीं करूंगा वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात नहीं करूंगा ,टु व्हीलर पर हेलमेट जरूरी लगाऊंगा। बड़ी गाड़ी है तो लेने ड्राइविंग का पालन करूंगा। डॉ लक्ष्मी नारायण सिंह पटेल ने कहा कि अपने प्राण रक्षा के लिए हेलमेट अति आवश्यक है लोग लगाना नहीं चाहते। यदि सरकार घोषणा कर दे कि हेलमेट स्वेच्छा से लगाए, कानूनी प्रतिबंध नहीं हो। तो वैसे स्थिति में 90/95 प्रतिशत लोग हेलमेट का उपयोग नहीं करेंगे। हेलमेट कानून के भय से लगाते हैं। यहां तो पुलिस भी बगैर हेलमेट के मिल जाएंगे, उन्हें कौन रोकेगा। सड़क पर वाहन चलाने वालों में 90% से ज्यादा वगैर ट्रेनिंग के होते हैं।

केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की गाइडलाइन के अनुसार कोई ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल बने इसमें 3 से 18 एकड़ भूमि श्रेणी के अनुसार प्रजापत पार्किंग एरिया कम से कम 2 क्लास रूम, प्रशिक्षण में सहयोग करने वाली सामग्री जैसे कंप्यूटर, मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर, ड्राइविंग ट्रेक ,वर्कशॉप आदि होने चाहिए। मोटर वाहन संशोधन कानून 2019 में आरटीओ कार्यालय में पारदर्शिता की पहल हो चुकी है लेकिन इससे ड्राइविंग की दशा सुधारने में कोई खास मदद नहीं मिली, क्योंकि ड्राइविंग का ढांचा ही नहीं बन पाया, केंद्र की सहायता से इंस्टीट्यूट फॉर ड्राइवर ट्रेनिंग एंड रिसर्च के रूप में राज्यों में इस तरह के कुछ संस्थान खुले हैं ,लेकिन इससे मुट्ठी भर लोग ही ड्राइविंग में प्रशिक्षित होकर निकल रहे हैं यह हाल तब है जब खुद केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने 78% हादसों का दोष ड्राइवरों की खामी की दिया है। इसी कमी को दूर करने के लिए केंद्र सरकार ने ड्राइवरों की ट्रेडिंग से जुड़े संस्थानों की स्थापना और उनकी गिनती के लिए दिशानिर्देश जारी किए और ड्राइविंग को वैज्ञानिक व्यवस्थित बनाने अमल की जरूरत जताई। हर साल लगभग साढ़े तीन करोड़ ड्राइविंग लाइसेंस जारी हो रहे हैं। इनमें 95% से ज्यादा वे लाइसेंसी हैं जिनमें किसी स्कूल से ड्राइविंग का प्रशिक्षण नहीं लिया गया है। आरटीओ में एक तो टेस्टिंग फुलप्रूफ व्यवस्था नहीं है और अगर जांच परख होती भी है तो केवल ड्राइविंग स्किल यानी कौशल की ,ज्ञान और विवेक कि नहीं। समस्या केवल सीखने वालों की नहीं सिखाने वालों की भी है। स्थिति यह है कि हमारे यहां इंस्ट्रक्टर भी सही तरह से प्रशिक्षित नहीं है। उन्हें खुद ही नियमों के साथ साइन सिग्नल की जानकारी नहीं होती। दूसरा सबसे बड़ा जोखिम है की नीमोछिया ड्राइवर से बढ़ गई है सड़क दुर्घटना है। नीमोछिया ड्राइवर से सड़क दुर्घटनाएं ज्यादा ही बढ़ गई है। नीमोछिया ड्राइवर इस तरह लहरिया कट में चलाते हैं कि सामने वाले वाहन चकमा खा कर आपस में टकरा जाते हैं जिससे कारण कई जानलेवा हादसा भी हो चुकी है। स्थानीय प्रशासन को ध्यान देने की आवश्यकता है।●

राज्यों को बिजली पर टैक्स लगाने का अधिकार नहीं

● डॉ० लक्ष्मीनारायण सिंह

भारत सरकार ने राज्यों से कहा है कि किसी भी राज्य को किसी भी स्रोत से उत्पन्न बिजली पर टैक्स या कोई अन्य शुल्क लगाने का अधिकार नहीं है। राज्यों की ओर से इस तरह का कोई भी शुल्क लगाना गैर कानूनी और असंवैधानिक है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय की ओर से 25 अक्टूबर को जारी सर्कुलर में कहा गया है कि राज्य कोयला, जल,पवन,सौर या परमाणु स्रोत से उत्पन्न हुई बिजली पर किसी भी तरह का कर नहीं लगा सकते हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य सरकारों ने विकास शुल्क की आर में विभिन्न स्रोतों से बिजली उत्पादन पर अतिरिक्त शुल्क लगा लिया है ।पत्र में कहा गया है कि संवैधानिक रूप से कर शुल्क लगाने की शक्तियां विशेष रूप से सातवी अनुसूची में आती है। डॉ लक्ष्मी नारायण सिंह पटेल ने बिहार सरकार से कहा है की अविलंब बेवजह टैक्स लेना बंद करें तथा पहले लिए हुए टैक्स को बिजली बिल में कटौती करें।●

जरासंध प्रतिमा का निर्माण शीघ्र करे पूरा : सीएम नीतीश

● अमित कुमार सिंह/अनिता सिंह

राजगीर में जरासंध महोत्सव में हिस्सा लिये नीतीश, प्राचीन मंदिर में पूजा-अर्चना कर राज्य के सुख्या, एवं समृद्धि की कामना की। मगध सम्राट जरासंध के 5226वी0 जयंती समारोह के अवसर पर आयोजित जरासंध महोत्सव 2023 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शामिल हुए। उन्होने महाराज जरासंध की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की और उन्हें नमन किया। राजगीर स्थित महाराज जरासंध के अति प्राचीन मंदिर में पूजा अर्चना कर जरासंध की कीर्ति ध्वज तथा स्तंभ का पूजन मुख्यमंत्री ने किया और राज्य में सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। जरासंध महोत्सव के अवसर पर अखिल भारतीय जरासंध अखाड़ा परिषद की ओर से मुख्यमंत्री को अभिनंदन पत्र एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर उन्हें स्वागत किया गया। इस अवसर पर सांसद चंदेश्वर प्रसाद चन्द्रवंशी ने जरासंध के सम्पूर्ण इतिहास के बारे में बताया और कहा कि जरासंध का इतिहास बड़ा गौरवशाली अतित रहा है। मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक वृहदर्थ मगध सम्राट के पिता थे। भारत के प्रथम चक्रवर्ती सम्राट जिसे दुनिया लोहा मानती है। उनकी भुजाओं में 10 हजार हाथी का बल था। पुराणों में वृहदर्श वंश के 16 से 22 शासकों का उल्लेख मिलता है। चन्द्रवंश के 24 शासकों ने लगभग 700 वर्षो तक मगध राज्य पर शासन किया। उन्होनें अपने पराक्रम से काशी, कौशल, चेदि, मालवा, विदेह, अंग, वंग, कलिंग, पाण्डय, सौबीर, मद्र, गान्धार ऐसे 84 राजाओं पर विजय प्राप्त की थी। इसलिए पुराणों में इन्हें महाबली तथा देवेन्द्र के समान तेज वाला कहा गया है। ऐतिहासिक ग्रन्थों में भी वर्णन आया है। इनके विजय अभियान से भयभीत होकर भारत के अधिकांश राजाओं को दक्षिण भारत में भागकर वसना पड़ा। यहाँ तक कि स्वयं श्री विष्णु के अवतार माने जाने वाले भगवान श्री कृष्ण को मथुरा से भागकर पश्चिमी समुन्द्र तट पर द्वारिका पूरी जाकर रहना ही नही पड़ा था। अपितु 'रणछोड़' ऐसी क्षत्रियों के लिए अपमान पदवी की धारण करनी पड़ी। श्री कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर का शंका का समाधान करते हुये यह कहा था महाराज स्वयं मैं विश्व के सभी राजा

और देवलोक के सभी देवतागण भी एक साथ दिव्य अस्त्र-शस्त्रों के साथ जरासंध से सम्मुख (आमने-सामने) युद्ध करे तो भी हम उन्हें तीन सौ वर्षो तक नही हरा सकते है। उनका वध शक्ति से नही युक्ति से ही संभव है। श्री कृष्ण के ये शब्द क्षत्रिय सम्राट जरासंध के पराक्रम रूपीतंजि स्विता का प्रमाण प्रस्तुत करता है। इन्हे कई अन्य नामो से भी जाने जाते थे। मगध नरेश, मगधापति शुरवीर, दानवीर, पराक्रमी उन्होने अपना चक्रवर्ती सम्राट के नामों से जाने जाते है। उन्होनें अपना पराक्रम से 275 राजाओं का बंदी बनाया था। ये बड़े ही धार्मिक प्रवृति के सम्राट थे। जो दान पूण्य, जप और देव पूजन में आस्था एवं विश्वास रखते थे। जब इन्हें ऐसा अनुभव होने लगा कि अधिमास की अवधि में इनके द्वारा किये जाने वाले पूण्य कार्यो में रूकावट आ जाती है, तब इन्होनें मंत्रों एवं धार्मिक अनुष्ठानों के द्वारा देवलोक (स्वर्ग) के सभी देवताओं का आहवान करके उन्हें गिरिव्रज की धरती पर बुलाया तथा उन्हें प्रसन्न करके यह वयन लिया कि प्रत्येक अधिमास की अवधि में देव लोक के सभी देवतागण राजगृह में विराजमान रहेंगे। तब से ही प्रत्येक मलमास की अवधि में देवलोग में निवास करने के स्थान पर अपने निवास स्थान राजगृह को ही देवलोक बना दिया गया। जरासंध भी शिव के परम भक्त थे। इन्होनें भगवान शिव को राजगृह में उतारा था। मगध से चन्द्रवंशियों का उदय हुआ। देश के प्रथम चक्रवर्ती सम्राट की शौर्य, दृढ़ता की गाथा आज भी लोग गाते है तथा अखिल भारतीय जरासंध अखाड़ा परिषद् के राष्ट्रीय महासचिव श्याम किशोर भारती ने मुख्यमंत्री को जरासंध की शौर्यता एवं वीरता का प्रतीक गदा भेंट किया। जरासंध महोत्सव में शामिल होने के पश्चात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राजगीर में सम्राट जरासंध की स्थापित की जा रही 20 फीट उँची प्रतिमा के निर्माण कार्य स्थल का जायजा लिया। इस दौरान अधिकारियों को निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि निर्माण कार्य में तेजी लाकर प्रतिमा स्थापित करने का कार्य अगले छः माह के अंदर पूर्ण कराये। सम्राट जरासंध के स्थापित होने वाली प्रतिमा स्थल की चारों ओर अच्छे ढंग से अधिकाधिक वृक्षारोपन कराने का निर्देश दिया। इसके साथ हीं यहाँ लोगो को बैठने की सुविधा भी सुनिश्चित कराने को कहा ताकि लोग यहाँ आये तो कुछ देर यहाँ बैठ सके। सम्राट जरासंध की प्रतिमा स्थल चारों तरफ से पानी से घिरा रहेगा। जिसको ध्यान में रखते हुए प्रतिमा स्थल तक लोगों को सुगमता

पूर्वक आवागमन हेतु पथ का निर्माण कराने का भी निर्देश दिया। श्याम भारती ने कहा कि मगध के शिल्पकार ये चक्रवती सम्राट जरासंध महाभारत चन्द्रवंशियो का इतिहास रहा है। छठवर्त की प्रथम प्रमाण महाभारत में पाण्डवो के द्वारा किये जाने का इतिहास मे प्रमाण मिलता है। जेठान पर्व जरासंध की जन्म दिवस पर मनाया जाता है। जरासंध ने 84 करोड़ देवता सहित शिव को राजगृह में उतारा था। तभी से अधिमास यानी मलमास मेला का आयोजन किया जाता है। इतिहास में मगध पर 5000 ई0 शासन का उल्लेख मिलता है। इस अवसर पर ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार, सांसद कौशलेन्द्र कुमार, विधायक डॉ सुनील कुमार, राकेश कुमार रौशन, कौशल किशोर, कृष्ण मुरारी उर्फ प्रेम मुखिया, विधान पार्षद श्रीमती रीना यादव, पूर्व विधायक शक्ति सिंह यादव, पूर्व विधान पार्षद राजू यादव, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त परामर्शी मनीष कुमार वर्मा, ओएसडी गोपाल सिंह, पटना के आयुक्त कुमार रवि पुलिस महानिरीक्षक पटना क्षेत्र राकेश राठी, पटना के डीएम चंन्द्रशेखर सिंह, नालंदा कमीशनर सुर्भकर पटना के वरीय पुलिस अधीक्षक राजीव मिश्रा, मिलन चन्द्रवंशी, लवकुश चन्द्रवंशी, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अमित सिंह चन्द्रवंशी, डॉ0 धर्मेन्द्र चन्द्रवंशी, डॉ0 ाच ेपदहीए कत रंल त सहित व्यक्ति और वरीय अधिकारी जरासंध महोत्सव में हिस्सा लिये। ●

डॉ. अमित कुमार वरुण ने किया नीट पीजी क्वालीफाई

● **मनीष कमलिया/राजीव कुमार**

नवादा जिले के वारिसलीगंज नगर परिषद क्षेत्र के सिमरी गाँव में पले बढ़े डॉ अमित कुमार वरुण ने ऑल इंडिया स्तर पर आयोजित मेडिकल पीजी की परीक्षा में सफल होकर अपने परिवार, गांव एवं प्रखंड का मान बढ़ाया है। कहा गया है कि सपना वो नही जो देखते हैं, सपना वह है जो चैन से सोने नहीं देती है। यूं कहें कि पंख से कुछ नही होता हौसलों से उड़ान होती है। मंजिले उन्ही को मिलती है जिनके हौसलों में जान होती है। मंजिल पर पहुंचने के लिए स्वयं पर भरोसा और दृढ़ निश्चय ही मंजिल पर पहुंचाता है। अमित बचपन से ही पढ़ने में काफी तेज थे। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा आयोजित माध्यमिक परीक्षा में जिला टॉपर रहने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ।गांव में प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद वारिसलीगंज स्थित श्री गणेश बीके साहू इंटर विद्यालय से मैट्रिक एवं वारसी कॉलेज पांडे गंगौट से इंटर साइंस करने के बाद अपने सपनों को उड़ान देने के लिए कठिन परिश्रम करना शुरू किया था। उन्होंने बताया कि मुझे बचपन से ही चिकित्सा के क्षेत्र में जाने की लालसा थी और मैं जिज्ञासु भी था। बंगाल के बेहतरीन मेडिकल कॉलेज में शुमार कलकत्ता मेडिकल कॉलेज से बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए एमबीबीएस करने के बाद मैं दरभंगा मेडिकल कॉलेज में पदस्थापित भी था, परन्तु मुझे आगे भी कुछ करने की तमन्ना थी जिसके कारण मैं राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होने वाली पीजी (नीट) की परीक्षा में शामिल हुए और सफल हुआ। परीक्षा में सफल होने के बाद डॉ अमित कुमार वरुण ऑर्थोपेडिक सर्जन (एमएस) बनकर फिलहाल बैंगलौर में सेवा देंगे। अपनी सफलता का श्रेय अपनी माता पिता एवं ननिहाल के परिवार को देते हुए उन्होंने कहा कि हालांकि मुझे आर्थिक तंगी का सामना नही करना पड़ा परन्तु परिवार में जब अच्छे मार्गदर्शक होते हैं तो करियर भी बेहतर होता है बशर्ते आप पूरी ईमानदारी के साथ अपनी पढ़ाई को पूरा करें। उन्होंने कहा कि पढ़ाई के दौरान कई बाधाएं भी आती है लेकिन बाधाओं से लड़कर आगे बढ़ने के लिए दृढ़ इच्छाशक्ति की जरूरत होती है। जीवन में आई संकटो से घबराने की कतई जरूरत नही है।जीवन संघर्षों का ही नाम है। डॉ० अमित की धर्मपत्नी डॉ० सुरुचि कुमारी भी दरभंगा

मेडिकल कॉलेज में प्रसूति रोग विशेषज्ञ के पद पर स्थापित हैं। पति के सफलता पर डॉ० सुरुचि सहित पूरा परिवार में खुशी का माहौल कायम है। दूरभाष पर बात करते हुए डॉ अमित ने बताया कि भबिष्य में हम दोनों पति पत्नी का उद्देश्य अपने क्षेत्र के लोगों के बीच जाकर उन्हें

चिकित्सकीय सेवा प्रदान करना है। उन्होंने कहा कि पत्नी भी काफी सकारात्मक है जो हमेशा सहयोग करती है। डॉ० अमित के बड़े भाई डॉ० जितेंद्र कुमार असिस्टेंट प्रोफेसर थे। वर्तमान में नालन्दा जिले के के.के. यूनिवर्सिटी (बेरोउंटी) में अस्सिटेंट डीन के पद पर कार्यरत हैं। वही पिता विपिन सिंह बिहार सरकार सेवा से रिटायर हो चुके है और बेटे की सफलता से काफी खुश हैं। माता श्री मति बेबी देवी कुशल गृहिणी हैं। हालांकि डॉ० अमित का पैतृक गावँ कतरीसराय प्रखण्ड अंर्तगत सैदी गावँ है लेकिन बचपन से ही अमित अपने ननिहाल सिमरी गावँ में रहकर ही अपने शैक्षणिक भविष्य को सँवारने का काम किया है। वारिसलीगंज स्थित मानस भारती आवासीय विद्यालय में प्राचार्य सुनील कुमार के सानिध्य में शैक्षणिक गुण भी प्राप्त किया।इनके बचपन के सहपाठी रहे शिक्षक अवनीश कुमार ने बताया कि डॉ० अमित कुमार वरुण इतने बड़े चिकित्सक बनने के बाद भी अपने पुराने मित्रों को याद करना नही भूलते जो इनके व्यक्तित्व की पहचान है। इनके सफलता पर इनके ननिहाल के परिवार सहित दर्जनों सगे सबन्धियों ने इन्हें बधाई एवं शुभकामनाएं दी है। ●

गायक गुंजन सिंह ने किया हण्डिया छठ मेले का उद्घाटन

● **अमित कुमार सिंह/अनिता सिंह**

मगध की पावन धरती जरासंध की नगरी ऐतिहासिक मंदिर छठ मेले का उदघाटन फिल्म अभिनेता गायक एवं लोक सभा के भावी प्रत्याशी के रूप में उपस्थिति दर्ज की मेले का उदघाटन फीटा काट कर एवं विधिपूर्वक द्वीप प्रज्जवलित कर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जब व्यूरोचीफ केवल साथ्च पत्रिमा के अमित कुमार सिंह ने उनके पूछा कि झिकरूआ कुछ दिनो की मंदिर को पर्यटन का दर्जा मिला लेकिन द्वापर यूगिन कृष्ण के पुत्र साम्य के द्वारा निर्मित सूर्य मंदिर आज तक बिहार पर्यटक स्थल के रूप में नही जुड़ी। केवल समपत्रिका लगातार 19 वर्षा से सरकार तक इसकी आवाज पहुँचा रही है। लेकिन बिहार सरकार पर जू नही रेग रही है। इधर गुंजन सिंह ने कहा कि हम नवादा का सांसद बनते है। तो यूवाओ को रोजगार देगें और उधोग लगायेगें और नवादा का चौमुखी विकास करेगें। उन्होने गाने के माध्यम से कहा कि जब हम आयेगें सरकार में बेरोजगारी मिटायेगें बिहार में। उन्होने सभी माताओ बहने एवं सभी बड़े बुजुर्गो का आर्शीवाद प्राप्त किया और कहा कि ये सूर्य मंदिर भारत का 12 सूर्यमंदिर मे एक अदभूत सूर्य मंदिर है। उन्होने सर्व प्रथम मंदिर का गर्वगृह गये और वृजभूषण के द्वारा उन्होने सूर्य मंदिर मे माथा टेका और जिले मे समृद्धि के लिए आर्शीवाद माँगी।

इधर छोटेलाल पाण्डेय ने मंदिर के इतिहास के बारे में देश के प्रसिद्ध सूर्य मन्दिर में ज्यादातर सूर्य मन्दिर बिहार में अवस्थित है। हण्डिया सूर्य मन्दिर सरोवर स्नान मात्र से मिली है कुष्ट रोग से मुक्तिभारत के बारह एवं बिहार के पाँच सूर्य मन्दिर में एक है हण्डिया सूर्य मन्दिर गया और नालन्दा जिले की सीमा पर हण्डिया यह राजगीर से 8 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ श्रद्धालुओं को कुष्ट रोग एवं पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। प्राचीन सूर्य मन्दिर द्वापर यूगीन माना जाता है। कि वंदती है कि कृष्ण के पुत्र शाम्व ने श्राप से मुक्ति के लिए बारह, सूर्य मन्दिर का निर्माण भारत वर्ष में कराया था। जिनमें बिहार में देव औरंगाबाद, बड़गॉव, ओगारी नालन्दा तथा हण्डिया नवादा जिले में है। उड़ीसा में कॉणार्क मन्दिर है। तथा अन्य 6 मन्दिर अलग-अलग

भारत के राज्य में है। जिले के नारदीगंज प्रखण्ड के हण्डिया सूर्य मन्दिर का उसी श्रृंखला की एक कड़ी माना जाता है। हण्डिया को द्वापर यूगीन सूर्य मन्दिर माना जाता है। मन्दिर और उसके आस-पास पुरातात्विक महत्व की कई चीजे है जो मन्दिर की गौरवशाली अतीत को बयां कर रही है। यहॉ सूर्य नारायण की दुलर्भ मूतिर्या प्राचीन सरोबर है। श्रद्धालु इसी सरोबर में स्नान कर पूजा अर्चना करते है। हण्डिया सूर्य मन्दिर कुष्ट से मुक्ति के लिए जाना जाता है। मान्यता है कि पाँच रविवार तालाब में स्नान करने से असाध्य कुष्ट रोग से भी लोगों को छुटकारा मिल जाता है। वैसे तो यहाँ सालो भर लोगों आते-जाते रहते है। खासकर रविवार के दिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते है। लेकिन छठ के अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुँचते है। दक्षिण बिहार के अलावे सीमावर्ती झारखण्ड, पश्चिम बंगाल, दिल्ली समेत पूरे भारत वर्ष के लोग पूजा अर्चना के लिए पहुँचते है। बताया जाता है कि आम दिनों में गैर हिन्दुवासी कुष्ट रोग मुक्ति के लिए तालाबों में स्नान के लिए पहुँचते है। यह सामाजिक सदभाव का मिशाल है। पंडित छोटे लाल पाण्डेय कहते है कि यह श्री कृष्ण का प्रभाव वाला ईलाका रहा है।

मगध सम्राट जरासंध का मुख्यालय राजगीर था। हण्डिया के आस-पास बड़गॉव समेत कई प्रमुख सूर्य मन्दिर है। जरासंध की पुत्री धनियावती भी राजगीर से हण्डिया आती थी। माना जाता है कि इन्होनें ही धनिया पहाड़ी पर अवस्थित शिव मन्दिर की स्थापना की एवं मगध क्षेत्र के सभी सूर्य मन्दिर के निर्माण करायी थी। वृहद्धय वंश ई पूर्व छठी शताब्दी में ही समाप्त हो चुका था। पुराणों में वृहद्धय वंश के 16 से 32 शाशंको का उल्लेख मिलता है एवं इनमें वंशजो का 750 वर्षो तक मगध पर शासन का उल्लेख इतिहासों में वर्णित है। जिला प्रशासन ने इस बार पुलिस बल एवं एक मजिस्टर्ड की तैनाती की थी। नवादा डीएम आयुतोष कुमार वर्मा ने छठ के दो दिन पूर्व हण्डिया छठ मेले का निरिक्षण का अधिनस्त अधिकारी को निर्देश दिया। डीएम के निर्देश पर प्रखण्ड विकास पदाधिकारी रंजीत कुमार अंचल अधिकारी अर्चना कुमारी एवं थानाध्यक्ष मुकेश कुमार के नेतृत्व में मेले की पुरी निगरानी ड्रोन कैमरे से की जा रही थी। वहीं महिला पुलिस यात्रियों की सुरक्षा के लिए तैनात थी। मंदिर के बाहर एवं अन्दर की महिला छठवती को पूरी सहयोग कर रही थी। मौके पर सुनील कुमार, संतोष कुमार, अरविन्द सिंह, रजनीस कुमार एवं आदित्य प्रताप समेत हजारो की संख्या में मौजूद थी।●